चिंतन

बांग्लादेश और श्रीलंका की राह पर चल रहा पाकिस्तान

पाकिस्तान भी श्रीलंका और बांग्लादेश की राह पर चलता नजर आ रहा है। बदहाली से तंग आ चुकी जनता सत्ता पर काबिज आकाओं को बदलने का मूड बना चुकी है। पहले से ही बदहाल आर्थिक हालात, आतंकवाद और शिया-सुन्नी मुस्लिम तनाव के बीच उलझे पड़ोसी पाकिस्तान में सत्ता के खिलाफ नागरिकों के आंदोलन ने नई मुसीबत खड़ी कर दी है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर रविवार को जो हुआ उसके संकेत कतई सही नहीं हैं। इमरान खान के सैकड़ों समर्थक इस्लामाबाद में डी चौक पर पहुंच गए। पुलिस उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागती रही। इसके जवाब में प्रदर्शनकारी पुलिस और सेना पर पत्थर फेंक रहे हैं। डी चौक इस्लामाबाद का सबसे हाई प्रोफाइल इलाका है। राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री ऑफिस, संसद भवन और सुप्रीम कोर्ट इसी इलाके में हैं। सेना ने शिपिंग कंटेनर रखकर राजधानी पहुंचने वाले हाईवे को ब्लॉक कर दिया था, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने लिफ्टिंग मशीन और कई भारी मशीनों की मदद से बैरिकेड्स तोड़ दिए। प्रदर्शनकारियों ने श्रीनगर हाईवे पर सुरक्षा बलों पर गाड़ियां चढ़ा दीं, जिसमें कुचलकर 4 सैनिक और 2 पुलिसकर्मी मारे गए। हिंसा में अब तक 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो चुके हैं। ज्यादातर की हालत गंभीर है। हिंसा से निपटने के लिए धारा 245 लागू कर दी गई है। प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया है। पाकिस्तानी सेना को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी भी इलाके में कर्फ्यू लगाने का अधिकार दिया गया है। असल में आम चुनाव के दौरान पाकिस्तान में जो हुआ, उससे जनता खासी नाराज है। उस पर जेल में बंद इमरान खान के बयान आग में घी का काम कर रहे हैं। इमरान खान ने इसे आजादी की लड़ाई के रूप में पेश किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, 24 नवंबर गुलामी से मुक्त होने का दिन है। देश को यह तय करना होगा कि बहादुर शाह जफर की तरह गुलामी का जुआ पहनना है या टीपू सुल्तान की तरह आजादी का ताज। इमरान खान की पोस्ट से स्पष्ट है कि उनकी जिद टीपू सुल्तान की तरह आजादी का ताज पहनने की है। आर्थिक बदहाली से दो चार हो रहे पाकिस्तान पर यह आंदोलन महंगा साबित हो रहा है। विपक्ष के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों और लॉकडाउन से प्रतिदिन भारतीय मुद्रा में लगभग 6,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हो रहा है। साथ ही कारोबार भी नहीं चल रहे हैं जिससे लोगों को आर्थिक हानि भी हो रही है। निर्यात करने में भी काफी परेशानी आ रही है। पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय के अनुसार आंदोलन के कारण हर दिन 144 बिलियन पाकिस्तानी रुपये का जीडीपी को, कृषि क्षेत्र में 20 बिलियन और औद्योगिक क्षेत्र में 26 बिलियन पाकिस्तानी रुपये का नुकसान हो चुका है। हालात ये हैं कि अभी आंदोलन और तेज हो रहा है। इस आंदोलन के दौरान पाकिस्तान में सर्वशक्तिमान सेना का भयावह मिथक सार्वजनिक रूप से ध्वस्त हो होता नजर आ रहा है। इसमें दरारें दो साल पहले तब दिखनी शुरू हो गई थी, जब हजारों पाकिस्तानियों ने एक अपदस्थ प्रधानमंत्री के साथ रैली निकाली, जिन्होंने राजनीति पर जनरलों की मजबूत पकड़ के ख़िलाफ़ आवाज उठाई थी। एक साल बाद, गुस्साई भीड़ ने सैन्य प्रतिष्ठानों पर धावा बोल दिया और उन्हें आग के हवाले कर दिया। अब जनता में सेना के प्रति गुस्सा दिख रहा है। हैरानी नहीं होगी अगर अगले कुछ दिनों में यह खबरें आए कि श्रीलंका और बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान में भी जनता ने सत्ता परिवर्तन कर दिया।

विश्लेषण

डॉ. अश्वनी महाजन

जी-20 सम्मेलन में 'वसुधैव कुटुम्बकम' के आधार पर 'एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य' के ध्येय वाक्य ने वैश्विक स्तर पर चल रहे विवादों, संघर्षों, समस्याओं, मुद्दों को जैसे एक सूत्र में पिरो दिया था। जी-20 सम्मेलन में ब्राजील के राष्ट्रपति ने सदस्य राष्ट्रों को अपने पर्यावरण लक्ष्यों को बढ़ाने का आह्वान किया। जी-20 हो या ब्रिक्स सम्मेलन, वैश्विक स्तर पर इनके बढ़ते महत्व को समझते हुए कूटनीति विशेषज्ञ इन्हें महत्वपूर्ण वैश्विक मंच मानने लगे हैं। युद्ध, आर्थिक चुनौतियों विभिन्न संघर्षों के समय में मंचों का उपयोग विश्व शांति, पर्यावरणीय, प्रौद्योगिकी से जुड़ी समस्याओं के हल के लिए इन मंचों का अधिकतम इस्तेमाल वक्त की मांग है।

चुनौतियों के हल का मंच बने जी-20

पिछले वर्ष भारत ने जी-20 समूह के अध्यक्ष के नाते जी-20 सम्मेलन आयोजित किया था। कई मायनों में यह सम्मेलन अभूतपूर्व था। खासतौर पर वैश्विक स्तर पर चल रहे विवादों, संघर्ष और युद्ध के वातावरण के बावजूद आम सहमति से घोषणा पत्र जारी किया गया। भारत से पूर्व इंडोनेशिया ने इसकी अध्यक्षता संभाली थी, लेकिन उस समय अंतिम घोषणा पत्र में रूस-यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में रूस की आलोचना की गई थी। जी-20 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट में अस्तित्व में आया था। भारत में जी-20 सम्मेलन बहुत धूमधाम से आयोजित किया गया। इसकी न सिर्फ भौतिक तैयारियां, बल्कि बौद्धिक तैयारियां भी पूरी गंभीरता से की गई थीं। 2023 के सम्मेलन में भारत द्वारा रूस के बारे में कुशलतापूर्वक न केवल विवादास्पद भाषा से बचा जा सका, बल्कि विश्व के समक्ष उपस्थित मुद्दों, खासतौर पर बहुपक्षीय विकास बैंकों समेत वैश्विक वित्तीय संस्थानों में पूंजीगत संरचना में बदलाव, क्रिप्टो करेंसी, वैश्विक ऋण संबंधी समस्याओं का प्रबंधन, मौसम परिवर्तन से जुड़े वित्तीयन के मुद्दे आदि, सभी पर खुली चर्चा का मार्ग भी प्रशस्त हुआ।

'वसुधैव कुटुम्बकम' के आधार पर 'एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य' के ध्येय वाक्य ने वैश्विक स्तर पर चल रहे विवादों, संघर्षों, समस्याओं, मुद्दों को जैसे एक सूत्र में पिरो दिया था। ब्राजील की राजधानी रियो में सम्पन्न जी-20 सम्मेलन में इन विषयों को आगे ले जाने की एक विशेष चुनौती थी, इसलिए ब्राजील के जी-20 सम्मेलन में हुई चर्चाओं और सहमतियों को उस आलोक में भी देखना महत्वपूर्ण है। रियो, ब्राजील में सम्पन्न सम्मेलन का थीम रहा 'एक न्यायपूर्ण विश्व और एक धारणीय ग्रह'। जी-20 सम्मेलन में ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिलवा ने कहा कि जी-20 सम्मेलन 2024, पिछले वर्ष की भारत की अध्यक्षता से प्रेरित रहा और भारत की सम्मेलन को आयोजित करने की कुशलता को प्राप्त करने की कोशिश इस सम्मेलन में की गई है। जी-20 सम्मेलन में ब्राजील के राष्ट्रपति ने सदस्य राष्ट्रों को अपने पर्यावरण लक्ष्यों को बढ़ाने का आह्वान किया। जी-20 सम्मेलन के घोषणा पत्र में पर्यावरण वित्तीयन पर गतिरोध खत्म करने की जरूरत पर बल दिया, लेकिन उसके समाधान के बारे में स्पष्ट मार्गदर्शन देने में यह घोषणा पत्र असफल रहा। समझना होगा कि पर्यावरण वित्तीयन पर यह गतिरोध लगातार बना हुआ है, जो न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग और मौसम परिवर्तन जैसे अत्यंत गंभीर मुद्दों पर विकसित देशों की असंवेदनशीलता भी दर्शाता है। हालांकि सम्मेलन का घोषणा पत्र यह कहता है कि पर्यावरणीय वित्त को सभी स्रोतों से अरबों से खरबों डॉलर तक तेजी से और पर्याप्त रूप से बढ़ाना जरूरी है, इसके बारे में ठोस रणनीति या संवेदनशीलता कहीं दिखाई नहीं देती। जी-20 सम्मेलन के पहले सत्र, जिसका मुद्दा 'भुखमरी और गरीबी के खिलाफ एकजुटता था', को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "भारत ने 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे। 55 करोड़ लोग फ्री हेल्थ बीमा का

लाभ उठा रहे। किसानों को 20 बिलियन डॉलर (168 हजार करोड़ रुपये) दिए। भारत वैश्विक खाद्य सुरक्षा में योगदान दे रहा है। हाल में ही मलावी, जाम्बिया और जिम्बाबे में मदद पहुंचाई है।"

प्रधानमंत्री के भाषण में पिछले सम्मेलन के थीम एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य का जिक्र आया और उन्होंने इसे इस सम्मेलन के लिए भी उतना ही प्रासंगिक बताया। यही नहीं उन्होंने जी-20 सम्मेलन अफ्रीकी यूनियन को शामिल करने की बात को भी रखा। समझना होगा कि यह जी-20 के लिए एक मील का पत्थर था। प्रधानमंत्री ने कहा कि युद्ध के कारण दुनिया में खाद्य, तेल और उर्वरक का संकट पैदा हुआ है और विकासशील राष्ट्रों (ग्लोबल साऊथ) पर इसका असर सबसे ज्यादा हुआ है। प्रधानमंत्री के भाषण में यह भी रेखांकित किया गया कि जी-20 की चर्चा तभी सफल होगी, जब हम ग्लोबल साऊथ की चुनौतियों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा जाएगा। यही नहीं जी-20 सम्मेलन 2024 में पर्यावरणीय वित्त पर कोई ठोस बात नहीं हो पाई। पर्यावरण के विषय से जुड़े लोग इस बात को लेकर भी चिंतित हैं कि जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करने संबंधी भी कोई बात घोषणा पत्र में नहीं आ पाई। गौरतलब है कि जीवाश्म ईंधन के उपयोग को समाप्त करने संबंधी मुद्दे पर विश्व में एक मत नहीं है। जहां भारत सरीखे देश इस बात पर जोर दे रहे हैं कि केवल कोयले के उपयोग को कम करने पर ही नहीं, बल्कि पेट्रोलियम तेल के उपयोग करने पर भी उतना ही बल दिया जाना चाहिए, लेकिन अमेरिका और अरब देशों समेत अधिकांश विकसित देश भी चतुराई से केवल कोयले के उपयोग को कम करने की वकालत कर रहे हैं। उधर दुबई में आयोजित कॉप-28 सम्मेलन में देशों ने जीवाश्म ईंधनों के उपयोग को कम करने पर सहमति दर्शाई थी, लेकिन पर्यावरण से जुड़े कार्यकर्ताओं को लगता है कि जी-20 घोषणा पत्र में जीवाश्म ईंधनों के उपयोग के बारे में बात नहीं आने से कॉप-29 यह मुद्दा और कमजोर हो जाएगा। किसी भी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का नेतृत्व केवल सम्मेलन तक सीमित नहीं रहता। सम्मेलन के साथ-साथ यह एक अवसर भी होता है कि अन्य मुल्कों के साथ महत्वपूर्ण मुददों पर बातचीत हो, कुछ अनसुलझे मुद्दे सुलझाए जाएं। इस मौके पर भारत के प्रधानमंत्री एवं प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने इस मौके का बखूबी इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केवल ब्राजील के राष्ट्रपति ही नहीं, बल्कि इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मैलोनी के साथ मिलकर प्रतिरक्षा, सुरक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी जैसे मुददों पर बातचीत की गई। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कीर स्टॉर्मर के साथ भी प्रौद्योगिकी, हरित ऊर्जा, सुरक्षा, नवाचार जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई। इसके अलावा फ्रांस, नार्वे, पुर्तगाल और इंडोनेशिया के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बातचीत हुई। एक अन्य दिलचस्प बात भारत और चीन की द्विपक्षीय वार्ता की हुई, जिसमें चीन के प्रदेश मंत्री के साथ भारत के विदेश मंत्री जयशंकर की बातचीत रही। भारत-चीन सीमा पर दो विवादास्पद ठिकानों पर सेनाओं के पीछे हटने के फैसले के बाद यह पहली बार हुआ कि चीन के साथ सीमा विवादों पर कोई सरकारी बातचीत हुई हो। समझा जा सकता है कि इससे भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंध बेहतर होंगे।

ऐसा लगता है कि पिछले सालों में जी 20 सम्मेलन का महत्व बढ़ता जा रहा है और विभिन्न देश इस सम्मेलन में शासनाध्यक्ष विभिन्न मुद्दों पर आम सहमति बनाने का कर रहे हैं। जी-20 हो या ब्रिक्स सम्मेलन, वैश्विक स्तर पर इनके बढ़ते महत्व को समझते हुए कूटनीति विशेषज्ञ इन्हें महत्वपूर्ण वैश्विक मंच मानने लगे हैं। युद्ध, आर्थिक चुनौतियों विभिन्न संघर्षों के समय में मंचों का उपयोग विश्व शांति, पर्यावरणीय, राजकोषीय चुनौतियों, प्रौद्योगिकी से जुड़ी समस्याओं के हल के लिए इन मंचों का अधिकतम इस्तेमाल वक्त की मांग है।

(लेखक डीयू के पूर्व प्रोफेसर हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं।

विश्व सहकारिता सम्मेलन

विवेक शुक्ला

सहकारिता आंदोलन को देती गति सरकार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राजधानी में अंतरराष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का शुभारंभ और स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाने का फैसला दुनियाभर के करोड़ों गरीबों व किसानों के लिए आशीर्वाद सिद्ध होगा। यह संयोग ही है कि हजारों साल से सामुदायिक जीवन जी रहा भारत अब जाकर तरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (आईसीए) के सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। 19 अगस्त 1895 को आईसीए का पहला सम्मेलन लंदन में हुआ था, तब इंग्लैंड, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, इंग्लैंड, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड के साथ भारत के सहकारी प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारत लगभग 128 साल बाद वैश्विक सहकारी सम्मेलन का नेतृत्व कर रहा है। यह तब और महत्वपूर्ण हो जाता है, जब संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित कर रखा है। बेशक, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी और सहकारिता मंत्री अमित शाह को श्रेय दिया जाना चाहिए, जिन्होंने भारत के सहकारी क्षेत्र का पुनरुत्थान कर दिया है। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को सशक्त बनाने, उन्हें डिजिटल इंडिया से जोड़ने, ई-गवर्नेंस लागू करने और समितियों को आसान वित्तीय सेवा प्रदान करके ग्रामीण भारत और किसानों की आर्थिक उन्नति में योगदान के जरिये समृद्ध भारत की कल्पना को साकार करने की दिशा में मोदी सरकार ने कदम आगे बढ़ाया है। यही नहीं भारत की सहकारी समितियां स्थायी कृषि में भी योगदान दे रही हैं साथ ही प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही हैं और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की खोज कर रही हैं। मोदी यह भी लक्ष्य कर रहे हैं कि किसानों की आय दोगुनी करने में सहकारिता क्षेत्र से सबसे ज्यादा योगदान लिया जाए। मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों का लक्ष्य रखा था, उसमें सहकारी क्षेत्र को आत्मनिर्भर एवं व्यापक बनाने का भी कार्यक्रम भी शामिल था। पिछले दिनों ही अमित शाह ने 2 लाख नए डेयरी एवं मत्स्य सहकारी समितियों के गठन की घोषणा के साथ श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ किया और यह दावा भी किया कि श्वेत क्रांति में महिलाओं की आत्मनिर्भरता एवं सशक्तिकरण के साथ कुपोषण के खिलाफ लड़ाई भी मजबूत होगी। दुग्ध उत्पादन में भारत को शीर्ष पर बनाये रखने के साथ अमित शाह इसे किसानों की आय का प्रमुख स्रोत बनाने में जुटे हैं। इस बीच एक बड़ी उपलब्धि यह हुई है की अब डेयरी से जुड़ी कोई भी मशीनरी विदेश से आयात करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। इसका 100 फीसदी उत्पादन भारत में ही होने लगा है। यही नहीं दो लाख प्राथमिक सहकारी समितियों के पंजीकृत हो जाने के बाद एक भी पंचायत ऐसी नहीं बचेगी जहां पैक्स, डेयरी या मत्स्य सहकारी समितियां नहीं होंगी। तो क्या मोदी सरकार अपने इस कार्यकाल में किसानों की आय वास्तव में दोगुनी करने में सफल होगी? इस समय देश के 29 प्रमुख क्षेत्रों में सहकारी संस्थाएं काम कर रही हैं, आठ लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं। गुजरात, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और असम जैसे राज्य में सबसे सहकारी संस्थाओं की संख्या ज्यादा है। इस समय भारतीय सहकारी क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़ा है। देश के लगभग 30 करोड़ से अधिक लोगों सहकारिता के सदस्य हैं। देश की 20 प्रतिशत से अधिक आबादी सीधे इससे लाभान्वित है। दुनिया की जिन 300 सबसे बड़ी सहकारी समितियों का टर्नओवर सबसे ज्यादा है, उनमें से 15 भारत की हैं। भारत का इफ्को 72वें स्थान पर, अमूल 90वें स्थान पर है। नई प्रौद्योगिकी के जरिये कामकाज में पारदर्शिता लाना और सहकारी समितियों की बाजार हिस्सेदारी में बढ़ोतरी के लिए आवश्यक वित्त की व्यवस्था करना बहुत आवश्यक है। 2024 के बजट में सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए एक व्यवस्थित और सर्वांगीण नीति की घोषणा की गई और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेज गति प्राप्त करने के लिए 1.54 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। मोदी सरकार नेसहकारी क्षेत्र के लिए कई सुधार और प्रोत्साहन की योजनाएं शुरू की है। जैसे 1 से 10 करोड़ रुपये की आय वाली सहकारी समितियों के लिए सरचार्ज 12 से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया। सहकारी समितियों के लिए एमएटी 18.5 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत किया गया ताकि सहकारी समितियों और कंपनियों के बीच समानता रहे। मोदी और शाह ने सहकारी समितियों के पारिस्थितिकी तंत्र को बदलने का जो अभियान शुरू किया है, उम्मीद की जानी चाहिए कि यह ग्रामीण भारत की तक़दीर बदलने में कामयाब होगा।

((लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

ज्ञान का अभिषेक

संकलित

दर्शन

अखिल ब्रह्मांड ईश्वर का स्वरूप है। श्रावण मास में बरस रही जलधारा ही ऐसी प्रतीत होती है मानो प्रकृति इस धरा का अभिषेक कर रही है। प्रकृति के इसी कृत्य का अनुकरण हम मानव भी करते हैं। श्रावण मास में हम भी शिवलिंग पर जल चढ़ा कर अपने आपको ईश्वर के उसी कृत्य के साथ जोड़ लेते हैं। ईश्वर अथवा प्रकृति के गुणों को अपनाना सदाचार है। श्रावण मास हमें यह अवसर देता है। जल जीवन है और यह धरती को पुनर्जीवित करता है। वर्षा से प्रकृति पनपती है। तपती हुई धरती पर जब वर्षा होती है तो उसे शीतलता का आभास होता है। वनस्पतियां उगने लगती हैं। पेड़ों पर नए पत्ते लगने लगते हैं। जैसे श्रावण में लोगों को गर्मी से राहत मिलती है, वैसे ही ज्ञान के श्रवण से मन को पीड़ा और बेचैनी से राहत मिलती है। श्रावण में लोग एकत्रित होकर ज्ञान-श्रवण करते हैं। दिव्य कथाएं सुनते हैं। ईश्वर का गुणगान करते हैं, जिससे उन्हें संतोष प्राप्त होता है। जब मन पर ज्ञान का अभिषेक होता है, तो मन शांत और शीतल हो जाता है। श्रावण को सबसे पवित्र महीना माना जाता है, क्योंकि यह अनेक पर्वों को अपने साथ लाता है। हिंदू कैलेंडर में श्रावण मास भगवान शिव को समर्पित है। शिव परिवर्तन के लिए उत्तरदायी ऊर्जा हैं। शिव पुरातन को विनष्ट कर नूतन के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। शिव कल्याणकारी हैं। शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। कैलाश का अर्थ ही है कि जहां केवल उत्सव हो, केवल आनंद हो।

ईश्वर ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है

संकलित

प्रेरणा

एक बार स्वामी विवेकानद अपने आश्रम में एक छोटे पालतू कुत्ते के साथ टहल रहे थे। तभी अचानक एक युवक उनके आश्रम में आया और उनके पैरों में झुक गया और कहने लगा- स्वामीजी मैं अपनी जिंदगी से बड़ा परेशान हूं। मैं प्रतिदिन पुरुषार्थ करता हूं, लेकिन आज तक सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। पता नहीं ईश्वर ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है, जो इतना पढ़ा-लिखा होने के बावजूद मैं नाकामयाब हूं। युवक की परेशानी को स्वामीजी ने तुरंत समझ लिया। उन्होंने युवक से कहा- भाई! थोड़ा मेरे इस कुत्ते को कहीं दूर तक सैर करा दो। उसके बाद मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। उनकी इस बात पर युवक को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन दोबारा उसने कोई प्रश्न नहीं किया और कुत्ते को दौड़ाते हुए आगे निकल पड़ा। कुत्ते को सैर कराने के बाद, जब वह युवक आश्रम में पहुंचा तो यह देखा कि युवक का चेहरा तेज है, लेकिन उसका छोटा कुत्ता थक के हांफ रहा था। स्वामीजी ने पूछा-भाई, मेरा कुत्ता इतना कैसे थक गया? तुम तो बड़े शांत दिख रहे हो। क्या तुम्हें थकावट नहीं हुई? युवक ने कहा-स्वामीजी, मैं धीरे-धीरे आराम से चल रहा था, लेकिन मेरा कुत्ता अशांत था। सभी जानवरों के पीछे दौड़ता था, इसीलिए बहुत थक गया था। तब विवेकानंद ने कहा-भाई, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तो यही है! तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे आसपास है, लेकिन तुम उससे दूर चलते हो। तुम जो चाहते हो वह दूर हो जाता है। युवक ने विवेकानंद के उत्तर से संतुष्ट होकर अपनी गलती को सुधारने का निर्णय लिया।

अंतर्मन

आज की पाती

संविधान का सम्मान जरूरी

26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। इसी उपलक्ष्य में 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान की मर्यादा का ख्याल रखना भावी पीढ़ी के उज्ज्वल भविष्य के लिए जरूरी है। लेकिन ऐसा करेगा कौन? राजनेताओं को कुर्सी का मोह है और आमजन को सरकारों से मुफ्त योजनाओं की सौगात चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो न तो देश की राजनीति दागदार होती, न देश में भ्रष्टाचार की जड़े गहरी होती, न ही देश में कोई गरीब बच्चा शिक्षा से वंचित रहता, न कोई गरीब महंगे इलाज के कारण दम तोड़ता और न ही कोई व्यक्ति दो वक्त की रोटी को तरसता। हर भारतीय नागरिक को संविधान का सम्मान करना चाहिए। - *विपिन साहू, खरसिया*

करंट अफेयर

चौरसिया के बांसुरी वादन से इजराइल वासी हुए मंत्रमुग्ध

इजराइल में भारतीय संगीत के प्रशंसकों के बीच लोकप्रिय संगीतज्ञ और ग्रैमी पुरस्कार विजेता बांसुरी वादक राकेश चौरसिया ने यहां 25वें अंतरराष्ट्रीय ऊड महोत्सव में अपनी स्वर लहरियों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। चौरसिया और तबला वादक पंडित कालीनाथ मिश्रा की जुगलबंदी ने संगीतप्रेमियों को बांधकर रखा। यह चौरसिया की इजराइल में चौथी प्रस्तुति थी। उनके चाचा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया विश्व विख्यात बांसुरी वादक है। राकेश चौरसिया ने कहा, 'मुझे यहां बार-बार आना पसंद है क्योंकि यहां श्रोता हमेशा गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। इस बार भी अच्छा अनुभव रहा।' दस दिवसीय उत्सव में ट्यूनीशियाई गायिका हबीबा मसिका को श्रद्धांजलि देना तथा 'ट्रैक्टर रिवेंज बैंड' और 'पियुट एन्सेम्बल' की जुगलबंदी भी शामिल है। भारतीय दूतावास में मिशन के उप प्रमुख राजीव बोडवाडे ने कहा, 'आज रात प्रतिष्ठित यरूशलम अंतरराष्ट्रीय ऊड उत्सव में दो बार के ग्रैमी पुरस्कार विजेता राकेश चौरसिया और पंडित कालीनाथ मिश्रा की प्रस्तुति भारत और इजराइल के बीच जारी सांस्कृतिक सहयोग में दीर्घकालिक योगदान देगी।'

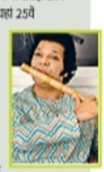

ऑफ बीट

कुछ शिशु इतने ज्यादा बालों के साथ क्यों पैदा होते हैं?

शिशु शरीर पर पतले, मुलायम, छोटे और हल्के रंग के बालों के साथ पैदा होते हैं, जिन्हें 'लानुगो' (गर्भरोम) कहते हैं। यह शब्द लैटिन शब्द 'लाना' से बना है जिसका मतलब 'ऊन' होता है। कुछ शिशुओं में बाल मुश्किल से दिखाई देते हैं। कुछ में, बहुत सारे बाल होते हैं, खासकर चेहरे, कंधों, पीठ और सिर के आसपास। हालांकि, किसी भी तरह से 'लानुगो' चिंता की बात नहीं है और जन्म के कुछ सप्ताह बाद यह अपने आप ही गायब हो जाते हैं। जन्म के समय कुछ शिशुओं के शरीर पर इतने ज्यादा बाल क्यों होते हैं? लानुगो गर्भावस्था के तीसरे महीने के आसपास भ्रूण पर दिखाई देता है। भ्रूण गर्भ में जैसे-जैसे विकसित होता है, सातवें महीने तक ये बाल घने होते जाते हैं। यह शिशु के शरीर के अधिकांश हिस्से को ढंक लेता है, सिवाय उन क्षेत्रों को छोड़कर जहां बाल नहीं होते। सभी बच्चे 'लानुगो' के साथ पैदा नहीं होते, लेकिन गर्भावस्था के दौरान गर्भ में पल रहे शिशु में ये गर्भरोम जरूर होते हैं। अधिकांश शिशुओं में ये गर्भावस्था के 33-36 सप्ताह के आसपास गर्भ में ही निकल जाते हैं, जहां ये एमनियोटिक द्रव के साथ मिल जाते हैं और गर्भस्थ शिशु इन्हें निगल लेते हैं। इसके बाद लानुगो उनके शरीर की प्रणाली से होकर गुजरता है।

ट्रेंड

विकास को बढ़ावा

बेहतर बुनियादी ढांचे का मतलब सपनों को जोड़ना और प्रगति को गति देना है। तीन प्रमुख रेल परियोजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी से महाराष्ट्र, एमपी और यूपी को फायदा होगा। यह मुंबई और प्रयागराज के बीच व्यस्त खंडों में विकास को बढ़ावा देगा।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

संविधान राष्ट्र की जीवनधारा

संविधान को अपनाने का 75वां वर्ष आज से शुरू हो गया है। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी भारतीयों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारे पूर्वजों द्वारा परिश्रमपूर्वक और सावधानीपूर्वक तैयार किया गया भारत का संविधान हमारे राष्ट्र की जीवनधारा है।

-मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस अध्यक्ष

सफल राजनीतिक स्टार्टअप

12 साल पहले, अरविन्द केजरीवाल ने नई तरह की राजनीति का सपना देखने का साहस किया- एक ऐसी राजनीति जो आम आदमी को केंद्र में रखे। आज, आम आदमी पार्टी भारत की सबसे सफल राजनीतिक स्टार्टअप के रूप में खड़ी है।

-राघव चड्ढा, आप नेता

अनुशासित रहने के कदम

अनुशासित रहने के कदम: स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें, एक दिनचर्या बनाएं, कार्यों को प्राथमिकता दें, सीमाएं निर्धारित करें, आत्म-जागरूकता पैदा करें, सचेतनता का अभ्यास करें, स्वस्थ आदतें स्थापित करें, खुद को जवाबदेह ठहराएं, समर्थन मांगें।

-हर्ष गोयनका, उद्योगपति

हमारा पता
हरिभूमि कार्यालय
नजदीक इंडस पब्लिक स्कूल, दिल्ली रोड, रोहतक-124001 फोन: 9253681019-20
ई-मेल : haribhoomi@gmail.com
वेब-साइट : www.haribhoomi.com

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

जब भी दुनिया को नेतृत्व व स्थायित्व देने की जरूरत हो, तब हमें यह कूटनीति के सहारे करना चाहिए। -केविन डि लियोन

बांग्लादेश में इस्कॉन से जुड़े धर्मगुरु की गिरफ्तारी को हसीना सरकार के पतन के बाद से ही अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों के आलोक में देखने की जरूरत है। छात्र आंदोलन के बहाने हुए राजनीतिक परिवर्तन के पीछे जिस तरह से कट्टरता का उदय हुआ है, उसे देखते हुए बांग्लादेश के बदलावों पर कड़ी नजर रखे जाने की जरूरत है।

कट्टरता की कड़ी

बांग्लादेश में इस्कॉन से जुड़े धर्मगुरु चिन्मय कृष्ण दास प्रभु के गिरफ्तार होने और इसका शांतिपूर्ण विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर हुए हमलों से यही जाहिर होता है कि वहां असहिष्णुता एक अलग स्तर पर पहुंच चुकी है। बांग्लादेश की स्थापना कहने को एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में हुई थी, लेकिन अस्सी के दशक में इसे एक इस्लामी राष्ट्र घोषित कर दिया गया। शेख हसीना ने 2011 में संविधान में धर्म निरपेक्षता को बहाल जरूर किया था, लेकिन इसको लेकर सरकार की प्रतिबद्धता हमेशा से सवालों के घेरे में रही है। तथ्य यह है कि 90 फीसदी से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले बांग्लादेश में वास्तविक अर्थों में धर्म निरपेक्षता तो कभी रही ही नहीं। जनवरी, 2013 से लेकर सितंबर, 2021 के बीच अल्पसंख्यक समुदायों पर साढ़े तीन हजार से भी ज्यादा हमले हुए, जिनमें तोड़फोड़, आगजनी और निशाना बनाकर की गई हिंसा शामिल है। लेकिन हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद से वहां अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने और धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ व आग लगाने की घटनाएं जिस तरह से बढ़ी हैं, वे बेहद चिंताजनक हैं। हाल ही में बांग्लादेश के शीर्ष विधि अधिकारी ने संविधान से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने की जो बात छेड़ी है, उससे वहां चल रहे खतरनाक रुझान को समझा जा सकता है। बेशक अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को बढ़ा-चढ़ा कर पेश करने की बात करें, लेकिन *ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल* की हालिया रिपोर्ट भी इसकी पुष्टि करती है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के शासन में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा बढ़ी है। रिपोर्ट यह खुलासा भी करती है कि हसीना सरकार के तख्तापलट वाले दिन यानी पांच अगस्त के बाद से बीस अगस्त के बीच ही अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के दो हजार से ज्यादा मामले सामने आए थे। रिपोर्ट तो अलबत्ता यह भी कहती है कि इन सभी मामलों में सरकार ने अपराधियों की पहचान करने और उन्हें दंड देने में न सिर्फ लापरवाही बरती, बल्कि ज्यादातर मामलों में कार्रवाइयां अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ ही कीं। संयुक्त राष्ट्र से लेकर डोनाल्ड ट्रंप तक के इस मामले में यूनुस सरकार से नाराजगी जताने के बावजूद अगर अल्पसंख्यकों पर हमले नहीं रुक रहे हैं, तो यह बांग्लादेश की ढीठता को भी दर्शाता है। अप्रत्यक्ष तौर पर फौज द्वारा नियंत्रित बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतें हमेशा से हावी रही हैं, ऐसे में फौज द्वारा ही गठित अंतरिम सरकार से ज्यादा उम्मीदें कैसे लगाई जा सकती हैं। छात्र आंदोलन के बहाने हुए राजनीतिक परिवर्तन के बाद जिस तरह से बांग्लादेश में कट्टरता बढ़ी है, उसे देखते हुए वहां के घटनाक्रमों पर गहरी नजर रखे जाने की जरूरत है।

ट्रंप के पास इतिहास रचने का मौका

ट्रंप बड़े सौदे करने में दिलचस्पी रखते हैं। अगर गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की अदला-बदली होती है, तो मुझे उम्मीद है कि वह इस पर चर्चा करने के लिए किसी का इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि इस लंबे और थकाऊ संघर्ष को रोकना अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण है।

क्या डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में दोबारा लौटने से इस्राइल और फलस्तीन पर दो राष्ट्र समाधान का अमेरिकी दबाव खत्म हो जाएगा? यह जरूरी नहीं है, क्योंकि यह इस पर निर्भर करता है कि व्हाइट हाउस में कौन-से डोनाल्ड ट्रंप बैठते हैं। क्या यह वह ट्रंप होंगे, जिन्होंने हाल ही में पश्चिमी तट पर इस्राइल कब्जे के समर्थक माइक हुकाबी को यरूशलम में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है? या वह ट्रंप होंगे, जिन्होंने अपने दामाद जेरेड कुशनर के साथ मिलकर बिल क्लिंटन के कार्यकाल के बाद दो-राष्ट्र समाधान के लिए विस्तृत योजना तैयार की थी?

थॉमस एल फ्रीडमैन
द न्यूयॉर्क टाइम्स

आपने सही पढ़ा-ट्रंप ऐसे दुर्लभ अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने इस्राइल और फलस्तीन के बीच सह-अस्तित्व के लिए विस्तृत योजना बनाई थी। अगर ट्रंप 2025 में उस पहल को पुनर्जीवित करते हैं, तो उन्हें एक ऐसे राष्ट्रपति के रूप में याद किया जा सकता है, जिसने इस्राइल को एक यहूदी लोकतंत्र के रूप में संरक्षित किया और साथ ही फलस्तीन को सुरक्षित राष्ट्र के रूप में जन्म लेने में मदद की। चार साल पहले जब मैंने उनसे बात की थी, तो उन्होंने अब्राहम समझौते का समर्थन करने के लिए धन्यवाद दिया था, जिसने इस्राइल और संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सूडान और मोरक्को के बीच ऐतिहासिक शांति का मार्ग प्रशस्त किया था।

ट्रंप के बारे में आप जो कहें, लेकिन वह बड़े सौदे करने में ही दिलचस्पी रखते हैं, जिनके गंभीर और यहां तक कि इतिहास को आकार देने वाले परिणाम हो सकते हैं। मैंने हाल ही में इस्राइल और यूएई में एक सप्ताह बिताया, जहां मैंने राजनेताओं, सैन्य और व्यापारिक नेताओं, यहूदियों, फलस्तीनियों व अरबों से बात की है कि ट्रंप इस बार उनके क्षेत्र में क्या कर सकते हैं। अगर ट्रंप सही तरीके से करना चाहें, तो ऐतिहासिक सौदे करने के लिए यहां बहुत सारे अवसर और इच्छाएं हैं। ट्रंप के पास एक शुरुआती बिंदु है : दो-राष्ट्र समाधान योजना, जिसे

उन्होंने जनवरी, 2020 में पेश किया था, जिसका शीर्षक था 'शांति से समृद्धि : फलस्तीनी और इस्राइली लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का दृष्टिकोण।' कोई भी पक्ष इसे उस रूप में स्वीकार नहीं करेगा, जैसा कि वर्तमान में लिखा गया है, और सात अक्तूबर, 2023 की घटना के बाद गाजा में होने वाला युद्ध किसी भी सौदे को बहुत जटिल बना देगा। लेकिन ट्रंप की योजना का 'दृष्टिकोण' गाजा के बाद इस्राइल-फलस्तीनी वार्ता के लिए एक शुरुआती बिंदु है, जिसे किसी राष्ट्रपति ने 24 साल पहले क्लिंटन द्वारा निर्धारित क्लिंटन मापदंडों के बाद से दो राष्ट्र बनाने के लिए सार्वजनिक रूप से पेश किया है।

इस योजना में इस्राइल को पश्चिमी तट के लगभग 30 प्रतिशत हिस्से पर कब्जा करने का अधिकार दिया गया था, जहां अधिकांश यहूदी बसते हैं, जबकि शेष हिस्सा पश्चिमी तट और गाजा में असैन्यीकृत फलस्तीनी राष्ट्र के लिए था। ट्रंप ने प्रस्ताव दिया कि गाजा का विस्तार इस्राइल के नेगेव रेगिस्तान की भूमि से किया जाएगा, ताकि फलस्तीनियों को पश्चिमी तट से छोड़े जाने वाले क्षेत्र के हिस्से के लिए मुआवजा दिया जा सके। और ट्रंप ने प्रस्ताव दिया कि गाजा और पश्चिमी तट को ऊपर की सड़कों और सुरंगों से जोड़ा जाए, लेकिन केवल तभी, जब हमास को गाजा में नेतृत्व से हटा दिया जाए, जैसा कि उन्होंने उस समय जोर दिया था। फलस्तीनी राजधानी यरूशलम के बाहरी इलाके में होगी। इस योजना में दोनों पक्षों से कहा गया कि एकमात्र स्थायी समाधान दो स्वदेशी लोगों के लिए दो राष्ट्रों का होना है, जिसमें भूमि विनिमय और पारस्परिक रूप से सहमत सुरक्षा व्यवस्था शामिल है, जिस पर वे बातचीत करेंगे। और नहीं भूलिए कि ट्रंप की 2020 की योजना पर कुछ महत्वपूर्ण छापें हैं।

प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रॉन डर्मर, जो तब अमेरिका में उनके राजदूत थे, ने उस समय इसे स्वीकार किया था, लेकिन नेतन्याहू ने इसे कभी औपचारिक रूप से अपने मंत्रिमंडल के सामने पेश नहीं किया। इसके बजाय, नेतन्याहू ने ट्रंप द्वारा इस्राइल के लिए निर्धारित क्षेत्र के कुछ हिस्सों को अपने में मिलाने की कोशिश की, लेकिन ट्रंप ने उन्हें रोक दिया। फिर यूएई ने दखल देते हुए कहा कि अगर नेतन्याहू पश्चिमी तट को एकतरफा ढंग से अपने में नहीं मिलाने का वादा करते हैं, तो वे इस्राइल के साथ रिश्तों को सामान्य कर देंगे। इस तरह से अब्राहम समझौते की शुरुआत हुई। लेकिन यह सिर्फ एक सांत्वना पुरस्कार था, बेशक मूल्यवान, लेकिन सदी का वह सौदा नहीं था, जिसकी ट्रंप आकांक्षा रखते थे। इसलिए अगर गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की अदला-बदली होती है, तो मुझे उम्मीद है कि ट्रंप इस दूसरे मौके का फायदा उठाने पर विचार करेंगे, जो इतिहास उन्हें दे रहा है, दोनों पक्षों को शांति शिखर सम्मेलन के लिए कैंप डेविड में आमंत्रित करके वह वहां से बातचीत शुरू कर सकते हैं।

इस पहल से दोनों पक्षों को यह पता चल जाएगा कि ट्रंप इस पर चर्चा करने के लिए उनकी राजनीति का इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि इस संघर्ष को रोकना अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण है, इससे पहले कि यह अमेरिका को कहीं ज्यादा इस युद्ध में घसीट ले। और हम जानते हैं कि ट्रंप को यह युद्ध पसंद नहीं है। अगर ट्रंप अपनी योजना को फिर से शुरू करते हैं, तो यह दुनिया को स्पष्ट कर देगा कि इस्राइल को अमेरिका से कोई कोरा चेक नहीं मिला है, जिससे वह बिना किसी विश्वसनीय योजना के गाजा में हमेशा के लिए लड़ सके।

यह संकेत देगा कि फलस्तीनियों को अपनी बातचीत एक साथ करने की जरूरत है, न कि केवल शिकायत करने की, और यह ईरान को संकेत देगा कि ट्रंप तेहरान को कूटनीतिक ढंग से सैन्य रूप से अलग-थलग करने का इरादा रखते हैं, जैसा कि उन्होंने अपनी योजना में कहा है, अगर वे इस्राइल से सुरक्षित शांतिपूर्ण रिश्ते बनाते हैं, तो 'फलस्तीनियों के आत्मनिर्णय की वैध इच्छा' को साकार करने में मदद मिलेगी। पिछले हफ्ते इस्राइल में, मैंने इस्राइली यहूदियों, इस्राइली अरबों और पश्चिमी तट के फलस्तीनियों से बातचीत में एक बात समान देखी कि ये सभी इस युद्ध से थक चुके हैं और दोनों पक्षों के सर्वश्रेष्ठ लोग देश छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। ट्रंप युद्ध खत्म करवा कर उन्हें आश्चर्यचकित कर सकते हैं। ©The New York Times 2024

जीवन धारा

लास्लो क्रस्नाहोरकाई

हर एक के भीतर कुछ न कुछ बोलता रहता है। उसे सुनें। यह कुछ ऐसा है कि हम किसी नदी के किनारे चुपचाप बैठ जाएं और उसकी आवाज को सुनें और यह भी देखें कि किस तरह से प्रकाश सतह पर फैलता है।

अपने भीतर के संगीत से जुड़ें

उन दिनों मैं तीस साल का था, जब मैंने पश्चिम की तरफ यात्रा की, यानी बर्लिन की तरफ। मैंने वहां अच्छा समय बिताया। मेरी दो किताबें इसी शहर से प्रभावित हैं। अक्सर कहा जाता है कि मेरे लेखन में जो वाक्य हैं, वे न तो वर्तमान के हैं और न ही अतीत के। ये सिर्फ साहित्यिक न होकर, एक दार्शनिक हैं। मैं बीस साल की उम्र से ही अपने दिमाग के भीतर ही काम करते आया हूं। कोई ऐसा लेखक नहीं है, जो अपनी लेखन मेज पर ही सोचता या लिखता है। यह कभी नहीं होता। यह कुछ ऐसा है कि कोई मेरे भीतर लगातार बोलता रहता है। और दुर्भाग्य से यह कोई अलंकार नहीं है। मैं अपने दिमाग में उस आवाज से जुड़ने की कोशिश करता हूं। अगर मैं अपने भीतर उस आवाज या संगीत को समझ पाता हूं और पीछा करता हूं, तो पंद्रह से बीस पृष्ठ तक लगातार लिखता जाता हूं।

मैं हमेशा उस आवाज के अधिक से अधिक करीब जाता हूं। वह आवाज मुझे कुछ अर्थपूर्ण संदेश देती है। मेरे भीतर की आवाज से बने पात्रों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। हमें लगता है कि इस दुनिया को कुछ दिखाना चाहिए, लेकिन असल में हमारा काम कुछ और है। यह कुछ ऐसा है कि हम किसी नदी के किनारे चुपचाप बैठ जाएं और उसकी आवाज को सुनें। नदी की सतह को देखें और यह भी देखें कि किस तरह से प्रकाश सतह पर फैलता है। इस दुनिया से जुड़े छोटे या बड़े निर्णय लेने से ज्यादा जरूरी ये काम हैं। खासतौर से, यह जरूरी है कि मैं अपनी पत्नी, अपने दोस्तों और अपने करीबी लोगों को समझने की कोशिश करूं। उस स्थिति में रहूं, जहां मैं उन सभी को कुछ दे पाऊं, जो कि मेरे तरफ से हो।

हम इस दुनिया के बारे में निर्णय तब लेते हैं, जब हम जवान होते हैं, लेकिन जिस उम्र में मैं हूं, उसमें एक ही काम हो सकता है कि मैं इस दुनिया को पूरी सहानुभूति के साथ देखूं। मनुष्यों के साथ होने वाले अनुभव कभी नहीं बदलते। जवानी, बुढ़ापा और फिर एक दिन मृत्यु। यह सब कुछ सदियों के बाद भी नहीं बदला है। ये सारी चीजें ज्यों की त्यों हैं। इसके अलावा एक और बात, हमेशा जिज्ञासु बने रहें। मैं बहुत जिज्ञासु हूं। मुझे लगता है कि जानने जैसा या समझने जैसा कुछ नहीं है। ये मेरा काम नहीं है। पूरा ब्रह्मांड एक रहस्य है। हर बड़े चिंतक ने हमें यह समझाने की कोशिश की है कि कुछ भी अस्तित्व में नहीं और न ही कोई अंतिम सत्य है। अगर आप किसी कार दुर्घटना के बारे में बात करें, तो किसी को यह बताना मुश्किल होगा कि किस तरह से कई सारी घटनाएं मिलकर उस घटना का कारण बनीं। अगर हम रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी एक घटना को ठीक से नहीं बता पाते, तो हम ब्रह्मांड से जुड़े सवालों के बारे में इतनी आसानी से कैसे सोच सकते हैं? अच्छा हो कि हम अपने दिन-प्रतिदिन के जीवन से शुरू करें।

चारों ओर देखें

सूत्र

ताजा हवा शरीर के लिए जितनी अच्छी है, उतनी ही मन के लिए भी। प्रकृति हमेशा हमसे बात करने की कोशिश करती दिखती है, जैसे कि उसे कोई बड़ा रहस्य बताना हो। पृथ्वी हमारी नहीं है, हम पृथ्वी के हैं। प्रकृति को समझने के लिए जंगल जाने की जरूरत नहीं, बल्कि हमारे आसपास का एक छोटा-सा पौधा ही आपको जीवन और प्रकृति के विषय में सब कुछ बता सकता है।

दूसरा पहलू

दिमागी मशीनें अब तकनीक की नई गति और सटीकता के साथ वैश्विक मौसम पैटर्न की भविष्यवाणी कर रही हैं।

नई तकनीक और मौसम का पूर्वानुमान

कुछ महीने पहले जैसे ही तूफान बेरिल कैरेबिया से गुजरा, तो शीर्ष यूरोपीय मौसम एजेंसी ने भूस्खलन की भविष्यवाणी की कि मेक्सिको में इसकी सबसे ज्यादा संभावना थी। यह चेतावनी विमानों, प्लवों और अंतरिक्ष यान द्वारा वैश्विक टिप्पणियों पर आधारित थी, जिसे कमरे के आकार के सुपर कंप्यूटरों ने पूर्वानुमान में बदल दिया। ठीक उसी दिन बहुत छोटे कंप्यूटर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सॉफ्टवेयर चलाने वाले विशेषज्ञों ने टेक्सास में भूस्खलन की भविष्यवाणी की। इस मशीन ने ग्रह के वातावरण से पूर्व में जो कुछ सीखा था, उससे ज्यादा उसे कुछ नहीं पता था। चार दिन बाद तूफान बेरिल टेक्सास में पूरी ताकत के साथ आया, सड़कों पर पानी भर गया, 36 लोगों की मौत हो गई और लाखों घरों की बिजली गुल हो गई। ह्यूस्टन में तेज हवाओं के कारण घरों पर पेड़ गिर गए, जिसमें कुछ लोगों की मौत भी हुई।

विलियम जे ब्रॉड

टेक्सास के संबंध में की गई भविष्यवाणी एआई की उभरती दुनिया की बानगी है। सुपर कंप्यूटर जो काम घंटों में करता है, एआई वह सेकंडों में कर देता है।

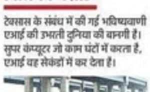

मौसम विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान की प्रोफेसर एमी मैकगवर्न, जो एआई मौसम संस्थान को निर्देशित करती हैं, ने कहा कि रैपिड एआई के मौसम को लेकर किए जाने वाले पूर्वानुमान वैज्ञानिक खोज में भी सहायक होंगे।

टेक्सास के संबंध में की गई भविष्यवाणी एआई की उभरती दुनिया की बानगी पेश करती है। यूरोपीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र के एआई विशेषज्ञ मैथ्यू चैंट्री ने कहा कि यह रोमांचक कदम है। वाशिंगटन विश्वविद्यालय में वायुमंडलीय विज्ञान के एमेरिटस प्रोफेसर क्रिस्टोफर एस ब्रेथरटन ने कहा, 'सामान्य तौर पर सुपरफास्ट एआई भावी खतरों को अच्छे से भांप सकते हैं। उनका कहना है कि भीषण गर्मी, हवाओं और बारिश को लेकर की जाने वाली चेतावनियां अभी की तुलना में और ज्यादा अद्यतन होंगी, जिससे कई जिंदगियों को बचाया जा सकेगा।'

ओक्लाहोमा विश्वविद्यालय में मौसम विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान की प्रोफेसर एमी मैकगवर्न, जो एआई मौसम संस्थान को निर्देशित करती हैं, ने कहा कि रैपिड एआई के मौसम को लेकर किए जाने वाले पूर्वानुमान वैज्ञानिक खोज में भी सहायक होंगे। डॉ. मैकगवर्न कहती हैं, 'यह हमें मूलभूत प्रक्रियाओं को तलाशने देता है और यह नई चीजों को खोजने में मूल्यवान उपकरण है।' महत्वपूर्ण बात यह है कि एआई मॉडल डेस्कटॉप कंप्यूटर पर चल सकते हैं, जिससे कमरे के आकार के सुपर कंप्यूटर की तुलना में तकनीक को अपनाना ज्यादा सरल बना देता है, जो अब वैश्विक पूर्वानुमान की दुनिया पर राज करते हैं। मैरीलैंड विश्वविद्यालय की शोध मौसम विज्ञानी मारिया मोलिना, जो एआई आधारित चरम मौसमी घटनाओं का अध्ययन करती हैं, कहती हैं कि यह एक निर्णायक मोड़ है। 'आपको पूर्वानुमान के लिए सुपर कंप्यूटर की जरूरत नहीं है। आप इसे अपने लैपटॉप से ही कर सकते हैं, जो विज्ञान को अधिक सुलभ बनाता है।' ©The New York Times 2024

आंकड़े

इलेक्ट्रॉनिक सामान

भारत इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के उत्पादन में काफी प्रगति कर रहा है। बीते छह वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक सामान के उत्पादन में 108 फीसदी की वृद्धि हुई है।

2018-19	4,58,006
2020-21	5,54,461
2021-22	6,40,810
2022-23	8,22,350
2023-24	9,52,000

आंकड़े इलेक्ट्रॉनिक सामान उत्पादों की कीमत के, करोड़ रुपये में | स्रोत : DGCI&S

मनुष्य प्रभु से क्या प्रतिज्ञा करके आया था और क्या करने में लग गया? इस बात की ओर ध्यान दिलाते हुए बीरू साहब ने प्रभु के प्रति प्रेम का संदेश दिया।

जीवन की ज्योति

बीरू साहब दिल्ली की संतशिखामणि श्रीबावरी साहिबा के शिष्य थे। बीरू साहब को विषयों से वैराग्य और प्रभुचरणों में अपार प्रेम-यही उनकी जीवन की ज्योति थी। बावरी साहिबा के परधाम गमन के बाद बीरू साहब उनके स्थान पर सत्संग करते-कराते रहे। मनुष्य प्रभु से क्या प्रतिज्ञा करके आया था और क्या करने में लग गया, इस बात की ओर ध्यान दिलाते हुए बीरू साहब लिखते हैं-

हंसा रे बाउल मोर याहि घरां, करबो मैं कवनि उपाय। मोतिया चुगन हंसा आयल हो, सो तो रहल भुलाय॥ झीलर को बगुला भयो है, कर्म कीट धरि खाय। सतगुरु सत्य दया कियो, भव बंधन ते लियो छुड़ाय॥ उनका कहने का मतलब यह है कि क्या उपाय करूं, मेरा हंस जो मोती चुगने के लिए आया था, बावली का बगुला होकर कर्म कीट को खा रहा है, अपना स्वरूप भूल गया है। यह सारा संसार अंधा होकर मोह-माया में लिपटा हुआ है। गुरुदेव की कृपा से मेरी आंखें खुलीं और भक्ति का प्रसाद पाया।

अंतर्यात्रा
संकलित

बीरू साहब आगे लिखते हैं, *आली रूप लागीलो आछे मने। हियरा मध्य मोहनि मूरति राखिलो यतने॥* कहते हैं कि हृदय के भीतर मोहिनी मूर्ति विराज रही है, इसे यत्न से रखो और वहां से फिसलने न दो। उसे देखो, उसका स्पर्श करो, हिलो-मिलो। वह कहते हैं कि जब मन स्थिर नहीं, तब मैं पापी, भगवान को कैसे भजूं। हद-अनहद को लांघकर अपने प्रियतम को पहचानो और उसके साथ हो जाइए।

अमर उजाला
पुराने पन्नों से — 08 जून, 1962

भारतीय वायुसेना मिग-जैट विमानों से सुसज्जित होगी

भारतीय वायुसेना शीघ्र ही मिग-जैट विमानों से सुसज्जित होगी
संसद की स्वीकृति रक्षामंत्रालय को मिली

लोकसभा द्वारा स्वीकृति दिए जाने के बाद भारत की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय रूस से मिग-जैट विमान खरीदने की तैयारी कर रहा है। संसद के इस निर्णय से ब्रिटेन और अमेरिका के कान खड़े हो गए हैं।

समावेशी विकास के लिए सहकारी आंदोलन जरूरी

नीतिगत पोषण से प्रेरित एक पुनर्जीवित सहकारी आंदोलन देश में अधिक समावेशी ग्रामीण आर्थिक समृद्धि का अग्रदूत हो सकता है।

शाजी केवी, अध्यक्ष, नाबार्ड

आर्थिकी

साझा आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए समावेशी विकास रणनीति 'सहकार से समृद्धि' के देश में अब तक काफी कारगर नतीजे सामने आए हैं। स्वतंत्रता से पहले के दौर में अगर हम भारत में सहकारिता आंदोलन की उत्पत्ति को देखें, तो पाएंगे कि इसकी शुरुआत किसानों की गरीबी कम करने की चुनौती से हुई थी, जिसका मुख्य कारण बार-बार पड़ने वाला सूखा और साहूकारों की सूदखोरी प्रवृत्ति था। एनएएफआईएस, 2021-22 के अनुसार ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थानों के माध्यम से केंद्र सरकार की निरंतर और लक्षित वित्तीय समावेशी पहलों के कारण, ग्रामीण परिवारों की साहूकारों और जमींदारों पर निर्भरता अब घटकर मात्र 4.2 प्रतिशत रह गई है।

भारत में सहकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने वाली प्रारंभिक शक्तियां भले ही अब कमजोर पड़ रही हों, लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए इस समय कई नई और जटिल उभरती चुनौतियां हैं, जिनके लिए सहकारी आंदोलन को नई दिशा और उस पर ध्यान देने की

आवश्यकता होगी। इन नई चुनौतियों में किसानों की आय बढ़ाने से लेकर एक कुशल ग्रामीण आपूर्ति शृंखला हासिल करना, स्थायी आधार पर खाद्य मुद्रास्फीति को कम करना, कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना, कृषि उत्पादकता तथा जलवायु परिवर्तन से निपटने वाले प्रयासों को बढ़ाना और डिजिटल क्षेत्र में अवसरों का लाभ उठाना शामिल है। सहकारी संस्थाओं के लिए मददगार नीतियां बनाने की दिशा में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 'सामाजिक विकास में सहकारी समितियों पर रिपोर्ट' (2023) से जानकारी प्राप्त करना उपयोगी हो सकता है, जो इस बात पर जोर देती है कि 'सहकारी समितियां बाजार संबंधी विफलताओं से निपटने, हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाने, रोजगार के अवसर बढ़ाकर सतत विकास को सहारा देकर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं'।

भारत के सहकारी क्षेत्र में दूध और चीनी के क्षेत्रों में मिली अपार सफलता केवल एकीकृत दृष्टिकोण के महत्व को ही प्रमाणित करती है। इसका एक और अन्य सफल उदाहरण भारत की सबसे पुरानी श्रमिक सहकारी संस्था-उरालुंगल लेबर कॉन्ट्रैक्ट को-ऑपरेटिव सोसाइटी का है, जो इस वर्ष अपनी स्थापना के 100 साल पूरे कर रही है। सहकारिता के दो खास पहलू हैं, जिनमें पहला है, 'सहकारी समितियों के बीच सहयोग' का महत्व। जब उरालुंगल को एक सड़क परियोजना हेतु लिए गए भारी कर्ज की किस्तें चुकानी थीं, तो उसने 38 प्राथमिक सहकारी समितियों का एक संघ बनाया और उनकी मदद से यह भारी राशि जुटा सकी; दूसरा, निजी फर्मों के विपरीत, संकट की स्थिति में एक श्रमिक सहकारी समिति द्वारा रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।

नाबार्ड सहकारी समितियों को एक-दूसरे के तुलनात्मक लाभों से लाभान्वित करने की सुविधा प्रदान कर इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए 'सहकारी समितियों के बीच सहयोग' को बढ़ावा दे रहा है। इस पहल में वित्तीय पक्ष से जुड़ा एक महत्वपूर्ण बिंदु-सहकारी समितियों और उनके सदस्यों के मौजूदा बैंक खातों को विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों में समेकित करना और उन्हें एक केंद्रीकृत जिला/राज्य सहकारी के तहत रखना होगा, जिससे सहकारी प्रणाली के संसाधन प्रणाली के भीतर ही बने रहेंगे।

भविष्य में कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में नीतिगत तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। हाल के वर्षों में टमाटर, आलू और प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण दुग्ध क्षेत्र की तर्ज पर इन तीनों वस्तुओं के लिए अधिक से अधिक किसान उत्पादक संगठनों का गठन और एक एकीकृत आपूर्ति शृंखला मदद कर सकती है। उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के पीढ़ी दर पीढ़ी बंटवारे को देखते हुए बागवानी फसलों की बिक्री से होने वाले लाभों के मद्देनजर विशेष रूप से बहु-राज्य सहकारी समितियों को उत्पादकों का एक व्यापक नेटवर्क बनाने की आवश्यकता हो सकती है। यह लागत को कम करने और उनकी मोलभाव करने की क्षमता में सुधार करने में मदद कर सकता है। भूमि स्वामित्व पर किसी भी जोखिम के बिना सहकारी समितियों द्वारा बड़े पैमाने पर भूमि पूलिंग जैसे क्षेत्रों पर ध्यान दे सकती है।

विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप प्रसंस्कृत उत्पाद एक मजबूत कृषि-निर्यात उत्पाद क्षेत्र बनाने में मदद करने, तकनीक अपनाने, अधिक पारदर्शिता के साथ व्यापार करने में आसानी; प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता निर्माण और उद्यमी कारोबारी तंत्र के विभिन्न हिस्सों के रूप में कृषि स्टार्टअप के साथ अंतर्संबंधों को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता होगी। सहकारी समितियों को नए उभरते नवप्रवर्तकों या नए कारोबारी विचारों की पहचान करने और उन्हें आगे बढ़ाने, वित्तीय और अतिरिक्त सहायताएं देने के लिए एक प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता भी हो सकती है। नीतिगत पोषण से प्रेरित एक पुनर्जीवित सहकारी आंदोलन देश में अधिक समावेशी ग्रामीण आर्थिक समृद्धि का अग्रदूत हो सकता है।

सम्पादकीय

जलवायु संकट और वैश्विक तापमान बढ़ाने में आगे रहे अब क्यों भाग रहे विकसित देश

इसमें कोई दो राय नहीं कि जलवायु संकट आज विश्व भर में सभी देशों की चिंता में सबसे ऊपर है और इसके खतरे को कम करने या इससे पूरी तरह निपटने के लिए सभी देशों को अपनी ईमानदार इच्छाशक्ति जाहिर करनी होगी। मगर इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि दिनोंदिन गहराते जा रहे इस संकट और इसके प्रभाव पर सभी देश विमर्श तो करते हैं, मगर इससे पार पाने के उपायों को लेकर वही देश अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं, जिनकी भूमिका इस मुश्किल को बढ़ाने में ज्यादा रही है। विकसित देशों का यह रुख अपने आप में परेशान करने वाला है कि वे पृथ्वी के जलवायु पर बढ़ते संकट के सवाल पर हर बार दोहरा रवैया अपनाते हैं और इस मसले पर होने वाली तमाम बैठकों का हासिल अपने किसी मकसद तक नहीं पहुंच पाता। इस बार अजरबैजान के बाकू में भी सीओपी-29 की बैठक में उम्मीद जरूर की गई थी कि शायद ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन की वजह से बढ़ते वैश्विक तापमान और उससे निपटने के उपायों को जमीन पर उतारने को लेकर विकसित देश वास्तव में कुछ ठोस पहल करेंगे।

गौरतलब है कि बाकू में संपन्न हुए जलवायु शिखर सम्मेलन में समृद्ध देशों ने जलवायु वित्त पोषण के रूप में हर वर्ष तीन सौ अरब डालर की सहायता देने पर समझौता किया, वह भी सन 2035 से। जबकि विकासशील देशों की मांग तेरह सौ अरब डालर की थी। यानी एक तरह से विकासशील देशों की मांगों को अनसुना कर दिया गया। विकसित देशों के रुख और सहायता राशि में इतने बड़े अंतर पर विकासशील देशों के बीच गहरी निराशा पैदा हुई और इस पर मतभेद उभरना स्वाभाविक था। भारत की ओर से यह साफ तौर पर कहा गया कि वह इस प्रस्ताव को वर्तमान स्वरूप में स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि प्रस्तावित राशि बहुत ही कम है और यह हमारे देश के अस्तित्व के लिए जरूरी जलवायु कार्रवाई को असंभव बनाएगी। भारत ने समझौते को अपनाने के तरीके को भी आपत्तिजनक और 'पूर्व नियोजित' बताया। समस्या के स्वरूप और उससे निपटने के उपायों के मद्देनजर भारत की आपत्ति को विकासशील देशों का समर्थन मिला, वहीं विकसित देशों के बीच एक विचित्र चुप्पी देखी गई। यह सही है कि ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन की वजह से वैश्विक तापमान में इजाफा हो रहा है और इसमें सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका दुनिया के समृद्ध या विकसित देश ही निभाते हैं। दूसरी ओर, 'ग्लोबल साउथ' के देशों की भूमिका में इसमें अपेक्षया कम है और विकास की निरंतरता को कायम रखने के लिए उनकी कुछ व्यावहारिक जरूरतें हैं। इसी के मद्देनजर विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से उपजने वाले संकट से पार पाने में मदद के लिए विकसित देशों का वित्तीय और तकनीकी संसाधन जुटाने का दायित्व है। इसी जिम्मेदारी के तहत विकसित देशों ने सन 2020 से हर वर्ष सौ अरब डालर जुटाने की पेशकश की थी। वह दावा कितना पूरा हुआ, यह सभी जानते हैं। मगर वक्त और जरूरत के मुताबिक तेरह सौ अरब डालर की मांग को सिर्फ तीन सौ अरब डालर तक समेट देने का औचित्य समझ से परे है।

पश्चिम बंगाल में ममता का जलवा कायम रखने के साथ कांग्रेस व भाजपा पर राजनैतिक हमले भी जारी

पश्चिम बंगाल के छह निर्वाचन क्षेत्रों- नैहाटी, हरोआ, मेदिनीपुर, तालडांगरा, सीताई (एससी), और मदारीहाट (एसटी) में उपचुनाव हुए थे। 2024 के लोकसभा चुनावों में जीत हासिल करने के बाद विधायकों द्वारा अपनी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के कारण ये सभी सीटें रिक्त हुई थीं। आरजी कर मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के बीच 13 नवंबर को हुए इन चुनावों को राजनीतिक रूप से तनावपूर्ण माहौल के बीच सत्तारूढ़ दल के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा के रूप में देखा जा रहा था। अनेक विरोधों के बावजूद, टीएमसी ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में विजयी हुई और 2024 के लोकसभा चुनावों में अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा।

अशोक भाटिया, मुंबई

तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल उपचुनाव में क्लीन स्वीप किया है उससे तो यही लगता है कि पश्चिम बंगाल में ममता का जलवा कायम है । टीएमसी ने अपनी पांच सीटें बरकरार रखीं और मदारीहाट सीट भाजपा से छीन लिया। इस जीत के साथ पश्चिम बंगाल में टीएमसी का राजनीतिक प्रभुत्व और मजबूत हो गया है। यहां तक कि आरजी कर की जघन्य घटना पर चल रहे विरोध प्रदर्शन भी मतदाताओं को प्रभावित करने में विफल रहे। छह में से पांच निर्वाचन क्षेत्र दक्षिण बंगाल में स्थित हैं, जो टीएमसी का गढ़ है, जबकि मदारीहाट उत्तर में है, जिसे भाजपा ने 2021 में जीता था। हरोआ में, जहां 70 प्रतिशत से अधिक मतदाता अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, भाजपा तीसरे स्थान पर रही और अपनी जमानत बचाने में विफल रही, जिसके बाद पार्टी नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा, अल्पसंख्यक भाजपा को वोट नहीं देते। सीपीआई (एम) के नेतृत्व वाले वाम मोर्चा ने खुद को राज्य में पुनर्जीवित करने के लिए आरजी कर विरोध प्रदर्शनों को भुनाने की कोशिश की थी। लेकिन लेफ्ट को करारी हार का सामना करना पड़ा। सीताई, तालडांगरा, मेदिनीपुर और मदारीहाट में वाम मोर्चे ने अपनी जमानत गंवा दी। वाम मोर्चे में शामिल सीपीआई (एमएल) की नैहाटी में जमानत जब्त हो गई, जबकि ऑल इंडिया सेक्युलर फ्रंट को हरोआ में जमानत गंवानी पड़ी। कांग्रेस ने 2021 के बाद पहली बार वाम दलों के साथ गठबंधन के बिना चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे सभी छह निर्वाचन क्षेत्रों में जमानत गंवानी पड़ी। सीताई (एससी) में, टीएमसी की संगीता रॉय ने भाजपा के दीपक कुमार रे पर 1,30,636 के अंतर से जीत हासिल की, जिन्हें केवल 35,348 वोट मिले। टीएमसी का वोट शेयर 2021 के राज्य चुनावों में 49 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर 76 प्रतिशत हो गया, जबकि भाजपा का वोट शेयर 45 प्रतिशत से गिरकर सिर्फ 16 प्रतिशत रह गया। मदारीहाट (एसटी) सीट, जो पहले भाजपा के पास थी, वहां टीएमसी ने जीत दर्ज की। सत्तारूढ़ दल के जयप्रकाश टोप्पो ने 79,186 वोटों प्राप्त किए और बीजेपी के राहुल लोहार को 28,168 वोटों के अंतर से मात दी। यह जीत टीएमसी के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि यह पहली बार है जब पार्टी ने चाय बागान बेल्ट की एक प्रमुख सीट मदारीहाट पर कब्जा कर लिया है। उम्मीदवार के चयन को लेकर भाजपा के अलीपुरद्वार सांसद मनोज तिग्गा और पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉन बारला के बीच मतभेद के कारण पार्टी को यह सीट गंवानी पड़ी। मदारीहाट में टीएमसी का वोट शेयर 2021 की तुलना में 34.13 फीसदी से बढ़कर 54.05 फीसदी हो गया, जबकि बीजेपी का वोट शेयर गिरकर 34 फीसदी हो गया। नैहाटी में टीएमसी के सनत डे ने 78,772 वोटों प्राप्त किए। उन्होंने बीजेपी के रूपक मित्रा को 49,277 वोटों से हराया। टीएमसी का वोट शेयर 2021 में 50 फीसदी से बढ़कर 62.97 फीसदी हो गया, जबकि बीजेपी का वोट शेयर 2021 में 38 फीसदी से गिरकर 23.58 फीसदी हो गया। हरोआ में, टीएमसी के एसके रबीउल इस्लाम ने 1,57,072 वोट प्राप्त किए। उन्होंने आईएसएफ के पियारुल इस्लाम पर 1,31,388 वोटों के भारी अंतर से जीत दर्ज की। पियारुल इस्लाम को सिर्फ 25,684 वोट मिले। यह परिणाम दक्षिण बंगाल में अल्पसंख्यकों के बीच टीएमसी के प्रभुत्व को रेखांकित करता है।

टीएमसी का वोट शेयर बढ़कर 76.63 फीसदी हो गया, जबकि आईएसएफ सिर्फ 12.53 फीसदी ही हासिल कर पाई, जबकि 2021 में टीएमसी का वोट शेयर 57.34 फीसदी था। मेदिनीपुर में, टीएमसी के सुजॉय हाजरा ने 115,104 वोट हासिल किए और बीजेपी के सुभाजीत रॉय को 33,996 वोटों के अंतर से हराया। बीजेपी प्रत्याशी को 81,108 वोट मिले। बीजेपी के 37.67 फीसदी की तुलना में टीएमसी का वोट शेयर मेदिनीपुर में 53..43 फीसदी तक पहुंच गया। साल 2021 के विधानसभा चुनाव में इस आदिवासी बहुल सीट पर टीएमसी का वोट शेयर 50.72 फीसदी और बीजेपी का 40.51 फीसदी था। तलडांगरा में, टीएमसी की फाल्गुनी सिंहबाबू ने 98,926 वोट प्राप्त किए और बीजेपी की अनन्या रॉय चक्रवर्ती को 34,082 वोटों के अंतर से हराया। टीएमसी ने अपना वोट शेयर 2021 में 46 फीसदी से बढ़ाकर 52 फीसदी कर लिया, जबकि बीजेपी का वोट शेयर 39.19 फीसदी से गिरकर 34 फीसदी हो गया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने राज्य के लोगों को उनके निरंतर समर्थन के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा, मैं अपने दिल की गहराइयों से मां, माटी और मानुष को धन्यवाद और बधाई देना चाहती हूं। आपका आशीर्वाद हमें आने वाले दिनों में लोगों के लिए काम करने में मदद करेगा। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने सभी छह टीएमसी उम्मीदवारों को उनकी निर्णायक जीत के लिए बधाई दी। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल की जनता ने जमींदारों, मीडिया और कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक वर्ग द्वारा अपने निहित स्वार्थों के लिए राज्य को बदनाम करने के लिए बनाए गए नैरेटिव को खारिज कर दिया। उन्होंने मदारीहाट की जनता को भी विशेष धन्यवाद दिया। अभिषेक बनर्जी ने कहा, मैं बांग्ला विरोधियों, उनके फर्जी नैरेटिव को लोकतांत्रिक तरीके से खत्म करने और हम पर अपना भरोसा जताने के लिए पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने शीश झुकाता हूं। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर की बलात्कार-हत्या के मामले को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के कारण तृणमूल कांग्रेस दबाव में थी। लेकिन उपचुनावों के परिणामों से साफ है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस तूफान से पार पा लिया है। इससे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पकड़ और भी मजबूत हो गई है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के विरोध प्रदर्शनों के बीच ये चुनाव राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी के लिए अग्नि परीक्षा सरीखे माने जा रहे थे। इसका मतलब यह है कि आरजी कर घटना के बाद राज्य सरकार के खिलाफ नकारात्मक अभियान के बावजूद पश्चिम बंगाल के लोगों ने ममता बनर्जी के नेतृत्व में अपना विश्वास बनाए रखा है। बीजेपी के लिए इस बार भी कई कारक अनुकूल नहीं रहे। लोकसभा चुनाव में भी उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। 2024 में उसकी सीटें घटकर 12 हो गईं, जबकि 2019 में उसने 18 सीटें जीती थीं। उस समय भी बीजेपी की चुनावी रणनीति, संगठनात्मक ढांचे और नैरेटिव पर कई सवाल उठे थे। इसके अलावा बीजेपी की केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भरता, मुस्लिम विरोधी बयानबाजी और नागरिकता संशोधन अधिनियम को समर्थन न मिलना भी नुकसानदायक साबित हुआ। इसके विपरीत ममता बनर्जी ने खुद को बंगाल के हितों की रक्षक के रूप में पेश किया। उनका यह अवतार भ्रष्टाचार और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में फेल रहने के आरोपों के बावजूद मतदाताओं के साथ जुड़ गया। कमाल की बात यह है कि पश्चिम बंगाल में भगवा फहराने का सपना देख रही बीजेपी ममता की काट निकालने में असफल रही।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने उपचुनाव के नतीजों को महत्व नहीं दिया। उन्होंने कहा, उपचुनाव के नतीजे एक विश्वसनीय संकेतक के रूप में काम नहीं कर सकते। लोग टीएमसी के साथ हैं या उनके खिलाफ, यह आगामी विधानसभा चुनाव में दिखाई देगा। 2021 के विधानसभा चुनावों के बाद से, टीएमसी ने मार्च 2023 में सागरदिघी उपचुनाव को छोड़कर हर उपचुनाव में जीत हासिल की है। सागरदिघी में कांग्रेस के एक उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी, जो बाद में टीएमसी में शामिल हो गया था। इस जीत के साथ, 294 सदस्यीय राज्य विधानसभा में टीएमसी की संख्या बढ़कर 216 हो गई है, जिससे उसकी स्थिति और मजबूत हो गई है। वहीं भाजपा की संख्या 77 से घटकर 69 हो गई है। उधर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बुरी हार के बाद टीएमसी ने उसके नेतृत्व पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए है।

आज का राशिफल

मेष
सरकारी काम में सफलता या लाभ मिलेगा। संतान के पीछे पैसे खर्च होंगे। कलाकारों एवं खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा दर्शाने के लिए उत्तम समय है। दिन की शुरुआत से ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव करेंगे।

वृष
किसी भी नए काम की शुरुआत आज न करें। किसी बात को लेकर मन में ग्लानि का भाव रहेगा। परिजनों के साथ वाद-विवाद न करें। दोपहर के बाद आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति में सुधार की संभावना है।

मिथुन
व्यापार में लाभ मिल सकता है। पिता से भी आर्थिक लाभ की संभावना दिख रही है। आज किसी प्रिय पात्र और मित्रों के साथ बाहर जाने का कार्यक्रम बनेगा। मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। व्यापार में भी आपको लाभ होगा।

कर्क
आज सुबह आपका मन क्रोधित रहेगा। शारीरिक रूप से अस्वस्थ और मानसिक रूप से चिंता का अनुभव होगा। विद्यार्थियों को अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे। दोपहर के बाद किसी प्रिय मित्र से मुलाकात हो सकती है। भागीदारी से लाभ होगा। क्रोध पर नियंत्रण रखें।

सिंह
प्रिय पात्र और मित्रों के साथ मुलाकात होगी। पर्यटन का आयोजन हो सकता है। शादी योग्य युवक-युवतियों का रिश्ता पक्का हो सकता है। आज का दिन आपके लिए शुभ है। नौकरीपेशा लोगों का टारगेट पूरा हो सकेगा।

कन्या
आज आपको विविध क्षेत्रों से लाभ होने होने की संभावना है। व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ होगा। साथी कर्मचारियों का पूरा सहयोग मिलेगा। क्रोध में किसी के साथ विवाद की आशंका बनी रहेगी। स्वास्थ्य नरम-गरम रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

तुला
आज आपको हर काम में सफलता मिलेगी। विरोधियों पर आप विजय प्राप्त कर सकेंगे। सामाजिक दृष्टि से आपको मान-सम्मान मिलेगा। आपकी एनर्जी कम हो जाएगी। आलस्य का वातावरण छाया रहेगा। विवाद में मानहानि हो सकती है।

वृश्चिक
आपकी कोई चिंता दूर हो सकती है। स्नेहीजन और मित्रों से मुलाकात सुखद रहेगी। हालांकि आप वाणी पर संयम रखें। शाम में किसी तरह के नकारात्मक विचार आपको परेशान कर सकते हैं। गुस्से पर संयम रखें।

धनु
आर्थिक लाभ भी होगा। भाई-बंधुओं के साथ प्रेम बढ़ेगा। भाग्यवृद्धि के अवसर मिलेंगे। काम की सफलता से आपका उत्साह बढ़ेगा। आज का आपका दिन खुशी और आनंद के साथ गुजरेगा। आप कुछ अधिक ही संवेदनशील रहेंगे।

मकर
पारिवारिक कठिनाइयां भी कम होंगी। किसी धार्मिक स्थल की यात्रा हो सकती है। ईश्वर का नाम स्मरण और आध्यात्मिकता आपके मन को शांति प्रदान करेंगे। मनोरंजक एक्टिविटी में आपका मन लगेगा।

कुंभ
परिजनों के साथ वाद-विवाद होने से मन चिंता से भरा रहेगा। छाती में दर्द या अन्य कोई शारीरिक परेशानी होने से शरीर शिथिल रहेगा। निरर्थक आर्थिक खर्च से बचें। किसी तरह की यात्रा का कार्यक्रम हो, तो आज टालना उचित रहेगा।

मीन
आज वाणी में संयम रखें। स्नेहीजनों के साथ किसी बात पर विवाद हो सकता है। आय की अपेक्षा व्यय अधिक रहेगा। किसी कन्फ्यूजन में दिन गुजरेगा। आप नए काम की शुरुआत कर सकेंगे। स्नेहीजनों के साथ मुलाकात होगी। सुखद यात्रा का संयोग बनेगा।

शख्सियत

बढ़ता राजस्थान

श्री आलोक गुप्ता
(भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी)

नमस्कार साथियों हमारी आज की शख्सियत कॉलम के स्टार हैं हमारे अलवर के गौरव और इस समय राजस्थान में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी के रूप में मुख्यमंत्री को अपनी सेवा देने वाले श्री आलोक गुप्ता। 1 अक्टूबर सन 1971 को अलवर में जन्में आलोक गुप्ता शुरू से ही कुछ कर गुजरने का जज्बा लेकर अपने साथ चले। इनके पिता डॉ.के.के.गुप्ता जोकि एक बड़े हस्ताक्षर के रूप में जाने जाते हैं। विश्व हिन्दू परिषद के स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। एज्यूकेशन के रूप में उन्होंने एम.टेक(संचार एवं रडार) बी.टेक(इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग) के रूप में कर भारतीय प्रशासनिक सेवा में आ गए।

आज प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार जयपुर जैसी बड़े पद का निर्वहन कर रहे हैं। इससे पूर्व ये प्रमुख शासन सचिव, उर्जा विभाग राजस्थान जयपुर। प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय जन अभियोग निराकरण मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग एवं जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान जयपुर। प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग,राजस्थान जयपुर। प्रमुख शासन सचिव, पर्यटन एवं देवस्थान विभाग राजस्थान जयपुर। शासन सचिव, देवस्थान विभाग जयपुर। आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग राजस्थान, जयपुर। शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान जयपुर। आयुक्त श्रम विभाग राजस्थान, जयपुर। आयुक्त, सीएडी बीकानेर। आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा एवं पदेन राज्य परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, बीकानेर। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा एवं पदेन राज्य परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, बीकानेर। रजिस्ट्रार, राजस्व बोर्ड राजस्थान, अजमेर। कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू। निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर। प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड, उदयपुर। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर। सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। उप शासन सचिव योजना विभाग, राजस्थान जयपुर। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर। उप शासन सचिव, कार्मिक विभाग ए-1 राजस्थान, जयपुर। अतिरिक्त कलक्टर विकास एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद एवं पदेन परियोजना निदेशक, डीआरडीए बांसवाड़ा। उपखण्ड अधिकारी, बाली पाली। उपखण्ड अधिकारी, जयपुर पूर्व। एलबीएसएन मसूरी में दूसरे चरण के प्रशिक्षण के तहत। जोधपुर में जिला प्रशिक्षण के तहत। इसके अतिरिक्त इन पदों को अतिरिक्त प्रभार के रूप में भी संभाला:- अध्यक्ष राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर। प्रमुख शासन सचिव, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान, जयपुर। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर। अध्यक्ष, राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, राजस्थान जयपुर। आयुक्त, पर्यटन विभाग राजस्थान, जयपुर। अध्यक्ष, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, राजस्थान जयपुर। प्रमुख शासन सचिव, राजस्व, उपनिवेशन, सैनिक कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर। निदेशक एचसीएम रिपा एवं पदेन सचिव, राजस्थान सरकार जयपुर पद पर रहे। बहुत ही गौरव का विषय है कि इनका जन्म अलवर में हुआ और अलवर के लाल ने बड़े पदों पर रहकर जनसेवा के माध्यम से अलवर का गौरव ओर भी बढ़ाया है। दैनिक बढ़ता राजस्थान की टीम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है।

रूपक शर्मा

आज का इतिहास

27 नवंबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

- पोप अर्बन द्वितीय ने 1095 में पहले क्रूसेड (धर्मयुद्ध) का उपदेश दिया।
- सन 1795 में पहले बांग्ला नाटक का मंचन हुआ।
- पुर्तगाल के शाही परिवार ने 1807 में नेपोलियन की सेना के भय से लिस्बन छोड़ा।
- पोलैंड साम्राज्य ने 1815 में संविधान अपनाया।
- पेरिस में पुलिस ने 1947 में कम्युनिस्ट समाचार-पत्र के कार्यालय पर कब्जा कर लिया।
- जबलपुर के निवासियों ने 1949 में चंदा इकट्ठा करके नगरपालिका प्रांगण में सुभद्रा कुमारी चौहान जी की आदमकद प्रतिमा लगवाई जिसका अनावरण कवयित्री और उनकी बचपन की सहेली महादेवी वर्मा ने किया।
- अमरीका के विख्यात ड्रामा लेखक यूजीन ओ नील का 1953 में की आयु में निधन हुआ।
- उरुग्वे ने 1966 में संविधान अपनाया।
- फ्रांस के राष्ट्रपति चार्ल्स डी गॉल ने 1967 में फिर दोहराया कि वह ब्रिटेन की सामूहिक बाजार की कोशिशों का विरोध करेंगे।
- गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के सह-संस्थापक रॉस मैक्विर्टर की 1975 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
- मिस वेनेजुएला जैकेलीन एग्वीलेरा मार्कानो 'मिस वर्ल्ड' 1995 चुनी गईं।
- पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने 2007 में अपने सैनिक साथियों से विदाई ली।
- छठा वेतन आयोग देने वाला उत्तर प्रदेश 2008 में देश का पहला राज्य बना।

27 नवंबर को जन्मे व्यक्ति

- भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार एवं पुरातत्व के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान काशी प्रसाद जायसवाल का 1881 में जन्म हुआ।
- प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर का 1888 में जन्म हुआ।
- प्रसिद्ध कवि और लेखक हरिवंश राय बच्चन का 1907 में जन्म हुआ।

विशेष आलेख

साइबर अपराध की नई राह 'डिजिटल अरेस्ट'

लोगों की पसीने की कमाई को लूट रहे ठग डिजिटल तकनीक तकनीकी वर्तमान में समय में वरदान के साथ-साथ अभिशाप भी बनती जा रही है, जिसका प्रभाव लोगों को वर्तमान समय में दिखने लगा है। जब तक कोई तकनीक लोगों के हितों में कार्य करें तब तक ही उसे ठीक माना जा सकता हैं, लेकिन उसी तकनीक से लोगों को काफी ज्यादा नुकसान होने लगे तो वह अभिशाप बन जाती है। इससे जुड़ी चिंता भी काफी बड़ी हो जाती है। जैसा कि उपनिदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में वरिष्ठ सहायक पद पर कार्यरत किरोड़ी लाल मीणा एक शोध में बताते हैं कि वर्तमान समय में देश के लिए 'डिजिटल अरेस्ट' एक ऐसा ही संकट है। जिससे देश की जनता अधिक सतर्क और जागरूक रह कर ही इस खतरे का मुकाबला कर सकती है। वर्तमान समय में साइबर धोखाधड़ी रोकने में संसाधनों की कमी आम लोग जागरूकता के अभाव में इस साइबर फर्जीवाड़ा करने वालों की चाल में फंस जाते हैं।

डिजिटल के चक्कर में मेहनत की कमाई लूट रही हैं : वर्तमान समय में देश में डिजिटल भुगतान व्यवस्था ने लोगों के लेनदेन को आसान और सुविधाजन बनाने में बेहतरीन योगदान दिया है। नगद लेनदेन की जगह डिजिटल भुगतान व्यवस्था से लोगों में भुगतान करने का तरीका तो आसान हुआ है वहीं दूसरी ओर जबसे देश में डिजिटल डिजिटल भुगतान की व्यवस्था बनी है और लोगों का उसमें रुझान भी बहुत जल्दी बढ़ा है वहीं साइबर ठगों ने इस रास्ते को ही आम जनता को ठगने के लिए अपनाया हैं। सरकार और उसकी एजेंसियां साइबर ठगी से लोगों को बचाने के जो इंतजाम करती हैं, साइबर ठग जल्द ही दूसरी किस्म की धोखाधड़ी करने का रास्ता निकाल लेते है। सरकार और ऐजेन्सीयों द्वारा आम जनता को अपील की जाती है कि मोबाइल से बैंकिंग लेनदेन के वक्त पिन, पासवर्ड, ओटीपी किसी से साझा न करें इस पर साइबर ठग कोई विश्वसनीय दिखने वाला लिंक भेज कर लोगों के फोन ही हैक कर लेते हैं। ऐसे में सारे पिन और ओटीपी ठगों के वांछित फोन पर जाने लगते हैं और देखते ही देखते लोगों के बैंक खातों में जिंदगी भर की जमा पूंजी चली जाती है। सरकार एवं ऐजेन्सीयां इस पर लगाम लगाती, इससे पहले 'डिजिटल अरेस्ट' के रूप में की जाने वाली लूट सामने आने लगी।

डिजिटल अरेस्ट क्या है : आखिर 'डिजिटल अरेस्ट' में साइबर ठग असली पुलिस या जांच एजेंसियों के वास्तविक अधिकारियों के वेश में लोगों को गिरफ्तारी का डर दिखा कर पैसे ऐंठने का प्रयास करते हैं। इसमें किसी शख्स को मोबाइल फोन पर वीडियो या सामान्य कॉल करते हुए गिरफ्तारी या सीबीआई अथवा आयकर जांच का भय दिखाया जाता है। एक बार जब कोई व्यक्ति इनके जाल में फंस जाता है, तो वह इनके आगे खुद को असहाय महसूस करने लगता है। तब ये साइबर ठग उस व्यक्ति को अपनी सारी जमा-पूंजी बताए गए बैंक खातों में खुद ही भेजने को मजबूर कर देते हैं।

ठग इस तरह फंसाते है लोगों को : अधिकतर 'डिजिटल अरेस्ट' वाले मामलों कूरियर कंपनी के झांसों, इनमें लोगों के बेटे या बेटी के किसी मामले में फंसे होने, यौन शोषण के आरोपी होने, किसी आर्थिक धोखाधड़ी में शामिल होने जैसे तमाम मामलों का हवाला असली दिखने वाले फर्जी सबूतों के आधार पर करते हैं एवं लोगों की बात पुलिस समेत अन्य जांच एजेंसियों के नकली अधिकारियों से कराई जाती है। फर्जी एफआइआर, गिरफ्तारी का वारंट और अन्य नकली दस्तावेज मुहैया कराए जाते हैं, जिनमें पीड़ित का नाम दर्शाया जाता है। ऐसी स्थिति में पीड़ित व्यक्ति बुरी तरह भयभीत हो जाता है। ऐसे कई मामलों में वर्दीधारी पुलिस अधिकारी वीडियो काल पर किसी थाने में बैठे हुए पुलिसिया भाषा में बात करते दिखाया जाता है। पीड़ित को जब गिरफ्तारी की आशंका सच में बदलते हुए प्रतीत होती है, तो वह बिना देर किए, ठगों के संकेत पर मांगी गई रकम भेजने में ही अपनी भलाई समझता है।' डिजिटल अरेस्ट' साइबर लुटेरों के हाथ लगा बड़ा हथियार है, वर्ष 2024 में पूरे देश से साइबर ठगी लाखों की संख्या में शिकायतें दर्ज की गई। इनमें से कई करोड़ रूपए आम लोगों को आभासी गिरफ्तारी का डर दिखा कर ठगे गए है।

अनजान नंबरों से आए फोन अनदेखा करें : लोगों को थोड़ा सजग रहे एवं रुपए-पैसे के लेनदेन से जुड़ी अपनी निजी जानकारी साझा करने से बचे और आभासी गिरफ्तारी के डर पर काबू पा ले, तो साइबर लुटेरों के मनसूबे पूरे नहीं हो सकते। अनजान नंबरों से आए फोन को अनदेखा करें। अगर कोई फोन कॉल सुनना जरूरी हो जाए, तो बिना डरे और निजी जानकारियां साझा किए बिना ही बात करें। जगारूकता एवं सजगता से ही इस साइबर अपराध को रोका जा सकता है।

अपराधियों के लिए बने कठोर कानून : देश में साइबर अपराधियों पर कड़ी नकेल कसने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कानून बनाया गया है इस कानून के तहत, साइबर अपराधों के लिए दंड और सजा का प्रावधान है। फिर भी सरकार को इस पर और भी कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है जिससे इन साइबर अपराधियों में डर पैदा हो और आमजन भयमुक्त जीवन जी सकें।

किरोड़ी लाल मीना
(वरिष्ठ सहायक, उपनिदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय, सवाई माधोपुर)

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक श्रीमती कमलेश विजयवर्गीय द्वारा बढ़ता राजस्थान प्रिंटिंग प्रेस,हमीरपुरा रोड खण्डवा,निवाई टोंक (राज.) से मुद्रित एवं 185/ 116 ''प्रतीक्षा'' सेक्टर-18, प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर से प्रकाशित, संपादक-तनुजा पठान"। प्रधान संपादक-राम बिलास विजयवर्गीय मो. 9414242258, 9214048888,जयपुर फोन नं.0141-2796794,795 टोंक कार्यालय-बाईपास निवाई, टोंक फोन नं.01432-244881 निवाई 01438-222201,202,203 अलवर कार्यालय-मेहताब सिंह का नोहरा,अलवर मो. 7733000123,कोटा कार्यालय-छावनी मेन रोड,कोटा मो.9414823448 । ई मेल-badhatarajasthan@yahoo.com "पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार

राष्ट्रीय सहारा

नई दिल्ली • बुधवार • 27 नवम्बर • 2024

www.rashtriyasahara.com

समाजवाद का अर्थ

यह महज संयोग है कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर संविधान के प्रस्तावना में निहित समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्दों के महत्त्व और उसकी उपयोगिता की व्याख्या की है, जिनका स्वागत किया जाना चाहिए। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के बारे में कहा कि भारत के नागरिकों ने इन दोनों शब्दों को अंगीकार करके आत्मसात कर लिया है। इसलिए 44 वर्षों बाद इन शब्दों को संविधान के प्रस्तावना से निष्प्रभावी किए जाने का कोई वैज्ञानिक आधार दिखाई नहीं देता है। वास्तव में यह शब्द मूल संविधान के हिस्से नहीं थे। संविधान सभा में इन शब्दों पर विस्तृत विमर्श हुआ था, लेकिन अंततः संविधान में इन्हें शामिल करने के विचार का परित्याग कर दिया गया था। इंदिरा गांधी की सरकार ने आपातकाल के दौरान 1976 में संविधान के 42 में संशोधन के जरिए इन शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा था। वर्ष 2020 में अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, सुब्रह्मण्यम स्वामी और अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्दों को प्रस्तावना में शामिल किए जाने को चुनौती दी थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। याचिकाकर्ताओं का मानना है कि इन शब्दों को आपातकाल में जोड़ा गया जब लोक सभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। एक वर्ग का यह भी मानना है कि समाजवाद शब्द एक विशेष विचारधारा के पद पर चलने का संकल्प जाहिर करता है जो प्रतिनिधित्व और लोकतंत्र के सिद्धांतों के विरुद्ध है। कोर्ट का विश्वास है कि इन शब्दों को प्रस्तावना में 1976 में भले ही जोड़ा गया, लेकिन संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनसे जाहिर होता है कि ये संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 यह प्रावधान करता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म के आधार पर विभेद नहीं करेगा। शीर्ष अदालत ने समाजवाद को कल्याणकारी राज्य के रूप में व्याख्या की जो राज्य के नागरिकों के सामाजिक-आर्थिक जीवन के उन्नयन में महती भूमिका का निर्वाह करता है। संविधान की प्रस्तावना में निहित समाजवाद शब्द दक्षिणपंथी या वामपंथी अर्थव्यवस्था अपनाने के लिए विवश नहीं करता। 1955 के कांग्रेस अधिवेशन ने समाजवादी आर्थिक पक्ष पर चलने का संकल्प व्यक्त करते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। यह आज भी जारी है।

सहकार की जरूरत

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का यह कहना कि भारत के लिए सहकारी समितियां संस्कृति और जीवनशैली का आधार हैं, बिल्कुल न्यायसंगत है। वैश्विक सहकारिता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने सहकारिता आंदोलन को सर्कुलर इकोनॉमी से जोड़ने की जरूरत पर जोर दिया। मोदी ने भारत के भविष्य के विकास में सहकारी समितियों की बड़ी भूमिका बताते हुए बीते दस सालों में सहकारी समितियों से संबंधित परिवेश को बदलने की चर्चा भी की। सहकारी बैंकों में इस वक्त तकरीबन बारह लाख करोड़ रुपए जमा हैं। सहकारिता आंदोलन को आगे बढ़ाने में महिलाओं की बड़ी भूमिका की सराहना करते हुए मोदी ने बताया कि इन समितियों में साठ फीसद महिलाएं हैं। सहकारी समितियों का मतलब है जनता का वह संगठन जो सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक लाभ के लिए स्वेच्छा से मिलकर काम करता है। इसे साझा समृद्धि का बेहतरीन मॉडल माना जाता है। ये अपने सदस्यों व इर्द-गिर्द के समुदाय को लाभ प्रदान करती हैं। कुछ जगह सरकार भी सहकारी समितियों में सदस्य है। राष्ट्रीय सहकारी व्यापार संघ के अनुसार दुनिया भर में तकरीबन तीन मिलियन सहकारी समितियां हैं। जिनकी विश्व की 12 फीसद आबादी सदस्य है। सहकारी समितियों के सदस्य त्वरित ऋण द्वारा स्वरोजगार चालू करने को स्वतंत्र होते हैं। हालांकि इन समितियों पर प्रबंधन अकुशलता के आरोप लगते रहते हैं। खासकर अपने यहां सहकारी समितियां पारस्परिक मतभेदों, आपसी झगड़ों और असहयोग की भेंट चढ़ जाती हैं। उनमें होने वाले घपलों/ घोटालों से मुंह नहीं चुराया जा सकता। सहकारी बैंकों के खातों से लेकर उनमें हुई भर्तियों की धांधली पर सरकार खुद संदेह के घेरे में रही है। बात सिर्फ मंत्रालय बनाने या सहकारी समितियों से महिलाओं को जोड़ने भर तक ही सीमित नहीं है। प्रधानमंत्री की अपेक्षाओं पर तभी खरा उतरा जा सकता है, जब इन रुकावटों को सिरे से साफ किया जा सके। हम तेजी से बढ़ती इकोनॉमी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। फिर भी हकीकत तो यही है कि देश की कुल संपत्ति का आधे से अधिक हिस्सा अभी भी एक प्रतिशत अति समृद्धों की मुट्ठी में है। जिन्हें किसी सहकारिता के प्रति कोई सरोकार नहीं। धन प्रबंधन के महत्व तथा सहकारिता को जितनी गहराई से समझा जाएगा, आम जनता तक उसका लाभ खुद-ब-खुद पहुंचना शुरू हो जाएगा।

डायबिटीज/डॉ. सत्यवान सौरभ

गंभीर स्वास्थ्य चुनौती

डायबिटीज वैश्विक स्तर पर एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती के रूप में उभरा है और भारत अब व्यापकता और निदान न किए गए मामलों दोनों में सबसे आगे है, जिसमें 212 मिलियन लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं और 30 वर्ष से अधिक आयु के 133 मिलियन लोग उपचार के बिना रह रहे हैं। जीवनशैली में बदलाव, आहार पैटर्न और तंबाकू के उपयोग से प्रेरित भारत में डायबिटीज के मामलों में वृद्धि, विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2030 के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्त्वपूर्ण बाधाएं खड़ी करती है, यह सुनिश्चित करना कि डायबिटीज से पीड़ित 80 फीसद लोगों का निदान हो और उनमें से 80 फीसद ग्लाइसेमिक नियंत्रण प्राप्त करें।

डायबिटीज एक ऐसी स्थिति है जो तब होती है जब आपका रक्त शर्करा (ग्लूकोज) बहुत अधिक होता है। यह तब विकसित होता है जब आपका अग्न्याशय पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनाता है या बिल्कुल भी नहीं बनाता है, या जब आपका शरीर इंसुलिन के प्रभावों पर ठीक से प्रतिक्रिया नहीं करता है। डायबिटीज का निदान होना जीवन बदलने वाली घटना है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप एक खुशहाल और स्वस्थ जीवन नहीं जी सकते। डायबिटीज का प्रबंधन करने के लिए निरंतर देखभाल और परिश्रम की आवश्यकता होती है। हालांकि यह शुरू में बहुत भारी लग सकता है, लेकिन समय के साथ आप इस स्थिति का प्रबंधन करने और अपने शरीर के साथ तालमेल बिठाने में बेहतर समझ हासिल कर लेंगे। अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता (ओं) से नियमित रूप से मिलते रहें। डायबिटीज के प्रबंधन में टीम के प्रयास की आवश्यकता होती है-आप चाहेंगे कि चिकित्सा पेशेवर, मित्र और परिवार आपके साथ हों। यदि आपको मदद की आवश्यकता हो तो उनसे संपर्क करने में संकोच न करें, जबकि भारत ने डायबिटीज को संबोधित करने के लिए कदम उठाए हैं, चुनौती की गंभीरता को देखते हुए गहन और समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। निदान को बढ़ाना, प्राथमिक स्तर पर व्यापक देखभाल को एकीकृत करना और जीवनशैली और व्यवहार संबंधी कारकों को संबोधित करना, 2030 के डब्ल्यूएचओ लक्ष्यों को पूरा करने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।

देश की नई आर्थिक चिंताएं

अर्थव्यवस्था

डॉ. जयंतीलाल भंडारी

यकीनन इस समय बढ़ते हुए रूस-यूक्रेन युद्ध और इस्राइल-ईरान संघर्ष के कारण भारत की भी आर्थिक चिंताएं बढ़ गई हैं। ये चिंताएं बढ़ती कीमतों, शेयर बाजार में गिरावट, माल ढुलाई की लागत बढ़ने, खाद्य वस्तुओं की महंगाई, भारत से चाय, मशीनरी, इस्पात, रत्न, आभूषण तथा फुटवियर जैसे क्षेत्रों में निर्यात आदेशों में कमी, निर्यात के लिए बीमा लागत में वृद्धि तथा युद्ध में उलझे हुए देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार में कमी के रूप में दिखाई दे रही हैं।

स्थिति यह है कि वैश्विक शेयर बाजार के साथ-साथ भारत के शेयर बाजार पर भी असर पड़ना शुरू हुआ है। पश्चिम एशिया संकट और चीन से सरकारी प्रोत्साहन के दम पर बाजार चढ़ने के मद्देनजर भारत के शेयर बाजार में कुछ विदेशी निवेशकों के द्वारा जोखिम वाली संपत्तियां बेची जा रही हैं और वे अपना बड़ी संख्या में निवेश निकाल रहे हैं। स्थिति यह है कि सेंसेक्स और निफ्टी के लिए अक्टूबर और नवम्बर 2024 दो साल की बड़ी गिरावट के महीनों के रूप में दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच निवेशक सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की खरीदी का भी रुख कर रहे हैं। इससे वैश्विक स्तर के साथ-साथ भारत में भी सोने की खपत और सोने की कीमत बढ़ी है।

एक चिंताजनक बात यह है कि ईरान और इस्राइल के बीच संघर्ष का असर वैश्विक शिपिंग रूट्स पर भी पड़ सकता है। दुनिया को मिलने वाला करीब एक तिहाई तेल और खाद्य व कृषि उत्पादों का अधिकांश यातायात इसी मार्ग से होता है। इससे खाद्य पदार्थों, जैसे कि गेहूं, चीनी और अन्य कृषि उत्पादों की कीमतें बढ़ने लगेंगी। यह बात भी महत्त्वपूर्ण है कि ईरान और इस्राइल के बीच युद्ध का अप्रत्यक्ष प्रभाव भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग पर भी पड़ सकता है, क्योंकि भारत अभी भी ज्यादातर दवाओं के लिए कच्चे माल का बड़ा हिस्सा विदेश से आयात करता है। ऐसे में दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका होगी। इसमें कोई दो मत नहीं है कि पश्चिम एशिया में युद्ध के बढ़ने पर भारतीय शेयर बाजार में तेज गिरावट और महंगाई वृद्धि का दौर निर्मित होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भी भारत के कई ऐसे मजबूत आर्थिक पक्ष हैं जिनसे भारत के आम आदमी और भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक नुकसान नहीं हो सकेगा। खास बात यह है कि इस समय भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। भारत खाद्यान्न अतिशेष वाला देश है और देश के 80 करोड़ से अधिक कमजोर वर्ग के लोगों को निशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भी भारत पर दुनिया का आर्थिक विश्वास बना हुआ है। नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक 21 नवम्बर तक भारत के पास 650 अरब डॉलर से अधिक का विदेशी

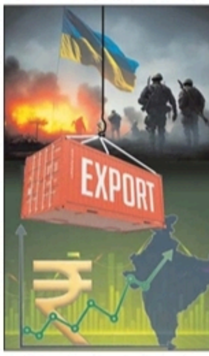

मुद्रा भंडार है, जिससे भारत किसी भी आर्थिक जोखिम का सरलतापूर्वक सामना करने में सक्षम है। यदि दुनिया के युद्धग्रस्त देशों में युद्ध और तेजी से बढ़ेगा तो कच्चे तेल के वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने का सिलसिला शुरू हो सकता है और अब यदि कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ेंगी तो दुनियाभर में कई वस्तुओं के दाम बढ़ने के साथ-साथ भारत में भी कीमतें बढ़ने का सिलसिला शुरू हो सकता है।

चूंकि ईरान दुनिया के सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादकों में से एक है और यह देश पश्चिम एशिया के संवेदनशील इलाकों में स्थित है। ऐसे में ईरान के तेल बाजार में अस्थिरता से कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ने पर पेट्रोल, डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पाद महंगे होने लगेंगे। यह भी चिंताजनक है कि अभी देश में महंगाई बढ़ने का रुझान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। 14 नवम्बर को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में थोक महंगाई दर बढ़कर 2.36 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो 4 महीने का उच्चतम स्तर है। बीते महीने खाद्य पदार्थों, विशेष रूप से सब्जियों और विनिर्मित वस्तुओं की कीमतें महंगी हो गई हैं। सितम्बर 2024 में थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर 1.84 प्रतिशत थी। ज्ञातव्य है कि 12 नवम्बर को प्रकाशित आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर 2024 में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.21 प्रतिशत हो गई। यह महंगाई का 14 महीने का उच्चतम स्तर है। इससे पिछले महीने सितम्बर में खुदरा महंगाई दर 5.49 प्रतिशत दर्ज की गई थी तथा अगस्त में 3.65 प्रतिशत थी। आलू, प्याज के साथ अन्य सभी प्रकार की सब्जियों की कीमतों में तेज वृद्धि तथा महंगे हुए अनाज व फलों के कारण अक्टूबर माह में खाद्य वस्तुओं की खुदरा महंगाई दर भी बढ़कर 10.87 प्रतिशत हो गई, जबकि सितम्बर माह में यह 9.24 प्रतिशत तथा माह अगस्त में 5.66 प्रतिशत थी।

इसमें कोई दो मत नहीं है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच अब सरकार को भी महंगाई नियंत्रण के लिए बहुआयामी रणनीति की डगर पर आगे बढ़ना होगा। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के चलते वैश्विक तेल की कीमतों में आए उछाल पर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि पश्चिम एशिया में अधिक तनाव बढ़ने पर भारत कच्चे तेल के किसी भी संकट से निपटने में सक्षम होगा। पहले भारत 27 देशों से कच्चा तेल खरीदता था अब इन देशों की संख्या बढ़कर 39 हो गई है। चालू वित्त वर्ष 2024-25 के बजट के तहत किए गए महंगाई नियंत्रण उपायों पर तुरंत कार्यान्वयन किया जाए।

हम उम्मीद करें कि पश्चिम एशिया संघर्ष और रूस-यूक्रेन युद्ध के विस्तारित होने पर सरकार बाजार की गिरावट रोकने के लिए भी रणनीतिपूर्वक आगे बढ़ेगी। हम उम्मीद करें कि सरकार पीएलआई योजना के तहत दवाई उद्योग में काम आने वाले जिन 35 प्रमुख कच्चे मालों (एपीआई) का उत्पादन देश में ही कर रही है, उनके अलावा करीब 18 प्रकार के एपीआई का उत्पादन भी देश में ही करने की डगर पर तेजी से आगे बढ़ेगी, ताकि दवाइयों के दामों पर नियंत्रण रखा जा सकेगा। ऐसे बहुआयामी रणनीतिक प्रयासों से देश के आमजन व देश की अर्थव्यवस्था को पश्चिम एशिया संघर्ष और विस्तारित होते रूस-यूक्रेन युद्ध के दुष्प्रभावों से बहुत कुछ बचाया जा सकेगा।

(लेखक के निजी विचार हैं)

हम उम्मीद करें कि सरकार पीएलआई योजना के तहत दवाई उद्योग में काम आने वाले जिन 35 प्रमुख कच्चे मालों (एपीआई) का उत्पादन देश में ही कर रही है, उनके अलावा करीब 18 प्रकार के एपीआई का उत्पादन भी देश में ही करने की डगर पर तेजी से आगे बढ़ेगी, ताकि दवाइयों के दामों पर नियंत्रण रखा जा सकेगा। ऐसे बहुआयामी रणनीतिक प्रयासों से आमजन व अर्थव्यवस्था को प. एशिया संघर्ष और विस्तारित होते रूस-यूक्रेन युद्ध के दुष्प्रभावों से बचाया जा सकेगा

- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार भारत के प्रीमियम सी-फूड निर्यात में जबरदस्त वृद्धि हुई है। 2023-24 में सी-फूड निर्यात का मूल्य 7.3 बिलियन डॉलर और मात्रा 17.81 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गई
- यूरोपीय संघ भारत का दूसरा सबसे बड़ा सी-फूड मार्केट बन गया है, जिसकी वार्षिक खरीद 0.95 बिलियन डॉलर है। भारत यूरोपीय संघ का दूसरा सबसे बड़ा झींगा सप्लायर भी है, जिसकी बाजार हिस्सेदारी 8 प्रतिशत है

(स्रोत : मीडिया इनपुट्स)

2014 के बाद से कांग्रेस बीजेपी की आमने-सामने की टक्कर में बीजेपी का पलड़ा भारी रहा। कुछ राज्यों में कांग्रेस ने बीजेपी से सत्ता जरूर छीनी जैसे हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान आदि। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि कांग्रेस ने बीजेपी का मुकाबला कर किसी राज्य में दोबारा सत्ता हासिल की हो। क्षेत्रीय दलों ने जरूर यह कर दिखाया है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और अब झारखंड में हेमंत सोरेन ने बीजेपी को हरा कर दोबारा सत्ता हासिल की। इस मोर्चे पर कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टियों से सीख सकती है।

अखिलेश शर्मा, पत्रकार
@akhileshsharma1

ऊंची बोली लगाकर चौंकाया

आईपीएल | मनोज चतुर्वेदी

आईपीएल की हर नीलामी में एक अलग ही कहानी देखने को मिलती है। इस बार सऊदी अरब के जेद्दाह में आयोजित आईपीएल नीलामी में फ्रेंचाइजियों ने धनवर्षा के लिए भारतीय खिलाड़ियों को चुना। भारतीय खिलाड़ियों में ऋषभ पंत 27 करोड़ रुपए पाकर आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। पिछली नीलामी में ऑस्ट्रेलिया के पेस गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने 24.75 करोड़ रुपए पाकर नया रिकॉर्ड बनाया था। पर इस बार पहले श्रेयस अय्यर को पंजाब किंग्स ने 26.75 करोड़ रुपए में खरीदकर इस रिकॉर्ड को तोड़ा और फिर पंत ने इस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। ऋषभ पंत की जब 20.75 करोड़ रुपए पर बोली रुकी तो उस समय उनकी पुरानी टीम दिल्ली कैपिटल्स को 'राइट टू मैच' (आरटीएम) का इस्तेमाल करने का मौका मिला। पर एलएसजी ने उनकी बोली को 27 करोड़ रुपए बढ़ाकर दिल्ली के हाथ से बाजी ले ली।

वैसे सोचने वाली बात यह है कि दिल्ली कैपिटल्स यदि (आरटीएम) का इस्तेमाल करती तो फिर यह सवाल उठता कि उसने उन्हें रिटेन क्यों नहीं किया, जो उससे कम राशि में हो जाता। इसी तरह श्रेयस अय्यर की भी एक अलग ही कहानी है। वह एक ऐसी टीम केकेआर को छोड़कर आए थे, जो चैंपियन बनी थी। कोई चैंपियन टीम का कप्तान छोड़कर जाए, ऐसा पहले नहीं देखा गया था। पर इसकी वजह शायद केकेआर टीम प्रबंधन और श्रेयस में पैसे बढ़ाने की बात नहीं बन पाई और वह फ्रेंचाइजी को छोड़कर नीलामी में उतर गए, जिसका फायदा उन्हें नीलामी के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में मिला। इस बार नीलामी की खूबी यह रही कि सबसे महंगे बिके टॉप पांच खिलाड़ियों में एक भी विदेशी खिलाड़ी नहीं है। पंत और श्रेयस के बाद वेंकटेश अय्यर को केकेआर ने 23.75 करोड़ रुपए में और अर्शदीप और युजवेंद्र चाहल को पंजाब किंग्स ने 18-18 करोड़ रुपए में खरीदा है। जोस बटलर सबसे महंगे खिलाड़ियों की सूची में छठे नंबर पर हैं और उन्हें गुजरात टाइटंस ने 15.75 करोड़ रुपए में खरीदा है। पिछली नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी बने मिचेल स्टार्क को इस बार दिल्ली कैपिटल्स ने पिछली से आधी राशि से भी कम यानी 11.75 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। स्टार्क की तरह ही ग्लेन मैक्सवेल भी अपनी उपयोगिता खोते नजर आए हैं। इस बार वह 4.40 करोड़ में पंजाब किंग्स में गए हैं। इस बार आईपीएल नीलामी में सुर्खियां बटोरने वाले बिहार के वैभव

सूर्यवंशी रहे। वह मात्र 13 साल की उम्र में आईपीएल के लिए चुने जाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 1.10 करोड़ रुपए में खरीदा है। नीलामी में फ्रेंचाइजी अपनी जरूरतों केहिसाब से मन बनाकर आती हैं। वह इस बात का पूरा विश्लेषण करती हैं कि उन्हें किस क्षेत्र में किस तरह के देशी या विदेशी खिलाड़ी चाहिए। जब किसी खिलाड़ी में ज्यादा टीमों की दिलचस्पी बन जाती है तो उसकी कीमत ऊंची चली जाती है। यही वजह है कि दक्षिण अफ्रीका के पेस गेंदबाज मार्को येनसन सात करोड़ में खरीदे जाते हैं। वहीं अंतरराष्ट्रीय कॅरियर समाप्त कर चुके भुवनेश्वर कुमार 10.75 करोड़ रुपए पा जाते हैं। वैसे आईपीएल को करोड़पति बनाने वाली मशीन भी समझा जाता है। कई बार ऐसे खिलाड़ियों को करोड़पति बना दिया जाता है, जिन्हें खुद इस बात की उम्मीद नहीं होती है। इस बार इस तरह के खिलाड़ियों में प्रियांश आर्य और अंशुल कंबोज के नाम शामिल किए जा सकते हैं। शायद इस नीलामी से पहले इनके रिश्तेदारों को भी इनके बारे में ज्यादा पता नहीं होगा। पर नीलामी में पंजाब किंग्स ने 3.80 करोड़ रुपए में खरीदकर सबसे महंगा अनकैप्ड खिलाड़ी बना दिया है। वहीं अंशुल कंबोज को चेन्नई सुपरकिंग्स ने 3.40 करोड़ रुपए में खरीदा। प्रियांश की खूबी छक्के लगाने में महारत रखना है। वह स्थानीय टी-20 लीग में एक ओवर में छह छक्के लगा चुके हैं। वह दिल्ली प्रीमियर लीग में ओपनिंग करके सबसे ज्यादा 608 रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे। इस खिलाड़ी में एक खूबी यह भी है कि वह गौतम गंभीर के कोच रहे संजय भारद्वाज से ही ट्रेनिंग लेते हैं।

जहां तक बात अंशुल कंबोज की है तो वह करनाल से ताल्लुक रखते हैं और ऑलराउंडर हैं। वैसे तो वह मुंबई इंडियंस के लिए तीन आईपीएल मैच खेल चुके हैं। इनमें वह दो विकेट ले चुके हैं। उन्होंने प्रथम श्रेणी के खेले 19 मैचों में 368 रन बनाकर अपनी सही प्रतिभा दिखाई है। यह रन उन्होंने 42 चौकों और 20 छक्कों की मदद से बनाए हैं। यह सही है कि आईपीएल नीलामी में खिलाड़ियों को दी जाने वाली ऊंची रकम का कोई लॉजिक नहीं होता। पर यह भी सच है कि टीमें कई बार बड़े-बड़े दिग्गजों तक पर निगाह नहीं डालकर उन्हें रद्दी की टोकरी में डाल देती हैं। इसकी वजह उनकी निगाह में इन दिग्गजों की कोई उपयोगिता नहीं होना है। यही वजह है कि इस बार डेविड वॉर्नर, डेरेल मिचेल, पृथ्वी शॉ, शार्दुल ठाकुर जैसे खिलाड़ी बिना बिके रह गए। पर इस बार एक नई खूबी इस लीग में जुड़ने जा रही है कि इसमें भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रति मैच 7.5 लाख रुपए की मैच फीस भी मिलेगी। इसलिए अब सभी 14 मैच कोई 30 लाख रुपए में खरीदा खिलाड़ी खेलता है तो वह एक करोड़ से ज्यादा कमा सकेगा।

दहेज | श्रीराम शर्मा आचार्य

साधु-ब्राह्मणों का यह एक परम पवित्र कर्त्तव्य है कि इस समय जिस धर्म के आश्रय में वे अपनी आजीविका चलाते हैं और पूजा-सम्मान प्राप्त करते हैं उस धर्म रक्षा के लिए उन्हें कुछ काम भी करना चाहिए-कष्ट भी उठाना चाहिए। आज जबकि धर्म संकट में है, देश की सुरक्षा एवं प्रगति का प्रश्न है तब तो उन्हें उन आदर्शों को परिपुष्ट करने के लिए अपना समय लगाना ही चाहिए। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी दक्षिणा बटोरने और पैर पुजाने का ही धंधा करते रहे, कर्त्तव्य की तिलांजलि दिए बैठे रहे तो आगामी पीढ़ियां उन्हें क्षमा न करेंगी। आज दहेज का असुर भाषण-लेखों और प्रस्तावों की मार खाकर भी दहेज का असुर मरता नहीं। रक्तबीज की तरह वह चोट खाकर और भी अधिक विकराल बनता चला जा रहा है। इसका अंत ऐसे होगा कि युग निर्माण योजना के सदस्य बच्चे यह प्रतिज्ञा करेंगे कि वे विचारशील साथी से ही विवाह करेंगे। दहेज और विवाहोन्माद में होने वाले भारी अपव्यय को हटाकर बिना खर्च की विधि से विवाह करेंगे। यदि अभिभावक इस निश्चय को मान्यता न देंगे तो वे आजीवन कुमार या कुमारी ही रहकर पवित्र जीवन व्यतीत करेंगे। आज भड़कीला श्रृंगार फैशन कहा जाता है और उसे कला, सुरुचि एवं सभ्यता का चिह्न कहकर पुकारा जाता है। कहा और माना जो कुछ भी जाए वास्तविकता ज्यों की त्यों रहेगी। हमारे उठती उम्र के बच्चे और बच्ची इस पतन पथ पर कदम न बढ़ाएं इसका ख्याल रखा जाना चाहिए। उत्तेजक श्रृंगार की जड़ में वासना का विकार स्पष्ट है इससे देखने वालों के मन में विक्षोभ उत्पन्न होता है। इसलिए हम सफाई से रहें, स्वच्छता पसंद करें, सादगी से रहें और सभ्य वेशभूषा धारण करें। मातृत्व पर-नारीत्व पर सर्वाधिक लानत फेंकने का काम दहेज के राक्षस ने किया है। इसे समझा भी गया तथा उसके निवारण के प्रयास भी बहुत हुए, सामाजिक भर्त्सनाएं की गईं, कानून भी बना। दहेज के प्रतिरोध में सैकड़ों विचारशील व्यक्तियों ने लिखा, भाषण किया, पर पुरानी पीढ़ी अपने स्थान से तिल भर हटने की तैयारी नहीं। जब कोई साहसपूर्वक प्रतिरोध, संघर्ष एवं आदर्श उपस्थित करने को तैयार होगा, तभी कुछ समस्या हल होगी। यह आशा अब नये रक्त से ही शेष है।

रीडर्स मेल

सख्त कार्रवाई जरूरी

बरेली में रामगंगा पर जर्जर पुल से एक कार के गिरने से तीन लोगों की जीवन लीला समाप्त हो गई। आखिर यह पीड़ादायक दुर्घटना का दायित्व किसका है? ऐसा भी नहीं कि कार की अधिक गति होने से यह दुर्घटना हुई, ऐसा भी नहीं कि किसी अन्य वाहन से कार टकराई हो। जिस पुल से कार 25 फुट गहराई में गिरी उस पुल का एक हिस्सा बरसात में 2022 में बह गया था, लेकिन न तो सेतु निगम और न ही पीडब्ल्यूडी ने पुल के पुनर्निर्माण पर ध्यान दिया। बस एक छोटी दीवार खड़ी करके अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ ली। अब जांचों का सिलसिला अवश्य शुरू होगा। विभागों की लापरवाही से यही तीन जिंदगी ही नहीं बल्कि प्रायः इसी तरह की लापरवाही से ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती है। इस बाबत दोषी लोगों पर सख्त कार्रवाई की दरकार है।

डॉ. नरेन्द्र टोंक, मेरठ

कैसे कम होगी महंगाई

देश की आम जनता से लेकर खास लोग तक सभी महंगाई की मार से त्रस्त है। टमाटर, प्याज, मटर, लहसुन और अदरक की कीमतें पिछले कुछ महीनों से आसमान छू रही है। दाल महंगी होने की वजह से आज गरीबों की थाली से दाल गायब हो चुकी है। धरातल पर महंगाई आंकड़ों से कहीं अधिक है। रोजमर्रा की सामग्री सब्जी, फल, तेल, दवा, जूता-चप्पल आदि सभी महंगी होती जा रही है। सरकार को आमजनों को महंगाई से राहत देने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में कटौती करनी चाहिए।

हिमांशु शेखर, गया

सक्रिय हो संयुक्त राष्ट्र संघ

देश-दुनिया में कहीं भी शांति नहीं है। रूस व यूक्रेन के बीच युद्ध को हजार से अधिक दिन हो गए हैं। दूसरी तरफ इस्राइल, फिलिस्तीन व ईरान के बीच युद्ध चल रहा है। अनगिनत सैनिक, निर्दोष नागरिक व महिलाएं व बच्चे इन युद्ध की वजह से जान गंवा चुके हैं तथा बेहिसाब संपत्ति की हानि हुई हो रही है। युद्ध की वजह से पर्यावरण को भी खतरा है। आए दिन चीन व पाकिस्तान जैसे देश भी पड़ोसी देश को चैन से नहीं रहने देते। इन सबके बीच विश्व की सबसे बड़ी पंचायत संयुक्त राष्ट्र संघ भी अपनी भूमिका के साथ न्याय नहीं कर पा रहा है। सवाल यह कि आखिर संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था का आज क्या औचित्य रह गया है? जहां-जहां युद्ध हो रहे हैं, वहां अपनी सक्रियता से युद्ध को रोकने में महत्ती भूमिका निभानी होगी।

हेमा हरि उपाध्याय 'अक्षत', उज्जैन

आरंभ है प्रचंड

न्यूजीलैंड के हाथों 3-0 से घर में श्रृंखला हारने के बाद, ऑस्ट्रेलिया में पहले टेस्ट में जीत वाकई राहत की बात है। जसप्रीत बुमराह की एक गेंदबाज और एक कप्तान के तौर पर जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है। निसंदेह पर्थ टेस्ट की इस जीत को भारतीय टीम की सेना देशों में हुई सबसे अहम जीतों में से एक के रूप में देखा जाना चाहिए। कोहली और राहुल की फॉर्म में वापसी, जायसवाल का शानदार सैकड़ा, नीतीश रेड्डी का अपने पहले मैच में इस तरह ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना और मोहम्मद सिराज का अपनी गेंदबाजी की धार वापस पाना; यह सब इस 'बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी' के आने वाले 4 मैचों के लिए भारतीय टीम के लिए अच्छे संकेत हैं।

बाल गोविंद, नोएडा

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित। समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रमेश मिश्र* ।

राष्ट्रीय सहारा

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 242

क्षमता केंद्रों को मिले सक्षम माहौल

बीते कुछ वर्षों में कारोबारी सेवा क्षेत्र में घटित कुछ अहम और उत्साहजनक घटनाओं में से एक है समग्र 'वैश्विक क्षमता केंद्रों' यानी जीसीसी का विकास जो बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए मददगार साबित होते हैं। इनमें से कई भारत में स्थित हैं या उन्हें भारत में बनाने की योजना है। यह दर्शाता है कि भारत के घरेलू क्षेत्र का दायरा बढ़ा है और उसके मूल्यवर्धन में भी अहम इजाफा हुआ है। स्वाभाविक सी बात है कि प्रस्तावित जीसीसी के लिए तय स्थानों की बात करें तो एक स्वस्थ घरेलू प्रतिस्पर्धा नजर आती है। कर्नाटक सरकार ने पहले ही जीसीसी पर केंद्रित एक रणनीति जारी कर दी है। अब मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने घोषणा की है कि राज्य सरकार की योजना जीसीसी के लिए तीन पार्क बनाने की है। ये पार्क बेंगलूरु, मैसूरु और बेलागावी में बनाए जाने हैं।

जीसीसी पर सिद्धरमैया का ध्यान उपयोगी भी है और आवश्यक भी। सूचना प्रौद्योगिक सक्षम सेवा क्षेत्र की बात करें तो लंबे समय से बेंगलूरु को उनका घर माना जाता रहा है लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि बीते कुछ वर्षों में इसके तकनीकी, शासन और कॉर्पोरेट विकास के क्षेत्र में पीछे रह जाने का जोखिम उत्पन्न हो गया है। परंतु यह भी समझने की आवश्यकता है कि किसी भी अन्य राज्य की तरह कर्नाटक में भी जीसीसी के विकास के लिए बुनियादी आवश्यकताएं वही हैं जो व्यापक रूप से हर नए निवेश, खासकर विदेशी निवेश के लिए जरूरी होती हैं। इनमें जमीन की उपलब्धता, उन्नत अधोसंरचना, सड़कें, विश्वसनीय और किफायती बिजली आपूर्ति (नवीकरणीय ऊर्जा हो तो बेहतर), और विवादों का आसानी से निपटारा शामिल हैं। अतीत में कर्नाटक सरकार का प्रदर्शन इन मानकों पर बहुत अच्छा नहीं रहा है। कई बार कर्नाटक कर और नियामकीय विवादों के लिए सुर्खियों में रहा है। राज्य का ध्यान स्पष्टता बढ़ाने पर केंद्रित होना चाहिए, न कि उसे कम करने पर। कारोबारी सेवाओं में मूल्य श्रृंखला में बेहतरी की बात करें तो शहरीकरण एक अहम कारक है। कुछ अनुमानों के मुताबिक देश के कुल आईटी और आईटी सक्षम सेवा निर्यात में 85 फीसदी चार राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु से होता है। जीवंत शहरी केंद्रों की उपस्थिति ही इसे संभव करती है। कर्नाटक की वर्तमान सरकार संतुलित क्षेत्रीय विकास की महत्ता पर जोर देती है लेकिन उसे यह भी समझना चाहिए कि विश्वस्तरीय शहरी केंद्र ही निवेश आकर्षित करते हैं। 'बियॉन्ड बेंगलूरु' एक अच्छा नारा है लेकिन इसे हकीकत में तभी बदला जा सकता है जब प्रदेश के अन्य शहरी केंद्रों के पास भी समतुल्य संपर्क, सुविधाएं तथा बेंगलूरु-मैसूरु जैसी जीवन गुणवत्ता हो।

मुख्यमंत्री ने जीसीसी को लेकर अपनी चर्चा में यह भी कहा कि राज्य पहले ही अपनी उत्कृष्ट इंजीनियरिंग प्रतिभाओं और विश्व स्तर पर सर्वाधिक एआई पेशेवरों के साथ 'प्राथमिकता वाला गंतव्य' बना हुआ है। उन्होंने अपनी सरकार द्वारा 'उद्योगों के लिए तैयार श्रम शक्ति' तैयार करने की पहल का जिक्र किया। यह एक तथ्य है कि जीसीसी के मामले में मानव संसाधन की चिंता प्रमुख है। ऐसा इसलिए कि जीसीसी श्रम की गहनता वाले क्षेत्र होते हैं। सरकार को यह भी समझना होगा कि उद्योगों के लिए तैयार श्रम शक्ति ऐसी नहीं होती है जो 'बाहरी लोगों' के साथ भेदभाव करे। जीसीसी की योजना बना रही कोई कंपनी नहीं चाहती कि वह नौकरी देते समय स्थानीय और बाहरी के जटिल राजनीतिक विवाद में उलझे। कर्नाटक के निवासियों की उत्पादकता और उनकी क्षमता बढ़ाने संबंधी पहलें स्वागतयोग्य हैं। परंतु स्थानीय लोगों को नौकरी में आरक्षण के लिए कठोर नियमन उचित नहीं। निवेशक सजा को नहीं लालच को अधिक पसंद करते हैं। कर्नाटक सरकार को जीसीसी के लिए उपयुक्त स्थानीय उम्मीदवारों पर ध्यान देना चाहिए बजाय कि श्रम मांग को अनुकूल बनाने की बाध्यता के।

एफडीआई पर भारतीय कंपनियों की रणनीति

भारतीय कंपनियों को चाहिए कि वे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जुटाने और वैश्विक स्तर पर एक वृहद भूमिका निभाने की तैयारी करें। कई बड़ी विदेशी कंपनियां ऐसा कर चुकी हैं। बता रहे हैं अजय शाह

सभी महत्त्वपूर्ण वैश्विक कंपनियां बहुराष्ट्रीय हैं। कई बड़ी भारतीय कंपनियों ने भी विदेशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) संबंधी गतिविधि शुरू की है। परंतु अभी भी यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां क्षमताएं और नियम-कायदे प्रारंभिक स्तर पर हैं। वैश्विक कंपनियों को भारत में सेवा उत्पादन का उपयोग करते देखना एफडीआई की भूमिका पर प्रकाश डालता है। वैश्विक कंपनियों ने भारतीय श्रम शक्ति का लाभ उठाने का अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए हरसंभव तरीका अपनाया है।

वे भारतीय सेवा कंपनियों को दूरवर्ती अनुबंध के माध्यम से काम पर रखते हैं। वे वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) और सीमित जगहों पर एफडीआई करते हैं। वे भारत में जीसीसी का इस्तेमाल एक ऐसे मंच के रूप में करते हैं जिनकी मदद से वे भारतीय सेवा कंपनियों को दिए जाने वाले अनुबंधों की बातचीत और निगरानी करते हैं। वैश्वीकरण का लाभ लेने के लिए अनुबंध और एफडीआई के ऐसे ही मिश्रण की आवश्यकता होती है।

भारतीय कंपनियों को एफडीआई से फायदा क्यों हो सकता है? सफल एफडीआई पहल से निर्यात बढ़ाने में मदद मिलती है, परिचालन को लेकर वैश्विक आशावाद उत्पन्न होता है और घरेलू प्रतिस्पर्धा मजबूत होती है। इससे विश्व बाजार तक पहुंच मजबूत होती है और भारतीय अर्थव्यवस्था में धीमेपन के दौर में कंपनी का जोखिम कम होता है। भारतीय माहौल की एक विशिष्टता जो वैश्विक कंपनियों में नहीं पाई जाती है वह है भारतीय कराधान और पूंजी नियंत्रण के साथ कम संबद्धता के कारण होने वाला लाभ। यह एफडीआई में प्रवेश की तयशुदा लागत के लिए भुगतान करने में मददगार साबित होता है।

दो गुना दो वर्गीकरण योजना की स्थापना मददगार है। भारतीय कंपनियां दो तरह की होती हैं: एक तो वे जो ऐसे उत्पाद बनाती हैं जो वैश्विक उपभोक्ताओं को सीधे बेचे जा सकते हैं जैसे बाल बियरिंग आदि। दूसरी वे जो भारतीय परिदृश्य में गहराई से शामिल होती हैं। यानी परिचालन क्षमता वाली ऐसी कंपनियां जो भारतीय नीतिगत माहौल और परिदृश्य में रची बसी होती हैं। और गंतव्य देश दो प्रकार के होते हैं: विकसित देश और शेष देश।

उच्च निर्यात तैयारी वाले उद्योग और एफडीआई: वैश्वीकरण का सबसे सहज मार्ग उन कंपनियों के लिए उपलब्ध है जो ऐसे उत्पादों पर काम करती हैं जो वैश्विक ग्राहकों को बिक्री के लिए सीधे उपलब्ध होते हैं।

इन कंपनियों के लिए निर्यात का सफर और एफडीआई कारोबारी विस्तार की दृष्टि से असीमित संभावनाएं लाता है। वे ऐसी वैश्विक कंपनी बनने की आकांक्षा कर सकती हैं जो कम लागत के कारण चुनिंदा कामों को भारत में रखती हैं। भारतीय कारोबार की दुनिया में इन क्षमताओं का उभार भारत के आर्थिक भविष्य के लिए बहुत मायने रखता है। अगर 100 भारतीय कंपनियां बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में तब्दील होती हैं, उनकी बैलेंस शीट का आकार 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाता है और उनके राजस्व का 50 फीसदी से अधिक हिस्सा भारत से बाहर से आता है तो इससे देश की जीडीपी बदल जाएगी।

प्रबंधन के तौर तरीके और संगठनात्मक संस्कृति जो भारत में फलती फूलती है उसे विधि के शासन के समक्ष कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। विकसित देशों में परिचालन अक्सर सख्त होता है। इन कंपनियों के लिए आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) से बाहर के देश भी बाजार हो सकते हैं लेकिन विकसित देशों की तुलना में बाजार का आकार छोटा है। भारत केंद्रित प्रबंधन गैर ओईसीडी देशों में परिचालन में खास प्रभावी हो सकता है लेकिन नेतृत्व को ऐसी तात्कालिक विजय से बचना चाहिए क्योंकि उनका मुख्य काम है ओईसीडी देशों में परिचालन और बिक्री करना सीखना। स्थानीय कंपनियों के साथ दूरस्थ अनुबंध गैर ओईसीडी देशों की बाजार संभावनाओं का लाभ उठाने का एक अहम जरिया है, वह भी बिना उनकी गड़बड़ी वाली संस्थागत व्यवस्थाओं में परिचालन सीखे तथा विधि के शासन की कमी के बीच।

भारतीय राज्य के साथ अधिक संपर्क वाले राज्य: उन भारतीय कंपनियों के लिए हालात थोड़ा अधिक दिक्कतदेह हैं जो देश के परिदृश्य में घुलीमिली हैं। वे ऐसे उद्योगों में हैं जहां उच्च सरकारी हस्तक्षेप होता है, या ऐसे उद्योगों में जहां भारत सरकार केंद्रीय नियोजन करती है। वे भारतीय माहौल में परिचालन से लाभान्वित हो सकती हैं या फिर वे ऐसे क्षेत्रों में परिचालित हो सकती हैं जहां भारतीय राज्य महत्त्वपूर्ण ग्राहक है। इन सभी कंपनियों के लिए भारत में उनकी कामयाबी के सूत्र विदेशों में उनकी राह का रोड़ा भी बन सकते हैं। उदाहरण के लिए भारत में एक सफल बैंक जिसने रिजर्व बैंक की केंद्रीय नियोजन प्रणाली के तहत मुनाफा कमाने की क्षमता हासिल की हो, विदेशी प्रतिस्पर्धा से सुरक्षित हो और सरकारी क्षेत्र के एकाधिकार वाले क्षेत्रों की भरपाई कर रहा हो, वह अमेरिका में उन अमेरिकी प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर पाएगी जिनमें ऐसी विसंगतियां नहीं हों तथा जो भारत में जीसीसी के माध्यम से कम लागत वाले उत्पादों हासिल करने में प्रभावी रूप से कामयाब रही हों।

जब ये कंपनियां ओईसीडी देशों में कारोबार करती हैं तो यह जोखिम होता है कि उनकी संगठनात्मक संस्कृति, जो भारत में उनके अनुभवों से संचालित होती हैं वे वहां लोगों को नाराज कर सकती हैं या नियम भंग कर सकती हैं। उन्हें ओईसीडी देशों में परिचालन के लिए सचेत प्रयास करने होंगे ताकि वे स्थानीय कारोबारी संस्कृति का अनुकरण कर सकें।

ओईसीडी से इतर देशों में परिचालित कंपनियों की बात करें तो उन देशों में कानून का शासन अधिक सीमित हैं और यह भारत में काम करने के समान है। परंतु टिकाऊ कारोबार के लिए रिश्ते बनाने की बात करें तो राजनीतिक उतार-चढ़ाव के बीच वहां भारत की तुलना में यह कठिन है। ऐसे में इन कंपनियों के लिए भी गैर-ओईसीडी देश में परिचालन की सही रणनीति यही होगी कि वे साझेदारी मॉडल पर भरोसा करें।

यह वैसा ही है जैसे कि वैश्विक कंपनियां अकेले कारोबार करने के बजाय भारत में कारोबारी साझेदार चुनती हैं। इस प्रकार वे राजनीतिक जोखिम का प्रबंधन करती हैं।

रणनीति का प्रश्न: अंशधारकों, बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधकों को इन सवालों के बारे में रणनीतिक ढंग से विचार करना चाहिए। एफडीआई में कई बड़े लाभ हैं लेकिन इसके लिए रणनीतिक सोच आवश्यक है। ऐसा करके कई रुचिकर चयन किए जा सकते हैं। जैसे कि शायद एक निजी भारतीय रक्षा विनिर्माता भारतीय राज्य को बिक्री बंद करके 'भारतीय राज्य के साथ अधिक संपर्कों वाले उद्योगों' की श्रेणी से बाहर निकल सकेगा। पोर्टफोलियो रणनीतिकार भी इन थीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दौरान उन भारतीय कंपनियों पर जोर दिया जा सकता है जो ओईसीडी देशों में निर्यात और एफडीआई के लिए तैयार हैं।

(लेखक एक्सकेडीआर फोरम में शोधकर्ता हैं)

सिनेमा उद्योग में पूंजी जुटाने के लिए नए कदम

भारतीय सिनेमा के रुपहले पर्दे पर एक नई कहानी का आगाज होने जा रहा है। लेकिन पहले बात करते हैं 1990 के दशक के शुरुआती वर्षों की जब करण जौहर जो महाराष्ट्र राज्य बोर्ड की परीक्षा में वाणिज्य विषय में अव्वल रहे और उन्हें जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में एमबीए की सीट की पेशकश की गई। चूंकि वह पहले से ही फ्रांस से स्नातकोत्तर के समान एक डिग्री हासिल कर चुके थे इसलिए उन्होंने पेरिस जाने का फैसला किया क्योंकि उनका इरादा फ्रेंच भाषा में एक अन्य कोर्स करने का था। हालांकि दक्षिण मुंबई के रहने वाले जौहर की दिलचस्पी हिंदी फिल्मों में काफी पहले से थी। उन दिनों उनके बचपन के दोस्त आदित्य चोपड़ा अपनी पहली फिल्म लिख रहे थे और जौहर इस फिल्म को लिखने में उनकी मदद भी कर रहे थे।

पेरिस जाने के ठीक तीन दिन पहले चोपड़ा ने उनसे बात की और कहा, 'तुम फिल्मों के लिए ही बने हो। एक दिन तुम फिल्मकार बनोगे।' इसके बाद उन्होंने जौहर से गुजारिश की कि वे उनकी फिल्म में उनका सहयोग करें। ये बातें जौहर ने अपनी आत्मकथा 'एन अनसूटेबल बॉय' में लिखी हैं जिसे पेंगुइन प्रकाशन ने 2017 में प्रकाशित किया था।

'शोले' फिल्म के बाद भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़ी सफलता पाने वाली फिल्म 'दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे' (1995) बनी और यह एक कल्ट क्लासिक फिल्म साबित होने के साथ ही 25 वर्षों से अधिक समय तक सिनेमाघरों में चलती रही।

सूरज बड़जात्या की फिल्म, 'हम आपके हैं कौन' (1994) के साथ ही 'दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे' ने भारतीय फिल्मों के लिए विदेशी बाजार के दरवाजे खोल दिए। चोपड़ा, जौहर और बड़जात्या पहले ऐसे फिल्मकार बने जिन्होंने1990 के दशक के शुरुआती दौर में भारत में उदारवाद के आगमन के साथ ही दर्शकों की बदलती पसंद को समझते हुए नए प्रयोग करने शुरू किए।

पिछले महीने भी जौहर ने अपने प्रोडक्शन हाउस को लेकर एक अहम फैसला किया जो काफी समय से लंबित था और इस तरह एक नए रुझान की शुरुआत के संकेत मिलने शुरू हुए। जौहर अब 52 वर्ष के हो चुके हैं और वह धर्मा प्रोडक्शंस में अपनी आधी हिस्सेदारी बेचेंगे जिसमें वह एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन भी हैं। वह अदार पूनावाला की सेरेन प्रोडक्शंस को 1,000 करोड़ रुपये में धर्मा प्रोडक्शंस की अपनी आधी हिस्सेदारी बेच देंगे। धर्मा पहली ऐसी घरेलू प्रोडक्शन कंपनी बन गई है जो बाहरी पूंजी लेगी और उम्मीद है कि ऐसे और रुझान जल्द ही देखने को मिलेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर (डॉन, दिल चाहता है, गली बॉय) के स्वामित्व वाली कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट भी कॉमकास्ट के यूनिवर्सल स्टूडियोज के साथ एक करार के माध्यम से फंड जुटा सकती है।

मीडिया मंत्र
वनिता कोहली-खांडेकर

यहां से यह कहानी नए भविष्य की तरफ इशारा करती है। धर्मा की स्थापना 1976 में जौहर के पिता ने की थी और इस प्रोडक्शंस की कुछ फिल्में हिट भी रहीं जैसे कि 'दोस्ताना' (1980) लेकिन यह कंपनी बड़ी लीग में शामिल नहीं हो पाई। जौहर के निर्देशन में बनी फिल्म 'कुछ कुछ होता है' के साथ ही इस प्रोडक्शन कंपनी के दिन बहुरे। इसके साथ ही जौहर का कद भारतीय सिनेमा में प्रभावशाली होता गया और वह फिल्मकार के साथ-साथ एक मॉडल और बतौर टीवी होस्ट (कॉफी विद करण) भी काफी सुर्खियां पाने लगे। धर्मा ने ही प्रतिभाशाली युवा निर्देशकों जैसे कि शकुन बत्रा और आयान मुखर्जी को भी उभरने का भरपूर मौका दिया है। इस प्रोडक्शंस हाउस के खाते में कल हो ना हो (2003), कपूर ऐंड संस (2016), टू स्टेट्स (2014), और शेरशाह (2021) सहित 45 फिल्में हैं।

हालांकि इस कंपनी की वृद्धि बेहद अस्थिर रही है। धर्मा ने वित्त वर्ष 2022 में 278 करोड़ रुपये का राजस्व हासिल किया जो वित्त वर्ष 2023 में बढ़कर 1,044 करोड़ रुपये हो गया लेकिन फिर इस वर्ष यह कम होकर 520 करोड़ रुपये हो गया। यह वास्तव में भारत के किसी एक व्यक्ति या किसी एक महिला द्वारा संचालित प्रोडक्शन कंपनियों की हकीकत है। वहीं दूसरी ओर यशराज फिल्म्स, टी-सीरीज और एक्सेल एंटरटेनमेंट का काम गुणवत्ता वाला है और इन प्रोडक्शन हाउस ने बेहद सफल फिल्में और ओटीटी शो दिए हैं लेकिन इनके लिए भी सतत विकास को बरकरार रखना चुनौतीपूर्ण है। अगर आप जियो स्टूडियोज जैसे बड़ी कंपनी का हिस्सा नहीं हैं तब फिल्म कारोबार में हिट और फ्लॉप की स्वाभाविक प्रक्रिया के चलते वृद्धि की रफ्तार को स्थिर रखना असंभव है। इसकी वजह यह भी है बाजार में बदलाव आ रहा है।

आलम यह है कि इन दिनों फिल्में (कुल कमाई: 19,700 करोड़ रुपये), स्ट्रीमिंग (31,000 करोड़ रुपये) और टेलीविजन (70,000 करोड़ रुपये) के दर्शकों की तादाद बढ़ रही है। हालांकि कंपनियों के बीच विलय आदि की वजह से पेशेवर तरीके से तैयार किए गए शो और सीरीज के लिए खरीदारों की संख्या कम हो गई है। बड़े खरीदारों में पीवीआर-आईनॉक्स, रिलायंस-डिज्नी, नेटफ्लिक्स और एमेजॉन प्राइम वीडियो शामिल हैं। अन्य बड़े खिलाड़ियों में यूट्यूब और मेटा हैं जिन्हें प्रोडक्शन हाउस की जरूरत ही नहीं है बल्कि वे उपयोगकर्ताओं द्वारा तैयार सामग्री के अरबों घंटे का इस्तेमाल करते हैं।

खरीद के लिए कम खिलाड़ियों के रहने का अर्थ यह है कि लागत, रचनात्मक स्वतंत्रता पर दबाव पड़ेगा और साथ ही फिल्में या शो बेचने के लिए विकल्पों की कमी होगी। इसी वजह से पैमाना बड़ा होना महत्त्वपूर्ण है। यह इस कारोबार की अनिश्चितता में बचाव का काम करता है। इसके साथ ही यह प्रोडक्शन कंपनी भी मोल-तोल करने की बेहतर स्थिति में होती है। लेकिन रचनात्मक कारोबार को बढ़ाना वैश्विक स्तर पर मुश्किल है और इसके लिए पैसा जुटाना भी आसान नहीं है। पूनावाला जैसे रणनीतिक निवेशक न केवल पूंजी लाते हैं बल्कि वे रचनात्मक स्वतंत्रता भी देते हैं। वास्तव में भारतीय सिनेमा को उनके जैसे निवेशकों की जरूरत है।

पुराने दौर में जब राजा और रानी का शासन होता था तब प्रदर्शन वाली कलाओं और उनके कलाकारों के संरक्षण का महत्त्व हुआ करता था। लेकिन वक्त के साथ-साथ इसमें भी बदलाव आता गया। एक वक्त ऐसा भी था जब भारतीय फिल्म कारोबार में सक्षम स्टूडियो तंत्र हुआ करता था लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह खत्म हो गया। उसके बाद से ही फिल्मकारों को फंडिंग के बेहतर स्रोत के लिए संघर्ष करना पड़ा। जहां तक समानांतर सिनेमा की बात है, उसे राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम जैसे संस्थानों और मनमोहन शेट्टी जैसे लोगों का संरक्षण मिला। एडलैब्स के संस्थापक शेट्टी ने चक्र (1981), अर्द्ध सत्य (1983) और हिप-हिप हुर्रे (1984) जैसी फिल्में बनाकर समानांतर सिनेमा का समर्थन किया। बाकी लोगों ने बिल्डरों और कारोबारियों से मदद लेना शुरू किया। 1980 के खराब दौर के समय सिनेमा कारोबार में अंडरवर्ल्ड का पैसा भी आया।

वर्ष 2000 में फिल्मों को उद्योग का दर्जा मिलने के बाद इन चीजों में काफी बदलाव आया। सार्वजनिक सूचीबद्धता (एडलैब्स, बालाजी, मुक्ता), प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल या बैंकों के जरिये पैसे जुटाना संभव हो गया। वर्ष 2008 के बाद विदेशी स्टूडियो मसलन फॉक्स, इरोस और डिज्नी ने भारत में कदम रखा। वहीं दूसरी ओर फिल्म उद्योग के रिटेल कारोबार (मल्टीप्लेक्स) में भी पूंजी निवेश हुआ और इसमें वृद्धि देखी गई। लेकिन सामग्री में निवेश करने वाली पूंजी को संघर्ष करना पड़ा क्योंकि कारोबार नया था। लेकिन इस चरण के चलते ही ऐसी व्यवस्था बनी कि प्रोडक्शन हाउस 2016 के बाद के दौर में ओटीटी के उभार के लिए तैयार दिखे।

पूंजी जुटाने का यह दौर, वृद्धि की संभावनाओं को लिए अच्छा संकेत है ताकि इस उद्योग के कारोबार की चुनौतियों का प्रबंधन किया जा सके। ऐसा भी हो सकता है कि आधा दर्जन प्रोडक्शन हाउस को एक प्राइवेट इक्विटी समर्थित एग्रीगेटर कंपनी में बदलने की बात हो। डिज्नी के दिग्गज केविन मेयर द्वारा स्थापित और संचालित ब्लैकस्टोन समर्थित लॉस एंजलिस की कंपनी कैडल मीडिया भी ऐसा करती है। पूनावाला जैसे निवेशक भी समान तरीके से एक्सेल और रॉय-कपूर फिल्म्स से लेकर अपलॉज और अर्का मीडिया वर्क्स को एक साथ मिलाने की कोशिश कर सकते हैं और इसका दायरा बढ़ने पर छोटी प्रोडक्शन कंपनियों को मोल-भाव करने की ताकत मिल सकती है।

आपका पक्ष

सौर और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना जरूरी

सरकार की तरफ से परंपरागत ऊर्जा की जगह हरित ऊर्जा (ग्रीन एनर्जी) को बढ़ावा देने के प्रयास के नतीजे अब दिखने लगे हैं। अब सबकुछ ठीक रहा तो वर्ष 2030 तक पेट्रोल-डीजल जैसे जीवाश्म ईंधन के आयात में गिरावट से एक लाख करोड़ रुपये तक की बचत का अनुमान लगाया गया है। इस अवधि तक कार्बन उत्सर्जन में भी सालाना पांच करोड़ टन की कमी आएगी। वित्त मंत्रालय की आर्थिक समीक्षा के अनुमान के मुताबिक वर्ष 2030 तक देश में ग्रीन हाइड्रोजन की उत्पादन क्षमता 50 लाख टन तक हो जाएगी। जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी के साथ इसके आयात को घटाने के उद्देश्य से पिछले साल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया था। भारत अपनी जरूरत का 80 प्रतिशत पेट्रोल-डीजल का आयात करता है। हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार फास्टर एडॉप्शन ऐंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल (फेम) योजना लेकर आई थी, जिसकी मदद से दो पहिया वाहनों की कुल बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 6 प्रतिशत से अधिक हो गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोत्साहन के लिए गत दिसंबर तक देश भर में 10,000 चार्जिंग स्टेशन की स्थापना की गई। देश भर में मेट्रो का जाल 450 किलोमीटर तक पहुंच गया है। सौर ऊर्जा के उत्पादन क्षमता में वर्ष 2014 के मुकाबले 25 गुना बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2014 में इसकी उत्पादन क्षमता सिर्फ 2,600 मेगावॉट थी, जो नवंबर 2023 में 76,000 मेगावॉट हो गई। गैर जीवाश्म बिजली उत्पादन की क्षमता पिछले नौ वर्षों में बढ़कर 1.87 लाख मेगावॉट तक पहुंच गई है। यह एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है।

सुधीर कुमार सोमानी, देवास

गैर जीवाश्म बिजली उत्पादन की क्षमता पिछले नौ वर्षों में बढ़कर 1.87 लाख मेगावॉट तक पहुंच गई है

जागरूकता के साथ सुरक्षा कर्मियों को बढ़ाने की जरूरत

आग हादसों को रोकने के लिए जागरूकता की विशेष आवश्यकता है। अग्नि सुरक्षा के उपायों को विद्यालयों-महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। शासन के स्तर पर नियम-कानून की कमी नहीं है। लेकिन उनके प्रभावी क्रियान्वयन की जरूरत है। प्रत्येक राज्यों में अग्नि सुरक्षा से जुड़े विभाग के सृजन और अग्नि सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। जिससे हादसों की स्थिति में तत्काल स्थिति को नियंत्रित किया जा सके।

कृष्ण चंद्र त्रिपाठी, रीवा

सावधानी से हादसों पर नियंत्रण संभव

अधिकांश आग हादसे मानव की त्रुटि या लापरवाही के कारण होते हैं। इसलिए सतर्कता और सावधानी से इन्हें रोका जा सकता है। ज्वलनशील पदार्थों को सुरक्षित स्थान पर रखते हुए उनकी नियमित देखरेख करना भी जरूरी है। विद्युत जनित आग हादसों को रोकने के लिए कार्यालयों, कारखानों, अस्पतालों, सभागृहों आदि में शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले विद्युत तारों का प्रयोग करना चाहिए। सभी सार्वजनिक स्थल और वाहनों में अग्निशमन यंत्र लगाते हुए उनके प्रयोग विधि से सभी को अवगत कराना चाहिए।

प्रणिता चोरडिया, लोनावला

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

मुंबई में 26/11 आतंकी हमले की बरसी पर मंगलवार को गेटवे ऑफ इंडिया के पास लोगों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। नवंबर 2008 में पाकिस्तान से समुद्र के रास्ते आए आतंकवादियों ने मुंबई में 60 घंटे की घेराबंदी के दौरान गोलीबारी कर 166 लोगों की हत्या कर दी थी। सुरक्षा बलों ने नौ आतंकवादियों को मार गिराया, जबकि एकमात्र जीवित पकड़े गए हमलावर अजमल कसाब को नवंबर 2012 में फांसी दी गई।

कल्पमेधा

दौलत से आदमी को जो सम्मान मिलता है, वह उसका नहीं, उसकी दौलत का सम्मान होता है।

- मुंशी प्रेमचंद

प्रदूषण की दुश्वारियां

पिछले कई दिनों से राजधानी दिल्ली की हवा कैसी है, यह जगजाहिर है। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि प्रदूषण में लगातार बढ़ोतरी की वजह से यहां प्रतिबंधों के स्तर को और ज्यादा सख्त करने की जरूरत पड़ रही है। इसके बावजूद दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कोई राहत मिलती नहीं दिख रही। हवा में घुले धुएं और धुंध की वजह से लोगों की परेशानियां कम नहीं हो रहीं हैं, सेहत के सामने कई तरह की मुश्किलें गहरा रही हैं। इस मसले पर शीर्ष अदालत तक को सख्ती बरतने का आदेश जारी करना पड़ा है और उसने प्रदूषण पर काबू पाने के लिए लागू किए गए उपायों की निगरानी करने की भी जरूरत बताई है। लगातार बढ़ती मुश्किलों के मद्देनजर इस उम्मीद में दिल्ली में ग्रैप-4 के नियम लागू किए जा चुके हैं कि प्रदूषण से उपजी स्थिति में कुछ सुधार होगा। मगर सरकार की ओर से तमाम उपायों को सख्ती से लागू करने के दावे के बरक्स हकीकत यह है कि राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक चार सौ से ऊपर दर्ज किया गया।

गौरतलब है कि ग्रैप-4 के तहत दिल्ली में बाहर से आने वाले वाहनों के सीमित प्रवेश को लेकर जो नियम लागू किए गए हैं, उनके सख्ती से पालन को लेकर कई सवाल उठे हैं। वाहनों के दिल्ली में दाखिल होने की जगहों पर सख्त निगरानी लागू करने पर जोर देने से लेकर कृत्रिम बारिश कराने तक पर विचार किया जा रहा है। मगर इस क्रम में नियमों के असर और उनके विरोधाभास को लेकर भी ऊहापोह की स्थिति बन रही है। प्रदूषण की रोकथाम के मद्देनजर पहले ही दिल्ली में पेट्रोल और डीजल से चलने वाली कारों के लिए क्रमशः पंद्रह और दस वर्ष की सीमा तय की गई है। मगर फिलहाल बाहर से दिल्ली में प्रवेश करने वाली गाड़ियों को जिस तरह प्रतिबंधित किया गया है, उसमें इससे कम अवधि वाले वाहन भी प्रभावित हो रहे हैं। दिल्ली में आवाजाही के लिए सार्वजनिक परिवहन की हालत यह है कि बसों से गंतव्य तक सही समय पर पहुंचना संभव नहीं रह गया है। वहीं मेट्रो भी अब समय और जरूरत के तकाजे के बोझ से दब रही है।

सवाल है कि इस वर्ष फिर ठंड की आहट के साथ ही प्रदूषण की वजह से उपजी समस्या के गहराते जाने के बाद दिल्ली सरकार ने जो शुरुआती उपाय किए, उससे राहत क्यों नहीं मिली! अब ग्रैप-4 के भी नियम लागू किए जाने के बावजूद राजधानी की हालत ऐसी क्यों बनी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट को भी स्कूलों के संचालन और अन्य स्तर पर नियंत्रण को लागू करने की हिदायत देनी पड़ी है। प्रदूषण का जो स्तर बना हुआ है, उस पर काबू पाने के लिए हर उचित उपाय किए जाने चाहिए। इससे किसी को असहमति नहीं होगी। मगर क्या इस क्रम में ऐसी स्थिति पैदा होनी चाहिए कि उन उपायों से आम लोगों को राहत मिलने के बजाय उनकी परेशानियों में इजाफा ही हो जाए। दिल्ली में वायु गुणवत्ता की दशा जिस पैमाने तक पहुंच गई है, उसमें बाहर से आने वाले वाहनों के यहां सीमित प्रवेश को लेकर लागू नियम का अपना महत्त्व हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद अगर दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक में कोई सुधार नहीं हो रहा है, तो इसकी क्या वजहें हैं? प्रदूषण से निपटने के वास्तविक उपायों को लागू करने के मोर्चे पर निरंतरता सुनिश्चित किए बिना तात्कालिक सख्तियों से कितनी राहत मिल सकेगी?

युद्ध के विरुद्ध

युद्ध का मैदान अंतिम तौर पर किसी ठोस समाधान की ओर नहीं ले जाता। इसका दूरगामी प्रभाव आसपास के देशों पर ही नहीं, पूरे विश्व पर पड़ता है। इतनी प्रगति का क्या फायदा, जब कोई देश युद्ध को लेकर अत्यधिक आक्रामक होकर दूसरे देशों के लोगों और यहां तक कि अपने नागरिकों का भी भविष्य रसातल में ले जाए। यह दुखद है कि दुनिया आज भी युद्ध के भयावह मंजर देख रही है। एक दूसरे पर महीनों से हमले कर रहे देशों को रोक पाने में संयुक्त राष्ट्र भी असहाय है। हैरत की बात है कि संवाद और कूटनीति के इस दौर में आज चंद देश प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से युद्ध कर रहे हैं, बिना यह सोचे कि उनकी पीढ़ियां दशकों पीछे चली जाएंगी। विश्व में लगातार बढ़ते संघर्ष के बीच भारत ने एक बार फिर शांति के प्रति अपना सरोकार जाहिर किया है। उसने याद दिलाया है कि युद्ध से कोई ठोस हल नहीं निकलता। रोम में 'एमईडी मेडिटेरेनियन संवाद' के दसवें संस्करण में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पश्चिम एशिया में द्वि-राष्ट्र का समर्थन करते हुए स्पष्ट किया है कि सैन्य अभियानों में बड़े पैमाने पर नागरिकों की मौत को भारत अस्वीकार्य मानता है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों की अवहेलना नहीं की जा सकती। इजराइल-फिलस्तीन संघर्ष और रूस-यूक्रेन युद्ध में हजारों नागरिक मारे जा चुके हैं। भारी तबाही के दृश्यों ने पूरे विश्व को विचलित कर दिया है। पश्चिम एशिया लंबे समय से संघर्ष का दौर देख रहा है। इससे किसी पक्ष का पलड़ा भारी होता दिखा हो सकता है, लेकिन इससे जन-धन की भारी क्षति हुई। खासतौर पर कमजोर पड़ने वाले देश की वर्षों और दशकों के विकास की उपलब्धियां बर्बाद हो गईं। ऐसे में युद्धविराम की आवश्यकता हर कोई महसूस कर रहा है। भारत ने इसकी पुरजोर हिमायत की है, क्योंकि संयम बरत कर और परस्पर संवाद को आगे बढ़ाते हुए ही युद्ध क्षेत्र से बाहर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। भारत ने संकेत दिया है कि वह अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक प्रयास के लिए सार्थक योगदान देने के लिए तैयार है। पश्चिम एशिया में तत्काल संघर्षविराम कराने के लिए कुछ बड़े देशों को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि शांति कायम होने से ही दुनिया आगे बढ़ेगी।

बांग्लादेश की कूटनीति और भारत

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अपनी विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव कर पाकिस्तान के साथ सामरिक, राजनीतिक और नागरिक संबंधों को प्राथमिकता से बहाल कर दिया है। भौगोलिक, आर्थिक और सामरिक दृष्टि से यह स्थिति भारत के लिए चुनौतीपूर्ण है।

ब्रह्मदीप अलूने

राजनीतिक बदलाव किसी देश के राजनीतिक निर्णयों, रणनीतियों और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं, इसका उदाहरण बांग्लादेश है। शेख हसीना की सरकार के तख्तापलट के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अपनी विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव कर पाकिस्तान के साथ सामरिक, राजनीतिक और नागरिक संबंधों को प्राथमिकता से बहाल कर दिया है। भौगोलिक, आर्थिक और सामरिक दृष्टि से यह स्थिति भारत के लिए चुनौतीपूर्ण है। इसके दूरगामी परिणाम बेहद घातक हो सकते हैं।

दरअसल, बांग्लादेश भारत का महत्त्वपूर्ण भू-राजनीतिक सहयोगी है। इसकी भूमि तीन ओर से भारत की सीमाओं से घिरी है और चौथी ओर बंगाल की खाड़ी है। बांग्लादेश म्यांमा और भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है। उसकी सीमा भारत के असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण, बांग्लादेश दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक प्राकृतिक कड़ी है। वहीं भारत ने एक दशक पहले 'एक्ट ईस्ट नीति' की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र स्थित देशों के साथ आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाना तथा चीन का मुकाबला करना था। बांग्लादेश इस नीति का एक स्वाभाविक स्तंभ है। अपनी भू-राजनीतिक स्थिति के कारण बांग्लादेश दक्षिण पूर्व एशिया और उससे आगे के देशों के साथ आर्थिक और राजनीतिक संबंधों के लिए एक पुल का काम करता है। बांग्लादेश रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्गों के निकट है तथा दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है।

सुरक्षा की दृष्टि से भारत के पूर्वोत्तर के राज्य बेहद संवेदनशील माने जाते हैं। शेख हसीना के डेढ़ दशक के कार्यकाल में भारत और बांग्लादेश के मजबूत संबंधों के कारण इन क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास और एकीकरण को बढ़ावा मिला तथा विकास का मार्ग भी प्रशस्त हुआ था। इस दौरान पूर्वोत्तर को आसियान के लिए अपना रणनीतिक प्रवेश द्वार बनाने के लिए भारत के प्रयास तेजी से चल रहे थे। 'एक्ट ईस्ट नीति' में आसियान और व्यापक हिंद-प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ कई स्तरों पर पहल की परिकल्पना की गई है। इन पहलों को द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय स्तरों पर निरंतर जुड़ाव की प्रक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ाया जाना है, जिससे राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंधों सहित व्यापक अर्थों में बेहतर संपर्क प्रदान किया जा सके। भारत के पूर्वोत्तर को सुरक्षा और आर्थिक दृष्टि से बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंधों से लाभ हुआ और पिछले डेढ़ दशक में पूर्वोत्तर में उग्रवाद कम हुआ। जबकि उत्तर-पूर्व से लगते म्यांमा में अशांति का प्रभाव भारत की कई महत्त्वाकांक्षी परियोजनाओं पर पड़ा है।

भारत, बांग्लादेश और म्यांमा के सहयोग के बिना 'एक्ट ईस्ट नीति' का सफलतापूर्वक संचालन नहीं कर सकता। म्यांमा में अस्थिरता के बाद भी भारत जुंटा सरकार के लगातार संपर्क में रही, लेकिन अब स्थितियां यहां भी भारत के नियंत्रण के बाहर होने की आशंका बढ़ गई है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच समुद्र के रास्ते व्यापार शुरू होना और पाकिस्तान के जहाज का चटगांव बंदरगाह पर आना भारत की रणनीतिक योजनाओं के लिए नई चुनौती के संकेत हैं। चटगांव बंदरगाह सामरिक रूप से भी बेहद अहम है। पूर्वोत्तर के उग्रवादियों की शरणस्थली और हथियारों की आपूर्ति के लिए कुख्यात रहा म्यांमा, चटगांव बंदरगाह से ज्यादा दूर नहीं है। यह बंदरगाह बंगाल की खाड़ी के जरिए पूर्वोत्तर भारत के प्रवेश द्वार के तौर पर काम करता है। यहां तक कि पाकिस्तानी जहाजों की नियमित आवाजाही इलाके की भू-राजनीति पर असर डाल सकती है। चीन, बांग्लादेश का एकमात्र सहयोगी देश है, जिसके साथ उसका रक्षा सहयोग समझौता है। चीन रक्षा क्षेत्र में बांग्लादेश का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है।

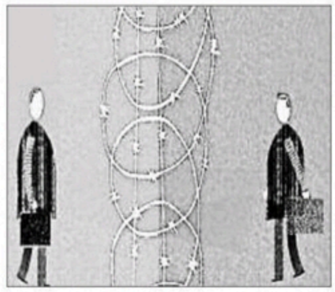

> पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बनने और भारत और बांग्लादेश के बीच मजबूत रिश्तों के रहते पाकिस्तान की खुफिया एजंसी भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में मजबूत नहीं हो सकी। इस कारण भारत की आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करने का चीन का मंसूबा भी कामयाब नहीं हो सका। पूर्वोत्तर के राज्यों की आर्थिक और जातीय समस्याएं भारत के लिए सुरक्षा का संकट बढ़ाती रही हैं। इन राज्यों के अलगाववादी आंदोलन पूरी तरह खत्म नहीं हो पाए हैं। बांग्लादेश से भारत में अवैध आप्रवासन को रोकना बेहद चुनौतीपूर्ण रहा है। कुकी, चिन और लुसाई जनजाति का पारंपरिक निवास स्थान तीन देशों की सीमाओं में बंटा है।

'एक्ट-ईस्ट नीति' मुख्य रूप से आसियान देशों ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमा, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, जापान, दक्षिण कोरिया, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सहित एशिया प्रशांत क्षेत्र के अन्य देशों को लक्षित करती है। बांग्लादेश दक्षिणपूर्व एशिया के साथ अपने संबंध मजबूत करने के लिए थाईलैंड से मदद की उम्मीद कर रहा है। वहीं थाईलैंड भारत के साथ सीधा संपर्क चाहता है। बांग्लादेश के दक्षिणपूर्वी तट पर स्थापित चटगांव देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। बांग्लादेश का नब्बे फीसद समुद्री व्यापार इसी बंदरगाह की जरिए होता है। चटगांव बंगाल की खाड़ी का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। रानोंग पोर्ट अंडमान सागर में थाईलैंड का इकलौता बंदरगाह है, जो इसे बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है। थाईलैंड रानोंग पोर्ट को इसलिए विकसित कर रहा है, जिससे वह दूसरे तटीय देशों, खासकर भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह से सीधे जुड़ सके। थाईलैंड के लिए चटगांव बंदरगाह से सीधे जुड़ाव का मतलब यह हुआ कि वह नेपाल, भूटान और पूर्वोत्तर भारत के साथ अपने व्यापार को सुधार सकता है।

बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव के बाद भारत की भविष्य की परियोजनाओं और बांग्लादेश में किए गए व्यापक निवेश पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी से मजबूत संबंध हैं। बीएनपी को भारत विरोधी समझा जाता है। 2004 में बीएनपी के शासनकाल में हथियारों और गोला-बारूद की अब तक की सबसे बड़ी खेप जब्त की गई थी। भारत अपने पूर्वोत्तर इलाके के सात राज्यों की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहा है। इस घटना के कुछ दिनों पहले भूटान में चलाए गए अभियान 'आल क्लीयर' के दौरान उल्फा के हथियारों के भंडार को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया था।

बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच मजबूत रिश्तों का असर म्यांमा पर भी पड़ सकता है। चीन की मदद से पाकिस्तान और म्यांमा के बीच सैन्य उद्योग में साझेदारी बढ़ी है। म्यांमा अपनी सैन्य ताकत बढ़ाना चाहता है तथा वह पाकिस्तान के साथ अपनी सैन्य साझेदारी बढ़ा रहा है। पाकिस्तान और म्यांमा की सेना के प्रतिनिधिमंडलों ने एक-दूसरे देश की यात्रा की है। चीन पाकिस्तानी सैन्य उद्योग के जरिए अपने हथियार बेचना चाहता है। पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों ने म्यांमा की सेना को हथियारों के उत्पादन में तकनीकी मदद भी की है। म्यांमा की सीमा पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों से सटी हुई है। चीन म्यांमा आर्थिक गलियारा भी भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है।

पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बनने और भारत और बांग्लादेश के बीच मजबूत रिश्तों के रहते पाकिस्तान की खुफिया एजंसी भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में मजबूत नहीं हो सकी। इस कारण भारत की आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करने का चीन का मंसूबा भी कामयाब नहीं हो सका। पूर्वोत्तर के राज्यों की आर्थिक और जातीय समस्याएं भारत के लिए सुरक्षा का संकट बढ़ाती रही हैं। इन राज्यों के अलगाववादी आंदोलन पूरी तरह खत्म नहीं हो पाए हैं। बांग्लादेश से भारत में अवैध आप्रवासन को रोकना बेहद चुनौतीपूर्ण रहा है। कुकी, चिन, लुसाई जनजाति का पारंपरिक निवास स्थान तीन देशों की सीमाओं में बंटा है। बांग्लादेश से पाकिस्तान के मजबूत होते संबंधों के कारण आइएसआइ भारत के पूर्वोत्तर के विभिन्न जातीय समूहों और अलगाववादी तत्वों को भारत के खिलाफ अपनी साजिशों का हिस्सा बना सकती है। बांग्लादेश और म्यांमा की सीमा से भारत में आतंकवादियों का प्रवेश, मादक द्रव्यों की तस्करी, मानव तस्करी और जाली मुद्रा के अवैध कारोबार को रोकना एक बड़ी चुनौती होगा।

विकल्पों का मायाजाल

मुनीष भाटिया

दुनिया मेरे आगे

उद्देश्य निर्धारण केवल एक मानसिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारी आंतरिक और बाहरी दुनिया के बीच एक सेतु की तरह काम करता है। जब हम कोई ठोस निर्णय लेते हैं, तो हमारी ऊर्जा उसी दिशा में प्रवाहित होने लगती है और धीरे-धीरे परिस्थितियां भी हमारे संकल्प के अनुसार ढलने लगती हैं। संकल्प शक्ति हमें यह भी सिखाती है कि व्यक्ति अपनी इच्छाशक्ति और कर्म के माध्यम से अपनी परिस्थितियों को बदल सकता है। इसमें वह बल है जो असंभव को भी संभव बना सकती है, बशर्ते हमारा विश्वास और प्रयास दृढ़ हो। जीवन में हम अक्सर किसी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं और इसके लिए हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं। लेकिन केवल यही पर्याप्त नहीं है, उसकी प्राप्ति के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति अत्यंत आवश्यक है। यही शक्ति हमारे लक्ष्य को वास्तविकता में बदलने का मार्ग प्रशस्त करती है। बिना दृढ़ इच्छाशक्ति के चाहे लक्ष्य कितना भी बड़ा या सुंदर क्यों न हो, हम उसे हासिल नहीं कर सकते। संकल्प वह ऊर्जा है जो हमें कठिनाइयों का सामना करने और उन्हें पार करने का साहस देता है। यह हमें अपने मार्ग पर अडिग रहने और निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा देता है। यही ऊर्जा हमें जीवन की चुनौतियों से लड़ने का साहस और धैर्य प्रदान करती है।

जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, तब हमारी इच्छाशक्ति हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाए रखती है। यह हमें याद दिलाती है कि हर चुनौती एक अवसर है और हर रुकावट हमारे लिए परीक्षा है। इस परीक्षा में वही सफल होते हैं, जिनका संकल्प मजबूत होता है और जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं। इस मनोभाव के बिना कोई भी बड़ा कार्य अधूरा रह जाता है, जबकि दृढ़ संकल्प हमें असंभव को भी संभव करने की क्षमता प्रदान करता है। यही कारण है कि संकल्प को सफलता की कुंजी माना गया है। उद्देश्य प्राप्ति का यह आंतरिक बल वास्तव में एक ऐसा साधन है, जो हमें जीवन में न केवल उद्देश्य देता है, बल्कि उस उद्देश्य को पाने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन और दृढ़ता भी प्रदान करता है। सही दिशा में केंद्रित जीवन-ऊर्जा ही किसी भी कार्य को पूर्णता तक ले जाती है। इसके बिना हमारे विचार और कर्म अनियंत्रित रहते हैं, जैसे बिना पतवार के नाव, जो किसी भी दिशा में बहक सकती है। दरअसल, संकल्प इच्छाशक्ति या मनोबल से आगे वह ऊर्जा है जो जीवन के हर पहलू में एकजुटता और संतुलन लाने का कार्य करता है। यह हमें अपने सपनों और लक्ष्यों को हकीकत में बदलने की शक्ति देता है।

जीवन में जब संकल्प मन में रखा जाता है, तो शरीर अनायास उस दिशा में आगे बढ़ने लगता है। आज के जटिल और व्यापक संसार में संकल्प के सामने अनेक विकल्प उभरने लगते हैं, जो हमें एक विशिष्ट दिशा में चलने से विचलित कर सकते हैं। जैसे-जैसे हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, संकल्प के रास्ते में कई तरह के विकल्प खुलने लगते हैं। यह विकल्पों का जाल हमारे संकल्प को कमजोर कर सकता है या उसे और दृढ़ बना सकता है। यह इस पर निर्भर करता है कि हम किस विकल्प को चुनते हैं और कितना अडिग रहते हैं। यह भी महत्त्वपूर्ण है कि आज के समय में हम अक्सर संकल्प और विकल्पों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। हम किसी एक दिशा में संकल्पित होने से पहले यह देखने लगते हैं कि हमारे पास कितने और विकल्प उपलब्ध हैं। विकल्पों की अधिकता कभी-कभी हमारे विचारों के डगमगाने का कारण बन जाती है, क्योंकि हमें यह भ्रम होता है कि शायद दूसरा विकल्प बेहतर होगा।

आज जब हमारे पास विकल्पों की भरमार है, यह सचमुच चुनौतीपूर्ण हो जाता है कि हम किसी एक दिशा में दृढ़ता के साथ संकल्पित रह सकें। विकल्पों की अधिकता अक्सर हमें एक प्रकार के मानसिक असमंजस में डाल देती है, जहां हम तय नहीं कर पाते कि कौन-सा रास्ता सर्वोत्तम होगा। यह स्थिति हमें अस्थिर बना देती है और हमारी ऊर्जा बिखरने लगती है। ऐसे में हमारा संकल्प एक स्पष्ट दिशा में न जाकर भटकाव का शिकार हो जाता है, क्योंकि हम विभिन्न विकल्पों के बीच बार-बार उलझते रहते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक चुनौती है, जिसे हम 'विकल्पों का भ्रम' कह सकते हैं। जब हमें कई विकल्पों का सामना करना पड़ता है, तो हम यह सोचते हैं कि शायद हमने सही विकल्प नहीं चुना। इस संदेह के कारण हम अपने संकल्प से दूर हो जाते हैं और किसी दूसरे विकल्प की ओर आकर्षित हो जाते हैं। सच्चाई यह है कि कोई भी विकल्प बिना पूरी निष्ठा और समर्पण के सही नहीं हो सकता। एक मजबूत संकल्प की जरूरत होती है कि वह हमें मार्ग पर टिकाए रखे।

> आज जब हमारे पास विकल्पों की भरमार है, यह सचमुच चुनौतीपूर्ण हो जाता है कि हम किसी एक दिशा में दृढ़ता के साथ संकल्पित रह सकें। विकल्पों की अधिकता अक्सर हमें एक प्रकार के मानसिक असमंजस में डाल देती है, जहां हम तय नहीं कर पाते कि कौन-सा रास्ता सर्वोत्तम होगा।

इसलिए सफल होने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने संकल्प को विकल्पों के भ्रम से ऊपर रखें और पूरी एकाग्रता और विश्वास के साथ उसे निभाएं। यह हमें असमंजस से बचाकर हमारे लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ने में मदद करता है। यह दृढ़ निश्चय हमें न केवल बाहरी परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति देता है, बल्कि आंतरिक संघर्षों से भी उबरने में मदद करता है। सफलता की यात्रा में कई बार हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पूरी एकाग्रता और अटूट विश्वास ही हमें मार्ग में आने वाली हर रुकावट को पार करने का साहस देता है। इसलिए अगर हम अपने संकल्प के प्रति पूरी निष्ठा से समर्पित रहते हैं और विकल्पों के भ्रम से खुद को मुक्त रखते हैं, तो हमारी ऊर्जा केंद्रित रहती है। यही केंद्रित ऊर्जा हमें निरंतर प्रयास करने और अपने लक्ष्य की ओर बिना किसी विचलन के बढ़ने में सहायता करती है। सफलता उन्हीं के पास आती है, जो न केवल अपने संकल्प को दृढ़ रखते हैं, बल्कि उसे पूरे धैर्य के साथ निभाते भी हैं।

सावधानी का तकाजा

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हर साल सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण बढ़ जाता है। वायु गुणवत्ता की चुनौती हर बार सामने आती है। वायु प्रदूषण के मुख्य कारणों में पराली जलाना तो है ही, वाहनों से निकलने वाला धुआं और पटाखे भी हैं। सर्द हवाएं और कोहरा मिल कर प्रदूषण की सघनता बढ़ा देते हैं। इस प्रदूषण का प्रभाव आम जनता पर पड़ता है, विशेष रूप से अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियों से पीड़ित लोगों पर। बच्चों और बुजुर्गों की स्थिति तेजी से बिगड़ जाती है। इसके साथ ही, धुंध के कारण सड़क दुर्घटनाएं भी बढ़ती हैं। प्रदूषण का नकारात्मक असर न केवल मानव जीवन पर बल्कि पेड़-पौधों और अन्य जीवों पर भी पड़ रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए कई ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। किसानों को तकनीक बता कर उनको पराली जलाने से रोका जा सकता है। इसी तरह सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ाया जाए। पटाखों पर तो पाबंदी लगा कर लोगों को त्योहार मनाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।

- दिव्यांशु खनाल, नोएडा

युद्ध का हासिल

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद रूस-यूक्रेन युद्ध की समाप्ति के आसार बन रहे थे, लेकिन अभी ट्रंप के शपथ ग्रहण में विलंब है। राष्ट्रपति के रूप में अपने आखिरी वक्त में जो बाइडेन ने यूक्रेन को घातक हथियारों से लैस करने का निर्णय किया है। उन्होंने यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल के इस्तेमाल की अनुमति दे दी। अनुमति मिलते ही यूक्रेन ने रूस पर लंबी दूरी की मिसाइल दागी। इसके जवाब में रूस ने भी यूक्रेन पर बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना लगाया। उसने पोलैंड में अमेरिकी अड्डे को निशाना बनाने की भी चेतावनी दी है। दुखद है कि अमेरिका ने कभी भी युद्ध रोकने का प्रयास नहीं किया। युद्ध में सदैव मानवता की हार होती है। युद्ध की विभीषिका में लाखों निर्दोष लोगों की जान चली गई है। इससे पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है और हथियारों की होड़ मच चुकी है। भारत सहित सभी शांतिप्रिय देशों को युद्ध समाप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए।

- हिमांशु शेखर, गया

विचित्र नीलामी

अजीब जमाना आ गया है। वस्तुओं, घरों और कबाड़ आदि को नीलाम होते सुना था, पर अब तो खिलाड़ी 'नीलाम' हो रहे हैं। जैसे खिलाड़ी, वैसे दाम। कोई करोड़ों में जा रहा है, तो कोई लाखों में और कोई हाथ मलते रह जाता है। क्रिकेट मैच के कभी टिकट बिका करते थे जो आज भी जारी है, लेकिन खिलाड़ियों की नीलामी नई खेल-परंपरा ही है। पहले किसी के हाथ किसी व्यक्ति के बिक जाने को बुरा समझा जाता था, पर अब तो उसका स्वरूप बदल गया है। यह बेहिचक कहा जाता है सबसे ज्यादा कीमत फलां खिलाड़ी को मिली और उसके बाद दूसरे, तीसरे। ऐसे घटते क्रम में इनकी नीलामी होती चली जाती है। जिसे ज्यादा पैसे मिले, वह किस्मत वाला और जिसे नहीं मिले, वह खुद को कोसता होगा। सचमुच वक्त बदल गया। कभी घर की नीलामी तक को ठीक नहीं समझा जाता था। अब तो खिलाड़ी को जितनी ज्यादा कीमत मिल जाए, उसे उतना ही विशिष्ट समझा जाने लगा है। सचमुच विचित्र है यह।

- शकुंतला महेश नेनावा, इंदौर

चुनाव की बिसात

महाराष्ट्र की जनता ने विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी के नारों को दरकिनार कर विकास के मुद्दों पर सत्ता के साथ जाना स्वीकार किया। कई दिग्गजों को मात मिली। पहली बार विधानसभा में विपक्ष के नेता का पद नहीं मिल पाएगा। राज्य के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा। वहीं झारखंड में जेएमएम नेता और मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अकेले दम पर भाजपा के कई नेताओं को शिकस्त दी। उन्होंने साबित कर दिया कि वे इस समय आदिवासियों के सबसे बड़े नेता हैं। सोरेन ने झारखंड में आदिवासी-मूलवासी का मुद्दा उठाया और खुद को धरतीपुत्र बताया, जिसमें वे सफल रहे। प्रधानमंत्री सहित भाजपा के कई मुख्यमंत्रियों ने झारखंड में आदिवासियों को रिझाने की पूरी कोशिश की। भाजपा ने जेएमएम के पुराने नेता चंपई सोरेन को भी अपने पाले में खींच लिया, लेकिन फिर भी हेमंत सोरेन को कोई चुनौती नहीं दे पाया।

- युगल किशोर राही, छपरा, बिहार

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

www.readwhere.com

दैनिक जागरण

शांति ही समृद्धि का आधार होती है

हार की खीझ ईवीएम पर

यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के स्थान पर मत पत्र से चुनाव कराने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई। और भी अच्छा होता कि उसकी ओर से इस तरह की याचिकाएं दाखिल करने वालों को हतोत्साहित करने के लिए कुछ कदम उठाए जाते, क्योंकि रह-रहकर ऐसी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होती रहती हैं, जिनमें ईवीएम में कोई न कोई खामी गिनाकर उसे संदिग्ध बताया जाता है। यह सिलसिला थमना चाहिए, क्योंकि कुछ दलों, नेताओं और कथित लोकतंत्र हितैषियों ने ईवीएम को बदनाम करने को अपना पेशा बना लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह सही कहा कि आखिर चुनाव हारने पर ही ईवीएम की शिकायत क्यों की जाती है? यह प्रश्न केवल याचिकाकर्ता के ही इरादों को बेनकाब करने वाला नहीं है, बल्कि उन नेताओं के दुष्प्रचार की पोल खोलने वाला भी है, जो महाराष्ट्र के चुनावों के बाद ईवीएम को लेकर हाय-तौबा मचाने में लगे हुए हैं। यह आश्चर्यजनक है कि जो महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों के आधार पर ईवीएम को दोष दे रहे हैं, वही झारखंड के परिणामों पर मौन साधे हुए हैं। क्या वे यह कहना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में ईवीएम ने सही तरह काम नहीं किया, लेकिन झारखंड में किया? वे महाराष्ट्र में मत पत्रों के जरिये चुनाव की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन यह कहने से बच रहे हैं कि ऐसा ही झारखंड में किया जाना चाहिए।

बीते कुछ वर्षों में ईवीएम को विश्वसनीय बनाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं, लेकिन उस पर हार की खीझ निकालने का सिलसिला थम नहीं रहा है। पहले यह व्यवस्था की गई कि मतदाता को यह दिखे कि उसका वोट उसी प्रत्याशी को ही गया, जिसको उसने दिया है। इसके बाद मतदान पर्ची यानी वीवीपैट की व्यवस्था की गई। फिर एक निश्चित संख्या में वीवीपैट का ईवीएम में दर्ज वोटों से मिलान किया जाने लगा। इस सबके बाद भी सदा असंतुष्ट रहने वालों को चैन नहीं। अब वे यह नई शिकायत लेकर आ गए हैं कि इस्तेमाल के बाद भी ईवीएम की बैटरी 99 प्रतिशत कैसे दिखती है। चुनाव आयोग ने इसका जवाब दे दिया है, लेकिन दुष्प्रचार करने वालों की सेहत पर कोई असर नहीं। इनमें से अनेक वे हैं, जो ईवीएम के स्थान पर मत पत्र को बेहतर बताने में लगे हुए हैं। ऐसे लोग लोकतंत्र के शुभचिंतक नहीं हो सकते, क्योंकि सब जानते हैं कि जब मत पत्र से चुनाव होते थे, तब किस तरह धांधली होती थी। तब मत पत्रों के साथ-साथ मतपेटियों की भी लूट होती थी। कुछ समय पहले बंगाल में पंचायत चुनावों के समय मतपेटियां तालाबों में पाई गई थीं। क्या मत पत्र से चुनाव की वकालत करने वाले ऐसी ही घटनाएं देश भर में देखना चाहते हैं। यदि नहीं तो फिर वे चुनाव प्रक्रिया को बैलगाड़ी युग में क्यों ले जाना चाहते हैं?

दूर हों भ्रांतियां

स्मार्ट मीटर योजना बिहार में प्रभावी ढंग से काम कर रही है। दूसरे राज्यों ने इस माडल को सराहा है और इसे लागू करने के तरीके को समझने के लिए अपने प्रतिनिधिमंडल भी बिहार भेजे हैं। कई राज्य इसकी तर्ज पर अपने यहां इसे जमीन पर उतार रहे हैं। मगर, राष्ट्रीय फलक पर नाम रोशन करने वाली इस योजना को लेकर अपने ही राज्य में कुछ दल एवं संगठन सवाल उठा रहे हैं। यह कहा जा रहा कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं की जेब पर चपत लगाने का काम कर रहा है। हालांकि कई मौकों पर स्मार्ट मीटर के बगल में पुराने मीटर को लगाकर यह साबित किया गया है कि दोनों में समान रूप से खपत का आंकड़ा दर्ज होता है। बिजली की चोरी कर अपने घर को रोशन करने वाले, मीटर में छेड़छाड़ कर अपने उद्योग-धंधों का मुनाफा बढ़ाने वालों की दुकानदारी स्मार्ट मीटर ने बंद कर दी है। ऐसे ही लोग सामान्य लोगों को भड़काते हैं और नए क्षेत्रों में मीटर लगाने के लिए जाने वाले लोगों पर हमले होते हैं। ऐसे स्वार्थी और समाज विरोधी लोगों को पहचान कर कार्रवाई करने की जरूरत है। अच्छी बात है कि बिजली कंपनी ने भी तय किया है कि वह लोगों के बीच जाकर स्मार्ट मीटर के प्रति उनकी भ्रांतियों को दूर करेगी। इस काम को पूरी संजीदगी से किए जाने की जरूरत है। मीडिया के माध्यम से हर जिले में जागरूकता कार्यक्रम करके और चुनिंदा टोल फ्री नंबर जारी करके इस समस्या का हल निकाला जा सकता है। फिर कहीं से शिकायत आए तो उस उपभोक्ता की शंका का समाधान अवश्य हो। स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली कंपनी का घाटा दूर हुआ है और राज्य के कोष पर दबाव घटा है। ऐसे में हर जागरूक नागरिक को इसे लगाना चाहिए, साथ ही इसके खिलाफ लोगों को बरगलाने वालों की शिकायत भी करनी चाहिए।

स्मार्ट मीटर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डालता, इसे समझने और समझाने की जरूरत है

टूट गई कांग्रेस के कायाकल्प की उम्मीद

राहुल वर्मा

हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम कांग्रेस की राजनीतिक संभावनाओं को और कमजोर करने वाले नजर आ रहे हैं

अवधेश राजपूत

हाल में संपन्न महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों के परिणामों का विभिन्न दृष्टिकोणों से विश्लेषण जारी है। इन परिणामों को लेकर यह अवश्य कहा जा सकता है कि ये काफी अप्रत्याशित रहे। दोनों राज्यों में सत्तारूढ़ गठबंधनों ने केवल सत्ता में वापसी ही नहीं की, बल्कि उनकी जीत पहले से भी जोरदार रही। ये चुनाव यह देखते हुए भी अप्रत्याशित कहे जा सकते हैं कि दोनों राज्यों ने करीब छह महीने पहले लोकसभा चुनावों के रुझान को भी पलटने का काम किया। लोकसभा सीटों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र में भाजपा को भारी झटका लगा था, जबकि झारखंड में उसकी स्थिति बढ़िया रही थी। लोकसभा में भाजपा को अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल न होने की एक बड़ी वजह महाराष्ट्र में उसका कमजोर प्रदर्शन भी माना गया। महाराष्ट्र में पिछले दस वर्षों के दौरान बीच के कुछ अंतराल को छोड़कर भाजपा सत्ता पर काबिज रही थी तो कुछ सत्ता विरोधी रुझान का भी उसे सामना करना पड़ रहा था। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार जैसे सहयोगियों के साथ तालमेल को लेकर भी तरह-तरह की खबरें आ रही थीं। मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर जारी मुहिम और ग्रामीण क्षेत्रों में असंतोष एवं कृषि संकट भी सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहा था। इसके बावजूद सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति की ऐसी प्रचंड विजय हुई कि विपक्षी दलों को नेता-प्रतिपक्ष का पद हासिल करने लायक सीटें भी नहीं मिलीं। दूसरी ओर, झारखंड में भाजपा की हार राजनीतिक विश्लेषकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर करने वाली है।

झारखंड की राजनीतिक प्रकृति ऐसी रही कि लगातार दो बार कोई दल चुनाव नहीं जीता और बारी-बारी से सरकार बनाने का रिवाज चला आया है। अक्सर राज्य की जनता ने खंडित जनादेश ही दिया, जिससे वहां जोड़तोड़ की राजनीति को खूब खाद-पानी मिलता रहा। ऐसे रुझानों को पलटते हुए राज्य की जनता ने झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो के नेतृत्व में आइएनडीआइए ने जोरदार जीत दर्ज की है। भाजपा वहां बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा जोर-शोर से उठाने के साथ ही उसे आदिवासी अस्मिता पर संकट के साथ जोड़ रही थी। साथ ही, बाबूलाल मरांडी की वापसी एवं सुदेश महतो के साथ अनुकूल गठजोड़ और चम्पाई सोरेन जैसे झामुमो के दिग्गज को अपने पाले में लाकर भाजपा जीत के प्रति आश्वस्त दिख रही थी। नतीजों ने इन सभी पहलुओं को अप्रभावी कर दिया और झामुमो सत्ता विरोधी रुझान को पलटने में सफल रही।

दोनों राज्यों में सत्तारूढ़ गठबंधन की जीत में महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं के योगदान को सबसे प्रमुख कारक बताया जा रहा है। महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने जहां लाडकी बहिन योजना तो झामुमो सरकार ने मंईयां सम्मान योजना पर बड़ा दांव लगाया। ये दांव कारगर भी रहे। दोनों राज्यों में विपक्षी दलों ने भी ऐसी ही मिलती-जुलती या कई मायनों में उससे भी आकर्षक योजनाओं का वादा किया, लेकिन मतदाताओं ने मौजूदा योजनाओं में ही अपना भरोसा जताया, जिनका उन्हें लाभ मिल रहा था। निःसंदेह दोनों राज्यों के विजयी गठबंधनों में इन योजनाओं की बड़ी भूमिका रही है, लेकिन इतनी व्यापक जीत में केवल कोई एक कारक ही जिम्मेदार नहीं हो सकता। ऐसी जीत में कई कारक एक साथ प्रभावी होते हैं। ऐसे ही एक कारक नैरेटिव की बात करें तो विरोधाभासी रुझान सामने आते हैं। जहां झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा नहीं चल पाया, वहीं महाराष्ट्र में 'बटेंगे तो कटेंगे' और 'एक हैं तो सेफ हैं' जैसे नारे बखूबी चले। विपक्षी धड़े के एक बड़े नेता शरद पवार ने यह स्वीकारोक्ति भी की। ऐसे में इस पर हैरानी होती है कि जिस प्रकृति का नैरेटिव एक राज्य में चला तो वह दूसरे प्रदेश में क्यों प्रभावी नहीं रहा?

इन चुनावों के साथ ही पिछले कुछ चुनावों के परिणामों की प्रकृति भी अप्रत्याशित रही है। ज्यादा पीछे न जाएं तो लोकसभा चुनाव इसके सबसे बड़े उदाहरण रहे, जहां मोदी सरकार की सत्ता में वापसी को लेकर एक प्रकार की सर्वानुमति थी। उसकी संभावित सीटों को लेकर तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन भाजपा को अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल करने में किसी को संदेह नहीं था। परिणाम उसके उलट रहे। इसी तरह, बीते दिनों हरियाणा चुनाव के दौरान लगा कि सत्ता का खेल केवल कांग्रेस को तश्तरी में परोसने की औपचारिकता भर है, लेकिन नतीजों के बाद बड़े-बड़े चुनावी पंडितों को भूमिगत होना पड़ गया। इसी कड़ी में अब झारखंड और महाराष्ट्र का नाम भी जुड़ गया है। अप्रत्याशित चुनावी परिणामों के सिलसिले में एक साझा कारक यह भी उभरता दिख रहा है कि लगभग हर चुनाव से पहले एक पार्टी या गठबंधन के पक्ष में जो माहौल दिखाई पड़ता है, उसके चलते उस पार्टी के नेताओं से लेकर उसके कार्यकर्ताओं और प्रतिबद्ध मतदाताओं में एक प्रकार का अति-आत्मविश्वास भर जाता है, जो अंत में आत्मघाती सिद्ध होता है। चुनावी माहौल समय से पहले परवान चढ़ जाता है और निर्णायक पड़ाव तक आते-आते ठिठक जाता है।

दोनों राज्यों के चुनाव परिणाम का राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य पर असर पड़ना तय है। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र की जीत जहां लोकसभा चुनाव में मिले भाजपा के जख्मों पर मरहम लगाने का काम करेगी, वहीं झारखंड की हार उसे कचोटती भी रहेगी। हालांकि ये नतीजे कांग्रेस के लिए कहीं ज्यादा बड़ा झटका हैं। लोकसभा चुनावों के बाद पार्टी को हरियाणा और महाराष्ट्र में कायाकल्प की उम्मीद थी, लेकिन उसे भारी निराशा हाथ लगी। उसके लिए यह और भी बड़ा झटका है कि अधिकांश सीटों पर सीधे मुकाबले में वह भाजपा से हार गई। चूंकि राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बड़े राज्यों में कांग्रेस पहले से ही हाशिए पर है, ऐसे में ताजा चुनाव परिणाम उसकी राजनीतिक संभावनाओं को और कमजोर करेंगे। झारखंड में भले ही झामुमो गठबंधन जीता हो, लेकिन कांग्रेस वहां 'जहां की तहां' वाली स्थिति में रही। यह काफी कुछ जम्मू-कश्मीर जैसी कहानी है, जहां पार्टी सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा तो है, लेकिन उसकी खुद की राजनीतिक जमीन सिकुड़ गई है। अब दोनों राष्ट्रीय दल दिल्ली और बिहार के विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटेंगे, जहां उन्हें अपनी रणनीति नए सिरे से तय करनी होगी।

(लेखक सेंटर फार पालिसी रिसर्च में फेलो एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

संभल सरीखे विवाद पर होश संभालें

राजीव सचान

यह सामान्य समझ सबको होनी ही चाहिए कि सर्वे मात्र से कोई मस्जिद मंदिर में तब्दील होने वाली नहीं है

मंदिर-मस्जिद विवाद में किसी भी भारतीय नागरिक को इतनी समझ होनी ही चाहिए कि यदि कोई अदालत किसी मस्जिद के सर्वे का आदेश दे देती है तो सर्वे होने मात्र से मंदिर का दावा करने वाले उस पर कब्जा नहीं कर सकते। इसलिए और भी नहीं, क्योंकि 1991 का पूजा स्थल अधिनियम यह कहता है कि सभी धार्मिक स्थल उसी स्थिति में रहेंगे, जैसे वे 15 अगस्त 1947 को थे। यह अधिनियम धार्मिक स्थलों के मामले में यथास्थिति कायम रखने का आदेश देने के साथ ही इसकी भी अनुमति देता है कि किसी स्थल का धार्मिक स्वरूप जानने के लिए उसका सर्वे हो सकता है। इसी के चलते पहले वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर का सर्वे हुआ और फिर धार, मध्य प्रदेश में भोजशाला परिसर का। मथुरा की ईदगाह मस्जिद के सर्वे का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इससे हर कोई परिचित होगा कि ज्ञानवापी और भोजशाला में सर्वे के दौरान वैसा कुछ भी नहीं हुआ, जैसा संभल में हुआ। संभल में इतना अधिक उपद्रव हुआ कि चार लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए, जिनमें कई पुलिसकर्मी भी हैं। संभल में भीषण पत्थरबाजी यही संकेत कर रही है कि उसके लिए पहले से तैयारी की गई थी।

संभल की जामा मस्जिद को लेकर एक अर्से से यह कहा जा रहा है कि यहां पहले भगवान विष्णु के नाम का हरिहर मंदिर था, जिसे बाबर के आदेश पर तोड़कर वहां मस्जिद बनवाई गई। ऐसा कई इतिहासकार भी कहते हैं। मंदिर की जगह मस्जिद का निर्माण कराए जाने के दावे के आधार पर कुछ लोग स्थानीय अदालत गए। 19 नवंबर को अदालत ने सर्वे के आदेश दिए। सर्वे का काम उसी दिन शाम को शुरू हो गया, लेकिन अंधेरा होने के कारण वह पूरा नहीं हो पाया और यह तय हुआ कि आगे फिर किसी दिन होगा। इसे रोकने के लिए ऊपरी अदालत जाने का रास्ता खुला था। लगता है कि उसका सहारा लेने के बजाय कुछ लोगों ने पत्थरबाजी करना बेहतर समझा। पत्थरबाजी के बीच पुलिस के वाहनों को भी निशाना बनाया गया और गोलीबारी भी की गई। पुलिस की मानें तो जो चार लोग मरे, वह उसकी गोली से नहीं मरे। पता नहीं सच क्या है। अब इस पर खूब बहस हो रही है कि हिंसा क्यों

संभल में मस्जिद के सर्वे पर भड़की हिंसा। एएनआइ

हुई और किसने की? शायद इसका पता चल जाए, लेकिन इससे वे वापस नहीं आने वाले, जिनकी जान चली गई। पता नहीं संभल में मस्जिद के सर्वे को लेकर क्या अफवाह उड़ाई गई, लेकिन यह तो साफ ही है कि सर्वे के बाद भी यथास्थिति में कोई बदलाव होने वाला नहीं था। आखिर जब अयोध्या में मंदिर के अकाट्य प्रमाण मिलने के बाद भी ऐसा नहीं हो सका तो भला संभल में कैसे हो जाता? यह एक तथ्य है कि ज्ञानवापी और भोजशाला के सर्वे के बाद भी यथास्थिति कायम है।

संभल में जामा मस्जिद के सर्वे से आपा खोने वालों की आपत्ति का यह एक आधार हो सकता है कि आखिर स्थानीय अदालत के मस्जिद के सर्वे के आदेश पर तुरंत अमल क्यों होने लगा, लेकिन क्या इस आपत्ति का जवाब पत्थरबाजी थी? जामा मस्जिद के सदर जफर अली की मानें तो भीड़ इसलिए भ्रमित हो गई, क्योंकि मस्जिद के सर्वे के क्रम में वजूखाने के हौज का पानी बाहर निकाले जाने से लोगों को लगा कि उसकी खोदाई शुरू हो गई है। यह अजीब और हास्यास्पद है, क्योंकि कथित भ्रमित लोग नकाब पहनकर पत्थरबाजी करते देखे गए। यह पहली बार नहीं, जब सरकार या अदालत के किसी फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतरकर हिंसा की गई हो। नागरिकता संशोधन कानून के मामले में भी ऐसा ही देखने को मिला था। तब सड़कों पर उतरकर बड़े पैमाने पर हिंसा की गई थी, जबकि इस कानून का किसी भारतीय नागरिक से कोई लेना-देना नहीं था। इस हिंसा में सरकारी और गैरसरकारी संपत्ति को आग के हवाले किया गया था और दिल्ली में तो शाहीन बाग इलाके में करीब साल भर तक एक प्रमुख सड़क को घेरकर धरना दिया गया था। यही धरना बाद में दिल्ली में भीषण दंगे का कारण बना, जिसमें 50 से अधिक लोग मारे गए थे।

यह संभव है कि किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय को कोई फैसला रास न आए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वह वैसा करे, जो संभल में किया गया। किसी को भी इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती कि यदि कोई काम उसके मन का न हो तो वह मनमानी करे। मंदिर-मस्जिद विवादों के हल के लिए दो ही उपाय हैं-एक, अदालतों के जरिये और दूसरा, आपसी सहमति के माध्यम से। आपसी सहमति से मंदिर-मस्जिद के विवाद हल हो सकते हैं, इसका प्रमाण है गुजरात का पावागढ़ मंदिर। इस प्राचीन मंदिर के शिखर को 15वीं सदी में आक्रमणकारी सुल्तान महमूद बेगड़ा ने ध्वस्त कर वहां एक पीर की दरगाह बनवा दी थी। दोनों पक्षों के बीच लंबी बातचीत के बाद मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराने की सहमति बनी और इस तरह सैकड़ों साल बाद 2002 में मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराया गया। यह एक तथ्य है कि देश में न जाने कितने मंदिर हैं, जिन्हें आक्रमणकारियों ने ध्वस्त कर वहां मस्जिदें बनवाईं। यह ठीक नहीं होगा कि हर ऐसी मस्जिद को मंदिर में तब्दील करने की कोशिश की जाए। ऐसा तो कुछ चुनिंदा मामलों में ही हो सकता है। जहां ऐसा नहीं हो सकता, वहां साक्ष्यों के आधार पर केवल इतना अंकित कर देना भर पर्याप्त होगा कि पहले यह स्थल एक मंदिर था। देश को आगे बढ़ना है तो उसे मंदिर-मस्जिद विवादों से बाहर निकलना ही होगा।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

जीवन का दर्पण

जीवन को एक दर्पण के रूप में ही देखना चाहिए। यह दृष्टिकोण न केवल हमारे कर्मों के परिणामों को उजागर करता है, अपितु हमारे अंतर्मन की सत्यता को भी परिलक्षित करता है। जीवन में जो भी हमें प्राप्त होता है, वह हमारे अपने आचरण, विचारों एवं भावनाओं का प्रतिबिंब होता है। यदि हम जीवन के प्रति उपेक्षा या अहंकार का प्रदर्शन करते हैं तो जीवन भी हमें वैसा ही लौटाता है। इसके विपरीत, यदि हम जीवन को प्रेम, करुणा और सहानुभूति के साथ अपनाते हैं तो जीवन हमें उसी की अनुकृति में प्रतिफलित करता है। जीवन की इस दर्पण तुल्यता का वास्तविक अर्थ यह है कि हमारे कर्म, विचार और शब्द किसी न किसी रूप में हमारे समक्ष पुनः उपस्थित होते हैं। हमारे द्वारा किए गए हर कार्य की एक अनुगूंज हमारे जीवन के किसी न किसी कालखंड में अवश्य सुनाई देता है। थैकर्ट ने कहा है, 'जीवन एक दर्पण है। यदि आप इसे आंख दिखाएंगे तो यह भी वैसा ही करेगा। यह अभिवादन का उत्तर अभिवादन से देता है।'

जीवन का दर्पण केवल बाहरी आचरण का ही नहीं, अपितु हमारे आंतरिक भावों का भी परावर्तन करता है। यदि हम अपने हृदय में कटुता, द्वेष या ईर्ष्या को पोषित करते हैं तो उसी अनुरूप भावनाएं हमारी परिस्थितियों और संबंधों में परिलक्षित होंगी। वहीं, यदि हम अंतर्मन में प्रेम, शांति और समर्पण का संचार करते हैं तो जीवन हमें उसी प्रकार की परिस्थितियों और संबंधों से अलंकृत करेगा। यह दर्पण एक सतत अभिव्यक्ति का प्रतीक है, जो हमारे प्रत्येक कर्म और विचार को बिना किसी भेदभाव के प्रकट करता है। स्मरण रहे कि नकारात्मकता या अशुद्धता अंततः हमारे ही जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करेगी। इसीलिए कहा गया है कि जैसे आप जीवन को देखेंगे, जीवन भी आपको वैसे ही देखेगा।

नृपेंद्र अभिषेक नृप

अनिवार्य बनेगी पर्यावरण शिक्षा

सुधीर कुमार

देश में पर्यावरण शिक्षा को स्नातक स्तर पर अनिवार्य करना एक दूरगामी और दूरदर्शी निर्णय है

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने स्नातक स्तर पर सभी विषयों के विद्यार्थियों के लिए 'पर्यावरण शिक्षा' को अनिवार्य बनाने के संबंध में निर्देश जारी किया है। इस दिशानिर्देश के अनुसार, सभी संकाय के विद्यार्थियों को स्नातक के दौरान अब अनिवार्य रूप से 160 घंटे की पर्यावरण शिक्षा प्राप्त करनी होगी। इस विषय को पढ़ने से उन्हें चार अतिरिक्त क्रेडिट भी हासिल होंगे। एक विषय के रूप में पर्यावरण शिक्षा की अनिवार्यता से जहां एक ओर युवा पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन संबंधी समस्याओं से अवगत होंगे, वहीं दूसरी ओर वे पर्यावरण संरक्षण के निमित्त संवेदनशील भी होंगे।

पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य बनाने से केवल भूगोल और पर्यावरण विज्ञान विषय के विद्यार्थी ही नहीं, अपितु इंजीनियरिंग, प्रबंधन, वाणिज्य एवं विज्ञान पृष्ठभूमि के युवा भी पर्यावरण संरक्षण संबंधी नीतियों, कर्तव्यों और कौशल को समझ पाएंगे। पर्यावरण संकट ऐसी समस्या है, जिसके समाधान में सभी वर्गों और पृष्ठभूमि के लोगों की भागीदारी अपेक्षित है। आज के युवाओं को न केवल पर्यावरण से जुड़े मुद्दों के प्रति जागरूक होना चाहिए, बल्कि उन समाधानों की भी समझ होनी चाहिए, जो वे अपने स्थानीय परिवेश में लागू कर सकते हैं। पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को इन जटिल समस्याओं से परिचित कराना है, ताकि वे भविष्य में नीतिगत, व्यावसायिक और व्यक्तिगत स्तर पर सही फैसले ले सकें। हालांकि यह शिक्षा महज एक विषय और अंक हासिल करने का माध्यम न बने, बल्कि यह भी कोशिश हो कि इसके माध्यम से देश में पर्यावरण संरक्षण की भावना घर-घर तक पहुंचे। इस पहल की सार्थकता इसी में है कि पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास की अवधारणा की समझ युवाओं में विकसित हो। जलवायु संकट की व्यापकता आज वैश्विक चिंता का विषय बन चुकी है। वनों की अंधाधुंध कटाई, जल एवं वायु प्रदूषण और जैव विविधता का क्षरण जैसी समस्याएं देशों और समाजों को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही हैं। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर पड़ने लगा है। जलवायु संकट के समाधान के बिना देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर रखना मुमकिन भी नहीं है। इस संकट का समाधान सामूहिक प्रयासों में निहित है। इस संदर्भ में पर्यावरण शिक्षा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है।

बहरहाल पर्यावरण शिक्षा को स्नातक स्तर पर अनिवार्य करना एक दूरगामी और दूरदर्शी निर्णय है। यह शिक्षा छात्रों को न केवल पर्यावरणीय मुद्दों की गहन समझ देगी, बल्कि उन्हें उनके समाधान में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए भी प्रेरित करेगी। सुरक्षित एवं स्वस्थ भविष्य के लिए यह एक आवश्यक कदम है।

(लेखक बीएचयू में शोधार्थी हैं)

मेलबाक्स

सराहनीय चिकित्सा सुविधाएं

'मेडिकल टूरिज्म का गढ़ बनता भारत' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में आरके सिन्हा ने चिकित्सा क्षेत्र में भारत के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। भारतीय चिकित्सकों और विदेशों में रह रहे अप्रवासी भारतीय चिकित्सकों ने अपनी प्रतिभा से एक विशिष्ट स्थान बनाया है। यह और भी गर्व की बात है कि विदेशी हस्तियों का भारतीय प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद मे विश्वास बढ़ा है। विकसित देश होने का दंभ भरने वाले देशों मे चिकित्सा सुविधाएं अत्यंत महंगी हैं। अपने डेढ़ महीने के कनाडा प्रवास के दौरान मैंने वहां की खस्ताहाल चिकित्सा सुविधाओं को देखा। वहां स्थिति यह है कि आपको चिकित्सा की आवश्यकता अभी है तो चिकित्सक से समय तीन दिन बाद का मिलेगा। कनाडा में भारतीय और चीनी चिकित्सक ही बहुतायत में हैं। भारतीय चिकित्सकों की प्रतिभा और उनके मधुर व्यवहार ने विकसित और धनी देशों के नागरिकों को इलाज के लिए भारत आने को प्रेरित किया है। गर्व की बात है कि विदेशियों में आयुर्वेदिक चिकित्सा के प्रति विश्वास बढ़ा है। ब्रिटेन के महाराजा का आयुर्वेदिक इलाज के लिए भारत आना इसका प्रमाण है। भारत सरकार को मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक प्रयास करते हुए देश में नए और स्तरीय मेडिकल कालेज खोलने चाहिए। मेडिकल टूरिज्म से देश को न केवल बहुमूल्य विदेशी मुद्रा मिलेगी, बल्कि इससे व्यापक स्तर पर रोजगार सृजन भी होगा। मेडिकल टूरिज्म पर ध्यान देने के साथ-साथ सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि देश के नागरिकों को भी सस्ती और सुलभ चिकित्सा मिलती रहे।

राजीव वार्ष्णेय, पुरानी पैंठ-चंदौसी

विपक्ष का हंगामा

पुरानी आदतें आसानी से नहीं जातीं। विपक्ष का हंगामा करना एक स्थायी राजनीतिक चरित्र बन चुका है। जिन मुद्दों पर चर्चा आवश्यक है, वे हाशिये पर चले जाते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और जनहित से जुड़े अनेक मुद्दे हैं, जिन पर विपक्ष गंभीर कभी नहीं रहा और फिर वही पुराना मणिपुर और अदाणी मुद्दा विपक्ष की कार्य सूची में रहा। सत्ता और विपक्ष के बीच कटुता दूर होनी चाहिए तभी स्वस्थ चर्चा और ज्वलंत मुद्दे सुलझ सकते हैं। हंगामा खड़ा करना ही जब विपक्ष की प्राथमिकता हो तो व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी।

कैलाश मेहरा, गुरुग्राम

आप का चुनावी संघर्ष

आम आदमी पार्टी (आप) को दिल्ली में जीतना इतना आसान नहीं होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव (2025) में आप को भाजपा से सीधी टक्कर मिलने वाली है। पिछले दो विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी अपनी भ्रष्टाचार मुक्त साफ छवि के कारण जीत पाई, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पार्टी भ्रष्टाचार के कई बड़े आरोपों से घिरी हुई है। आम आदमी पार्टी की जो साफ-सुथरी छवि थी, वह काफी हद तक धूमिल हो चुकी है। इसके साथ ही खुद अरविंद केजरीवाल का चेहरा इतना प्रभावशाली नहीं रहा है, जिससे उनके नाम पर वोट मांगे जा सकें। अरविंद केजरीवाल खुद जेल से छूटे हैं, जिसके कारण उनकी छवि भी बेदाग नहीं रह गई है। आप का संगठन भी अब इतना मजबूत नहीं रहा है। कैलाश गहलोत जैसे कई बड़े और विश्वासी नेताओं के पार्टी छोड़ने से पार्टी के संगठन पर भी असर पड़ा है और वह कमजोर हुआ है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह दिखाई नहीं दे रहा है, जो पिछले दो चुनाव में था। जिसके कारण पार्टी के सक्रियता पर भी व्यापक असर दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही पार्टी गुटबाजी की भी शिकार है। वर्तमान परिस्थितियों में पार्टी के अंदर पहली वाली एकजुटता नहीं रही है। दूसरी तरफ भाजपा दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक नए जोश के साथ उतरेगी। महाराष्ट्र और हरियाणा में भाजपा की एकतरफा जीत ने दिल्ली के कार्यकर्ताओं में भी नया जोश भर दिया है। जिसके चलते आम आदमी पार्टी को दिल्ली में सीधी टक्कर मिलने वाली है।

विजय किशोर तिवारी, दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, चेयरमैन एमेरिटस- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक- संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

राष्ट्रीय संस्करण www.jagran.com
दैनिक जागरण
बुधवार 27 नवंबर, 2024

3.2 प्रतिशत तक पहुंच गया है केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2024-25 में देश की जीडीपी का। 2019-20 में यह आंकड़ा 1.67 प्रतिशत था।

आजकल

आर्थिकी को गति देता सरकारी खर्च

आतिफ रब्बानी
असिस्टेंट प्रोफेसर, भीमराव आंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर

ट्रिकल-डाउन के समर्थकों का तर्क है कि धनी लोगों और कारपोरेट के हाथों में अधिक धन होने से व्यय, बचत, निवेश और रोजगार आदि को बढ़ावा मिलता है। इससे सभी को लाभ होता है, पर देश में ट्रिकल-डाउन कारगर नहीं दिखता। आर्थिक नीतियां ऐसी होनी चाहिए, जो सभी के लिए हितकारी हों। भारतीय ज्ञान परंपरा कहती है, 'सर्वे भवंतु सुखिनः'। यही सूक्ति समग्र आर्थिक नीतियों का प्रेरक दर्शन बने, तभी व्यापक कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा

पिछले एक दशक से भारतीय अर्थव्यवस्था की गाड़ी सम्मानजनक रफ्तार से आगे बढ़ रही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार पिछले तीन वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था ने सुधार की कई मंजिलें तय की हैं। अर्थव्यवस्था में व्यवस्थित तरीके से विस्तार हुआ है। वित्त वर्ष 2023-24 में वास्तविक जीडीपी का स्तर 2019-20 के मुकाबले 20 प्रतिशत अधिक हो गया है। दुनिया की कुछ ही अर्थव्यवस्थाएं हैं जिन्होंने ऐसी संवृद्धि को बरकरार रख पाने में कामयाबी पाई है। यही कारण है कि तमाम वैश्विक उथल-पुथल के बावजूद आज विश्व बैंक सहित मूडीज और एसएंडपी जैसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां भी भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को लेकर आशावादी हैं। व्यापक और समावेशी विकास की उम्मीद की जा रही है। समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत के नीति नियंताओं ने 'ट्रिकल-डाउन' के सिद्धांत पर भरोसा जताया। तमाम सामाजिक-आर्थिक नीतियों के सृजन में इसी सिद्धांत को आधार बनाया गया है। हालांकि 1991 में भारत ने उदारीकरण अपनाने के साथ ही इस सिद्धांत को अंगीकार कर लिया था। पिछले एक दशक से नवउदारवादी आर्थिक नीतियों की गाड़ी त्वरित गति से आगे बढ़ रही है।

'ट्रिकल-डाउन' यानी रिसाव के सिद्धांत के मुताबिक धनी लोगों को दिए जाने वाले फायदे अंततः समाज के निचले तबके तक रिस-रिसकर पहुंचते हैं। इस सिद्धांत की मान्यता है कि मुक्त बाजार की व्यवस्था में अगर कुछ लोग बहुत अधिक तरक्की करते हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं, क्योंकि उनकी दौलत उनके खर्चों के माध्यम से रिस कर नीचे आएगी, जिससे समाज के निचले तबकों को भी फायदा पहुंचेगा। ध्यातव्य है कि अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं में 'ट्रिकल-डाउन' नाम का कोई बुनियादी सिद्धांत कभी नहीं रहा। इस शब्द का पहली बार इस्तेमाल हास्य कलाकार विल रोजर्स ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति हर्बर्ट हूवर की आर्थिक नीतियों की आलोचना करने के लिए किया था।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से संपत्ति का सृजन करनेवाले कारोबारी वर्ग को टैक्स आदि में रियायतें देने बात कही थी। प्रधानमंत्री का कहना था कि इस कदम से अर्थव्यवस्था में निजी पूंजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। धनाढ्य वर्ग और व्यापारियों को उद्योग एवं व्यापार में सुगम्यता प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने अनेक सकारात्मक कदम उठाए। कारपोरेट करों में कटौती समेत कई प्रोत्साहन दिए गए। वित्त वर्ष 2019-20 में कारपोरेट टैक्स की दर को 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया गया। साथ ही सरकार ने नई निगमित घरेलू कंपनियों के लिए कारपोरेट टैक्स की दर को 15 प्रतिशत कर दिया, लेकिन इन रियायतों के अपेक्षित नतीजे नहीं दिखते। टैक्स में कटौती इस उम्मीद में की गई थी कि कारपोरेट सेक्टर में निजी निवेश बढ़ेगा। वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 में निजी पूंजी निर्माण यानी नई मशीनरी और उपकरणों के खरीद में लगातार कमी दर्ज की गई। हालांकि अगले दो वर्षों 2021-22 और 2022-23 में निजी पूंजी निर्माण में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई। वित्त वर्ष 2018-19 और 2022-23 के दौरान निजी गैर-वित्तीय निगमों का सकल अचल पूंजी निर्माण 34.1 प्रतिशत से बढ़कर 34.9 प्रतिशत ही हुआ। जाहिर है निजी सेक्टर ने इन छूटों का उपयोग अपने प्लांटों का विस्तार करने के बजाय देनदारियों को चुकाने में किया। वर्ष 2019-23 की अवधि में सरकारी पूंजीगत व्यय ही अर्थव्यवस्था के पहिये को गति देने में सहायक हुआ। केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2019-20 की जीडीपी के 1.67 प्रतिशत से बढ़कर चालू वित्त वर्ष 2024-25 में 3.2 प्रतिशत तक पहुंच गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 बताता है कि वित्त वर्ष 2019-20 से केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय में साल दर साल 28.2 प्रतिशत की रफ्तार से वृद्धि हुई है।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के आंकड़े बताते हैं कि पिछले पांच वर्षों के दौरान श्रम के अनौपचारीकरण में वृद्धि हुई है। कृषि में श्रम भागीदारी दर में इजाफा हुआ है। विकास की बुनियादी समझ कहती है कि अर्थव्यवस्था में विकास के साथ खेती में लगी श्रमशक्ति घटनी चाहिए और विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में श्रम भागीदारी दर बढ़नी चाहिए, लेकिन इसके बरक्स खेती में लगे लोगों की संख्या 2018-19 में 42.5 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 46.1 प्रतिशत हो गई। इस असंबद्धता की बड़ी वजह है कि कारपोरेट सेक्टर रोजगार सृजित करने के मामलों में फिसड्डी साबित हो रहा है। पीएलएफएस के आंकड़े बताते हैं कि भारतीय युवाओं के लिए नौकरियों में कमी आई है। हालांकि पिछले एक दशक के दौरान देश में प्रतिव्यक्ति आय में तकरीबन 35 प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली है। वित्त वर्ष 2014-15 में प्रति व्यक्ति आय 72,805 रुपये थी, जो 2022-23 में बढ़कर 98,374 रुपये हो गई। इसमें सालाना चक्रवृद्धि दर पर मात्र 3.83 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई। चूंकि वास्तविक मुद्रास्फीति पर गंभीरता से विचार नहीं किया जाता है, इसलिए प्रति व्यक्ति आय के स्तर में वास्तविक इजाफा और भी कम रह जाएगा। यदि हम शीर्ष की एक प्रतिशत आबादी के अलावा बाकी के 99 प्रतिशत आबादी के प्रति व्यक्ति आय को देखें तो इसमें मामूली वृद्धि ही दिखती है।

इतना ही नहीं, आर्थिक विषमता की खाई भी गहरा गई है। पेरिस स्थित शोध संगठन वर्ल्ड इनइक्वेलिटी लैब की ओर से हाल में जारी एक शोधपत्र के मुताबिक देश के शीर्ष एक प्रतिशत तबके की आमदनी में हिस्सेदारी अपनी ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गई है। साल 2023 तक सबसे अमीर एक प्रतिशत भारतीयों के पास देश की आय का 22.6 प्रतिशत हिस्सा था। घरेलू बचत के मोर्चे पर भी बहुत आशाजनक माहौल नहीं दिखता। वित्त वर्ष 2021-22 में शुद्ध घरेलू बचत दर 7.3 प्रतिशत से घटकर 5.3 प्रतिशत के स्तर पर आ गई है। यह गत 47 वर्षों का सबसे निचला स्तर है। वहीं दूसरी तरफ परिवारों पर देनदारी यानी ऋण का बोझ बढ़ रहा है। क्रिसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 में कुल खुदरा ऋण यानी रीटेल लोन जीडीपी का 12.1 प्रतिशत था, जो 2023 में बढ़कर 19.4 प्रतिशत हो गया। वहीं देश में धनकुबेरों की संख्या में वृद्धि हो रही है। दुनिया के अमीर लोगों की 'फोर्ब्स' सूची के अनुसार वर्ष 2014 से 2022 के दौरान, भारतीय अरबपतियों की शुद्ध संपत्ति में 280 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जबकि इसी अवधि में राष्ट्रीय आय में 27.8 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

ट्रिकल-डाउन के समर्थकों का तर्क है कि धनी लोगों और कारपोरेट के हाथों में अधिक धन होने से व्यय, बचत, निवेश और रोजगार आदि को बढ़ावा मिलता है। इससे सभी को लाभ होता है, लेकिन भारत के मौजूदा आर्थिक नतीजे बताते हैं कि देश में ट्रिकल-डाउन कारगर नहीं दिखता। आर्थिक नीतियां ऐसी होनी चाहिए, जो सिर्फ गिने-चुनों को लाभ पहुंचाने के बजाय सभी के लिए हितकारी हों। भारतीय ज्ञान परंपरा में कहा ही गया है- 'सर्वे भवंतु सुखिनः'। यही सूक्ति समग्र आर्थिक नीतियों का प्रेरक दर्शन बने, तभी बृहतर कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा।

इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास पर हो रहे व्यय से अर्थव्यवस्था को हो रहा लाभ। फाइल

युवा आबादी के संतुलित उपयोग का समय

देवेंद्रराज सुथार

भारत के पास इस समय बड़ी संख्या में लोग कामकाजी उम्र के हैं। हालांकि यह लाभ हमेशा के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि देश की कुल प्रजनन दर में गिरावट आ रही है। इसके कारण अगले कुछ सालों में कामकाजी उम्र की आबादी का अनुपात कम होने लगेगा। ऐसे में भारत के लिए जरूरी है कि वह अपनी वृद्धि को उम्रदराज आबादी के बढ़ने से पहले ही टिकाऊ बनाए। इसलिए सरकारें अभी से युवा आबादी को आर्थिक लाभ में बदलने के लिए नीतिगत सुधारों की दिशा में ठोस कदम उठाएं। अभी भी बड़ी संख्या में लोग कृषि जैसे कम उत्पादक क्षेत्र में लगे हैं। कृषि महत्वपूर्ण तो है, लेकिन इस क्षेत्र में काम करने वालों की उत्पादकता कम है, जिससे आर्थिक विकास धीमा हो रहा है।

भारत को कम उत्पादक क्षेत्रों से लोगों को हटाकर उन्हें अधिक उत्पादक क्षेत्रों खासकर विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। विनिर्माण क्षेत्र में सेवा क्षेत्र की तुलना में अधिक लोगों को रोजगार देने की क्षमता है। उदाहरण के लिए, कपड़ा उद्योग लाखों लोगों को रोजगार दे सकता है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ाई जा सकती है। इससे न केवल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी, बल्कि घरेलू आय में भी वृद्धि होगी और घरेलू अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। हालांकि विनिर्माण क्षेत्र के विकास में कई चुनौतियां हैं। जैसे कि व्यापार के लिए आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करने में कठिनाई, भूमि तक पहुंच की कमी और व्यापार नियमों की जटिलता। कई उद्योगपतियों का मानना है कि भारत में व्यवसाय शुरू करना और उसे सुचारु रूप से चलाना अभी भी काफी चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर अनुकूल कारोबारी माहौल बनाना होगा। सरकार को आयात शुल्क कम करना चाहिए, ताकि भारतीय कंपनियों को सस्ती दर पर कच्चा माल मिल सके और वे निर्मित माल का निर्यात भी कर सकें। इसके साथ ही ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ लंबित मुक्त व्यापार समझौतों को अंतिम रूप देकर भारतीय उत्पादों के लिए नए बाजार खोले जा सकते हैं।

राज्य सरकारों को श्रम सुधारों पर काम करना चाहिए, ताकि श्रमिकों को लचीले काम के विकल्प मिल सकें। इसी तरह भूमि और भवन नियमों को सरल बनाना भी आवश्यक है, ताकि कारखाने लगाना आसान हो और लागत कम हो।

खरी-खरी

कुछ तो गड़बड़ है...

राजेंद्र बज

कुछ तो गड़बड़ है... उनका तकिया कलाम है। जब कोई बात उनके मन माफिक नहीं होती है, वे दूध में नींबू निचोड़ दिया करते हैं। हर किसी मामले को संदेह की नजरों से देखना उन्हें एक तेजतर्रार राजनीतिज्ञ का दर्जा प्रदान करता है। वैसे उनका राजनीति से रत्ती भर भी सरोकार नहीं है, लेकिन जब राजनीति में भारी उथल-पुथल का दौर आता है या कैसा भी चुनाव परिणाम आता है, उनकी जुबान कैंची की तरह चलने लगा करती है। आमतौर पर वह मुख्यधारा के विपरीत चला करते हैं, इसलिए हमेशा चर्चा का केंद्रबिंदु हुआ करते हैं। दो टूक बात करना तो उनकी आदत ही नहीं है। साधारण से साधारण बात को भी उलझा कर रख देने में उन्हें दिव्य आनंद की अनुभूति हुआ करती है। एक प्रकार से पानी में कंकड़ फेंक कर लहरों को गिनने की क्रिया को ही वह पुरुषार्थ का प्रतीक मानते हैं। उनके व्यक्तिगत जीवन की कुल जमा उपलब्धि यही है कि जब कभी चार यार मिलते हैं, घूम फिर कर उनकी ही चर्चा होने लगती है। दरअसल उनकी पहचान भीड़ से सर्वथा अलग हुआ करती है।

इसका कारण यह है कि जो जमाना देखता, कहता और सुनता है-उसके विपरीत तमाम उल्टे-सीधे तर्कों के आधार पर वह अपनी बात कह दिया करते हैं। किसी भी मामले में संपूर्ण सच के अभाव में अधूरे सच को जमकर सत्यापित करने में उनकी कोई सानी नहीं है। किसी भी विषय के बारे में विषय के प्रति अनजान रहने पर भी वह बहुत ही आत्मविश्वास के साथ अपनी टिप्पणी जड़ दिया करते हैं। मात्र अटकल के सहारे डंके की चोट पर अपनी बात रखते हैं।

ऐसा नहीं है कि अपनी इस आदत के चलते वह कभी धर्मसंकट में नहीं पड़े हों। वास्तव में ऐसी स्थिति निर्मित हो जाने पर अपने पूर्व कथन एवं मान्यता को घुमावदार मोड़ देना भी वह अच्छी तरह जानते हैं। यही कारण है कि वह आज तक किसी के भी दांव में नहीं आए। इन तमाम संदर्भों में उनका व्यक्तित्व वर्तमान दौर की राजनीति में एकदम फिट बैठता है, लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि वह राजनीति में सक्रिय भागीदारी नहीं करते। अगर वह राजनीति में होते तो राजनीति का मजा ही कुछ और होता।

X पोस्ट

कुछ पार्टियां और उनके नेता सोशल नेटवर्क साइट्स पर ही चुनाव प्रचार के जरिये सरकार बनाकर प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। जगदीश भाटिया@jagdish

बांग्लादेशी हिंदू भी हमारे ही रक्त-संबंधी हैं। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाने के लिए आगे आना होगा।
राहुल शिवशंकर@RShivshankar

बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने चिन्मय कृष्ण दास को गिरफ्तार कर अपने मंसूबे जाहिर कर दिए। जब कृष्ण दास के नेतृत्व में हिंदुओं ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाई तो फिर उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया? सरकार न केवल हिंदुओं की आठ-सूत्रीय मांगों को अनदेखा करने में लगी है, बल्कि जिहादियों, सेना और पुलिस के हाथों उनके निरंतर उत्पीड़न को भी नहीं रोक पा रही।
तसलीमा नसरीन@taslimanasreen

संभल में पत्थरबाजी करती भीड़ ने चुनी हुई सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि भारत की न्यायपालिका के खिलाफ अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। न्यायपालिका नागरिक समाज का अंतिम आवलंबन है। इसके बाद अंधकार युग और आंतरिक संघर्ष ही बचता है। सुमंत@sumantkabir

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या महाराष्ट्र में भाजपा को अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहिए?

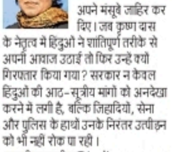

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या बांग्लादेश की अंतरिम सरकार कट्टरपंथियों के चंगुल में नजर आ रही है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

संजय जी धृतराष्ट्र के रहे आंख अरु कान,
मिटा रहे 'धृतराष्ट्र' का अब वह नाम-निशान।
अब वह नाम-निशान बचेंगे कैसे उद्धव,
संजय रोज बयान रहे देते जब नव-नव!
वह दल कैसे प्राप्त भला कर सकता है जय,
बैठा जिसके साथ रहे कलियुग का संजय!!
- ओमप्रकाश तिवारी

महाराष्ट्र डायरी

ले डूबी अतिमहत्वाकांक्षा

ओमप्रकाश तिवारी
ब्यूरो प्रमुख, मुंबई

करीब छह दशक तक मुंबई पर राज करनेवाले शिवसेना संस्थापक बालासाहेब ठाकरे की पार्टी कभी ऐसी अवस्था में पहुंच जाएगी, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। उनके पुत्र उद्धव ठाकरे की अतिमहत्वाकांक्षा एवं उद्धव के सिपहसालारों के बड़बोलेपन ने शिवसेना (उद्धव) की ऐसी दुर्गति करवा दी है, जिससे निकट भविष्य में उबर पाना संभव नहीं दिख रहा है। अपनी ताकत को वास्तविकता से अधिक आंकना उद्धव ठाकरे की कमजोरी रही है। 2014 में भाजपा के साथ गठबंधन करके लोकसभा चुनाव लड़ी शिवसेना 18 सीटें जीती थी। लोकसभा चुनाव में यह उसका सर्वोच्च आंकड़ा था। सर्वविदित है कि उस चुनाव में उसे इतनी सीटें मोदी लहर के कारण प्राप्त हुई थीं, लेकिन स्वयं उद्धव के साथ-साथ उनके पुत्र आदित्य ठाकरे और उनके सिपहसालार संजय राउत को लगा कि इतनी सीटें खुद उद्धव ठाकरे के चेहरे पर चुनाव लड़कर आई हैं। इसी गलतफहमी के कारण छह माह बाद हुए विधानसभा चुनाव में जब भाजपा ने सीटों के बराबरी से बंटवारे का प्रस्ताव रखा तो उद्धव ने उसे नकार दिया। उससे पहले तक विधानसभा में शिवसेना 171 एवं भाजपा 117 सीटों पर चुनाव लड़ती आई थीं। जबकि शिवसेना द्वारा लड़ी जानेवाली सीटों में से 60 सीटें ऐसी थीं, जिनपर वह कभी जीत नहीं सकी थी। भाजपा चाहती थी कि शिवसेना वही सीटें उसे दे दे, ताकि भाजपा उनपर लड़कर अपनी संख्या बढ़ाने का प्रयास कर सके, पर उद्धव इसके लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि शिवसेना-भाजपा का 1995 से ही फार्मूला चलता आ रहा था कि जिसकी सीटें ज्यादा आएंगी, उसका मुख्यमंत्री बनेगा। तब ढाई-ढाई साल का भी कोई फार्मूला निर्धारित नहीं हुआ था। दोनों दलों द्वारा लड़ी गई सीटों में 54 सीटों का अंतर होता था। फिर भी लड़ी गई सीटों पर हमेशा जीत का स्ट्राइक रेट भाजपा का ही ज्यादा होता था।

सीटों की संख्या को लेकर समझौता न हो पाने के कारण 2014 में नामांकन शुरू होने के ठीक पहले भाजपा-शिवसेना का गठबंधन टूट गया और दोनों दल अपनी-अपनी ताकत से अलग-अलग चुनाव लड़े। उस चुनाव में भाजपा को 122 और शिवसेना को उसकी लगभग आधी यानी 63 सीटें प्राप्त हुईं। यहां तक कि शिवसेना के गढ़ मुंबई में भी उसको भाजपा से कम सीटें मिलीं। उद्धव ठाकरे को उसी समय शिवसेना की वास्तविक ताकत का अहसास हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। भाजपा को उस समय सरकार बनाने के लिए 41 सीटों वाली राकांपा ने बाहर से समर्थन दे दिया था। अजीत पवार की मानें तो राकांपा का बड़ा हिस्सा उस समय भी इन संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार था, लेकिन भाजपा ने कुछ सप्ताह बाद ही अपनी पुरानी साथी शिवसेना को साथ लेकर चलाने का फैसला किया, और शिवसेन सरकार में शामिल हो गई।

उद्धव ने इसे भाजपा की कमजोरी समझा और पूरे पांच वर्ष तक राज्य और केंद्र की सरकार में साथ रहते हुए भी भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को लगातार भला-बुरा कहते रहे। इसके बावजूद 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले अमित शाह उद्धव ठाकरे के बांद्रा स्थित निजी आवास पर जाकर उनसे मिले, और लोकसभा चुनाव में उन्हें फिर से उतनी ही सीटें दीं, जितनी पर वह 2014 में लड़े थे। अमित शाह से हुई इसी मुलाकात को लेकर बाद में उद्धव ठाकरे लगातार यह बयान देते रहे कि शाह ने उन्हें ढाई साल मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया था। हालांकि अमित शाह एवं देवेंद्र फड़णवीस दोनों उद्धव के इस बयान का कई बार खंडन कर चुके हैं। चूंकि उस मुलाकात के समय शाह और उद्धव के अलावा और कोई नहीं था, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि कौन सच या झूठ बोल रहा है, लेकिन उद्धव ने यही बयान देकर भाजपा नेतृत्व को झूठा बताकर 2019 में भाजपा से अचानक गठबंधन तोड़ मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस-राकांपा का हाथ थाम लिया था। जबकि विधानसभा चुनाव उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर ही लड़ा था और उस चुनाव के प्रचार में हर जगह भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर पेश किया जा रहा था। तब न सिर्फ उद्धव से धोखा खाई भाजपा, बल्कि शिवसेना से चुनकर आए विधायक और उसे वोट देनेवाले मतदाता भी हक्का-बक्का रह गए थे, क्योंकि उन्होंने जनादेश उस कांग्रेस-राकांपा के विरोध में दिया था, जिनके साथ उद्धव गए थे।

उद्धव के प्रति मतदाताओं के मन में पल रहे गुस्से को बाद के घटनाक्रम ने और बढ़ाने का ही काम किया। जो बालासाहेब ठाकरे अयोध्या में विवादित ढांचा ढहने के पांच वर्ष पहले ही प्रबल हिंदुत्व का पक्ष लेने के कारण न्यायालय के निशाने पर आ चुके थे, उनके पुत्र उद्धव ठाकरे ने उसी हिंदुत्व को ताले में बंद कर दिया। मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने के लिए 'हिंदू हृदय सम्राट' के स्थान पर 'जनाब बालासाहेब' ठाकरे लिखा जाना कट्टर शिवसैनिकों को नहीं पसंद आया। दादर स्थित शिवसेना भवन के नीचे शिवसैनिकों से ज्यादा दाढ़ी-टोपी और बुर्का वालों की भीड़ लगना भी शिवसैनिकों को रास नहीं आ रहा था। उद्धव ठाकरे ने 2022 में शिवसेना तोड़ने वाले एकनाथ शिंदे को लगातार गद्दार कहकर संबोधित किया। उनके ये शब्द कुछ समय तक को मराठी मानुष को मनोरंजक लगे, लेकिन शिंदे को मुख्यमंत्री के रूप में दिनरात मेहनत करते देख उन्हें उद्धव के ये शब्द भी खटकने लगे। मराठी मतदाता उद्धव से कट तो लोकसभा चुनाव में ही गए थे। फिर भी तब उन्हें सफलता इसलिए मिली, क्योंकि कांग्रेस का मुस्लिम वोटबैंक उनके साथ आ गया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटबैंक भी उन्हें जिता नहीं सका, क्योंकि अधिसंख्य प्रतिबद्ध शिवसैनिक उनसे कट चुके हैं। इन्हीं कारणों से इस बार विधानसभा चुनाव में उद्धव गुट वाली शिवसेना 20 सीटों पर सिमटकर रह गई।

उद्धव ठाकरे। फाइल

हरियाणा डायरी

नेता विपक्ष का इंतजार

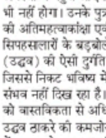

अनुराग अग्रवाल
राज्य ब्यूरो प्रमुख, हरियाणा

हरियाणा में लगातार तीसरी बार सत्ता में आई भाजपा जहां अपने सदस्यों की संख्या बढ़ाने में जुटी है, वहीं कांग्रेस के सामने विपक्ष के नेता के चयन का संकट बना हुआ है। कई साल के बाद यह पहला मौका है, जब हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र बिना विपक्ष के नेता के चला। इसे लेकर कांग्रेस की दलील है कि कर्नाटक में भी भाजपा कई माह तक विपक्ष के नेता का चयन नहीं कर पाई थी, लेकिन कर्नाटक और हरियाणा दोनों राज्यों की राजनीतिक परिस्थितियां भिन्न हैं। कर्नाटक में विपक्ष के नेता का चयन देरी से होने के पीछे भाजपा की गुटबाजी वजह नहीं थी, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस की गुटबाजी विपक्ष के नेता के चयन में देरी की सबसे बड़ी वजह है।

यदि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा मिलकर चुनाव लड़ते तो पार्टी की सत्ता में वापसी हो सकती थी, लेकिन हुड्डा बहुत अधिक आत्मविश्वास में थे। उन्हें लग रहा था कि हर हाल में कांग्रेस की सरकार आने वाली है। पार्टी के शुभचिंतक जब उनके पुत्र दीपेंद्र हुड्डा को आकर अलग-अलग सीटों पर जीत में आने वाली बाधाएं दूर करने का सुझाव देते थे तो उन्हें जवाब मिलता था कि हमारी सरकार आ रही है, इसलिए एक-दो सीट हार भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यह कहते-कहते कांग्रेस सत्ता से पूरी तरह दूर हो गई। यदि कांग्रेस एक-एक सीट पर आ रही बाधाओं को समय रहते दूर कर ली होती और सैलजा को भरोसे में लेकर चुनाव लड़ी होती तो निःसंदेह भाजपा के लिए तीसरी बार सत्ता में आना बड़ी चुनौती बन जाती। कुछ विश्लेषक कह रहे हैं कि कांग्रेस के गुटबाज नेताओं ने हरियाणा में जीत भाजपा को थाली में परोसकर स्वयं प्रदान की है।

भाजपा अभी पार्टी के साथ नए लोगों को जोड़ने के अभियान में पूरी ताकत के साथ लगी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल तक जिलों में सदस्यता अभियान के पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। विधानसभा चुनाव में 55 लाख 48 हजार 800 वोट प्राप्त करने वाली भाजपा ने इस बार 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। भाजपा हर छह साल बाद सदस्यता का नवीनीकरण करती है। हरियाणा की 90 सदस्यीय विधानसभा में इस बार भाजपा को 48 सीटों के साथ 39.94 प्रतिशत वोट मिले हैं। कांग्रेस को 37 सीटों के साथ 54 लाख 30 हजार 602 यानी 39.09 प्रतिशत वोट मिले हैं। दोनों के मत प्रतिशत में मात्र 0.85 प्रतिशत का अंतर है। भाजपा ने कांग्रेस के मुकाबले 11 सीटें अधिक हासिल की और मत प्रतिशत में बढ़ोतरी मात्र 0.85 प्रतिशत ही कर पाई। कांग्रेस के पास इस समय खुश होने के लिए सबसे बड़ा कारण यही है कि उसका और भाजपा का मत प्रतिशत लगभग बराबर है, लेकिन लोकतंत्र में हार-जीत काफी मायने रखती है।

आपसी गुटबाजी को छिपाने के लिए कांग्रेस इस समय ईवीएम पर पूरे योजनाबद्ध तरीके से ठीकरा फोड़ने की रणनीति पर चल रही है। उसने हाई कोर्ट में ईवीएम में गड़बड़ी होने संबंधी एक याचिका दायर की है। कांग्रेस के रणनीतिकारों ने अपनी हार के कारणों में एक कारण पार्टी प्रभारी दीपक बाबरिया को भी बना रखा है। पार्टी की हार की नैतिक जिम्मेदारी लेने से बच रहे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने पिछले दिनों कहा कि दीपक बाबरिया को मतगणना से पहले ही इस बात की जानकारी थी कि कांग्रेस किन-किन 14 विधानसभा सीटों पर चुनाव हारने वाली है, लेकिन बाबरिया ने इस जानकारी को कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से साझा करने के बजाय छिपाने का काम किया। बाबरिया का अभी इस आरोप पर कोई जवाब नहीं आया है।

दिल्ली में बैठे कांग्रेसी नेता हुड्डा खेमे की इस रणनीति को भलीभांति समझ रहे हैं कि उदयभान को बचाने के लिए बाबरिया को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस हाईकमान इस बार विपक्ष के नेता का पद हुड्डा को देने के हक में नहीं है। हालांकि कांग्रेस के नव निर्वाचित 37 विधायकों में 33 विधायक हुड्डा समर्थक हैं, लेकिन कांग्रेस हाईकमान की रुचि इस बात में है कि किसी दूसरे विधायक को यह जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। इसके लिए आफताब अहमद, अशोक अरोड़ा, गीता भुक्कल, चंद्रमोहन बिश्नोई और डा. रघुबीर कादियान के नाम चर्चा में चल रहे हैं। विपक्ष के नेता के अभाव में कांग्रेस विधायक भी आक्रामक नहीं हैं। रही-सही कसर सिरसा के कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने पूरी कर दी, जिन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मंच पर जाकर उनकी तारीफ के ऐसे पूल बांधे कि हुड्डा भी शर्मा गए। अब हरियाणा के कांग्रेसियों को पार्टी हाईकमान के इस फैसले का इंतजार है कि कब और किसे विपक्ष का नेता नामित किया जाता है।

विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (दाएं) और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। जागरण

संविधान दिवस

राष्ट्र की आत्मा

हर साल 26 नवंबर को भारत संविधान दिवस मनाता है। यह दिन 1949 में भारतीय संविधान को अपनाने की याद दिलाता है, जो एक ऐतिहासिक घटना थी जिसने भारत के लोकतांत्रिक लोकाचार की नींव रखी। जैसा कि हम इस महत्वपूर्ण अवसर पर विचार करते हैं, इस कानूनी दस्तावेज के निर्माण, कार्यप्रणाली और भविष्य की चुनौतियों को समझना अनिवार्य है जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के लिए मार्गदर्शक शक्ति रहा है। भारत की विविधता और जटिलताओं को देखते हुए भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करना एक असाधारण उपलब्धि थी। 1947 में स्वतंत्रता के बाद, 299 सदस्यों वाली संविधान सभा ने एक नए स्वतंत्र लेकिन विविधतापूर्ण राष्ट्र के लिए संविधान तैयार करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। भारतीय संविधान के निर्माता डॉ. बीआर अंबेडकर ने मसौदा समिति की अध्यक्षता की और सुनिश्चित किया कि यह दस्तावेज न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को प्रतिबिंबित करे। मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया को पूरा करने में सभा को 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे, जिसके दौरान इसने विस्तृत बहस और विचार-विमर्श किया। संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड और कनाडा जैसे विभिन्न देशों के संविधानों से प्रेरणा लेते हुए, भारतीय संविधान ने सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल किया और उन्हें भारतीय वास्तविकताओं के अनुरूप ढाला। 26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू हुआ, जिसने भारत गणराज्य के जन्म को चिह्नित किया। भारतीय संविधान, अपने 448 अनुच्छेदों, 12 अनुसूचियों और कई संशोधनों के साथ, दुनिया के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। इसकी मुख्य ताकत इसकी लचीलापन और अनुकूलनीयता में निहित है। अपने मूलभूत सिद्धांतों में कठोर होने के बावजूद, यह उभरते सामाजिक-राजनीतिक चुनौतियों को संबोधित करने के लिए संशोधनों की अनुमति देता है। अपने गोद लेने के बाद से, संविधान ने राष्ट्र को विभाजन, आर्थिक संकट और सामाजिक उथल-पुथल सहित कई चुनौतियों के माध्यम से मार्गदर्शन किया है, जिससे निरंतरता और स्थिरता सुनिश्चित हुई है। अपनी सफलता के बावजूद, भारतीय संविधान कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। भारत को संसाधन आवंटन, विधायी शक्तियों और प्रशासनिक स्वायत्तता को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच बढ़ते तनाव का सामना करना पड़ रहा है, जबकि संवैधानिक संरक्षक के रूप में न्यायपालिका की भूमिका के बावजूद न्यायिक सक्रियता और पारदर्शिता के बारे में चिंताएँ बनी हुई हैं। धनबल, राजनीति का अपराधीकरण और घटता मतदाता मतदान जैसे मुद्दे तत्काल सुधार की मांग करते हैं। साथ ही, संवैधानिक सुरक्षा उपायों के बावजूद जाति-आधारित भेदभाव, लैंगिक असमानता और क्षेत्रीय असमानताएं देश की प्रगति को कमजोर कर रही हैं। डिजिटल युग में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। जैसे-जैसे भारत एक गणतंत्र के रूप में अपनी शताब्दी की ओर बढ़ रहा है, जवाबदेही और पारदर्शिता के लिए संस्थानों को मजबूत करके, सहभागी लोकतंत्र को बढ़ावा देकर, धर्मनिरपेक्ष और बहुलवादी लोकाचार को कायम रखते हुए और यह सुनिश्चित करके संविधान के आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि करने की सख्त जरूरत है कि संवैधानिक संशोधन इसके मूल सिद्धांतों को संरक्षित करें।

राजनीति में लैंगिक पूर्वाग्रह

दुनिया पितृसत्तात्मक मानसिकता, लिंगवाद और श्रम के लैंगिक विभाजन में गहराई से उलझी हुई है। मुख्य राजनीतिक कार्यकारी के रूप में महिलाओं की हिस्सेदारी अभी भी पुरुषों की तुलना में अधिक है।

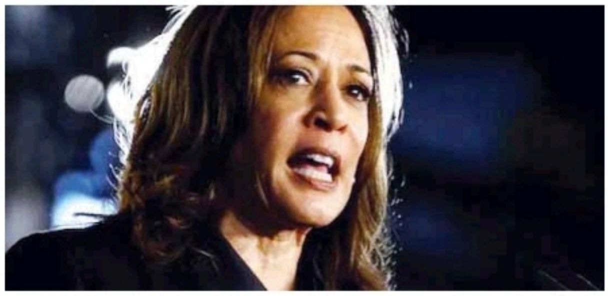

अर्चना दत्ता
(लेखिका दूरदर्शन की पूर्व महानिदेशक हैं)

डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी बार चुनावी जीत के बाद, एक प्रमुख अमेरिकी दैनिक ने पांच हजार से अधिक महिला मतदाताओं के बीच उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए एक सर्वेक्षण किया। उनमें से अधिकांश ने 'अधिकारों' के ह्रास और 'उनके प्रजनन भविष्य' के बारे में चिंता व्यक्त की, और 'दुख', 'डरावना', 'निराशा', 'पीड़ा', 'विश्वासघात' और 'दिल टूटने' जैसी भावनाओं को व्यक्त किया। कुछ पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं की टिप्पणियों में भी निराशा दिखी, क्योंकि उनमें से कई ने महसूस किया कि उनकी आवाज 'पहले से कहीं ज्यादा दबा दी गई' और उन्हें 'खाली हाथ' छोड़ दिया गया। जबकि एक 36 वर्षीय महिला ने अफसोस जताया कि 'यह स्पष्ट है कि पुरुष सत्ता पर कब्जा करना चाहते थे' इस चुनाव में लिंगभेद ने जीत हासिल की'। जबकि, एक अन्य प्रमुख अमेरिकी दैनिक ने हैरिस की हार का कारण 'गर्भपात के अधिकार' और 'लोकतंत्र की सुरक्षा' जैसे मुद्दों पर उनके ज्यादा जोर देना और अर्थव्यवस्था या आव्रजन की स्थिति पर पर्याप्त ध्यान न देना बताया, जिसे कई अमेरिकी सबसे ज्यादा दबाव वाले मुद्दे मानते हैं। दूसरी ओर, हैरिस ने अपने समर्पण भाषण में अपने समर्थकों से सतर्क रहने और अपने मूल्यों के लिए लड़ते रहने का आग्रह किया। फिर भी, प्रजनन स्वतंत्रता के लिए काम करने वाले कई गैर-लाभकारी संगठनों ने डेमोक्रेट्स से %अपनी पार्टी और राष्ट्र दोनों के भीतर लिंगभेद का सीधे सामना करने के लिए एक दीर्घकालिक योजना विकसित करने का आग्रह किया - जिसने हैरिस और हिलेरी क्लिंटन दोनों को बाधित किया%, जो एक प्रमुख पार्टी के राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन जीतने वाली एकमात्र महिला हैं। अमेरिका में, 2023 में महिलाओं ने कांग्रेस की 28 प्रतिशत सीटों पर कब्जा कर लिया, जबकि डेमोक्रेट्स ने रिपब्लिकन पर बढ़त हासिल की, 41 प्रतिशत सीटों के साथ, और रिपब्लिकन के पास केवल 15.4 प्रतिशत सदस्य थे।

महिलाएँ सभी राज्य विधायकों में 32.7 प्रतिशत हैं, डेमोक्रेट में 48 प्रतिशत और रिपब्लिकन में 20 प्रतिशत हैं। डेमोक्रेटिक महिलाएँ 26 राज्य विधानसभाओं में डेमोक्रेटिक पुरुषों के बराबर या उससे ऊपर हैं। जबकि रिपब्लिकन महिलाएँ सभी राज्यों में रिपब्लिकन पुरुषों के बराबर नहीं हैं, 47 राज्य विधानसभाओं में रिपब्लिकन सीटों का एक तिहाई या उससे कम हिस्सा रखती हैं। अध्ययनों ने टिप्पणी की है कि पार्टियों में लिंग भूमिकाओं के बारे में प्रचलित मान्यताएँ और दृष्टिकोण राजनीतिक प्रतिनिधित्व को नियंत्रित करते हैं, और रूढ़िवादियों के बीच अधिक पारंपरिक धारणा बनी हुई है कि %महिलाओं की सफलता पुरुषों की कीमत पर है% (रटगर्स विश्वविद्यालय में अमेरिकी महिला और राजनीति केंद्र)। हालाँकि, यह केवल यूएसए ही नहीं है जिसने कभी भी सर्वोच्च राजनीतिक पद पर किसी महिला को नहीं चुना, बल्कि स्वीडन जैसे कई सबसे सामाजिक और आर्थिक रूप से उन्नत देशों में, अधिकांश संस्थानों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का अच्छा रिकॉर्ड होने के बावजूद, संसद में 47.5 प्रतिशत और मंत्रिपरिषद में 54.5 प्रतिशत, कभी भी प्रधान मंत्री के रूप में एक महिला नहीं रही है। पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया के देशों ने राजनीतिक सशक्तिकरण (ह्रुश्रस्न) में काल्पनिक 100 प्रतिशत लिंग अंतर का केवल 15 प्रतिशत ही बंद किया है। जबकि भारत, सबसे बड़ा लोकतंत्र, वर्तमान लोकसभा में महिलाओं की बहुत कम उपस्थिति (13.62 प्रतिशत) है। पिछले साल एक कानून पारित किया गया था, जिसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित की गई थीं, लेकिन इसका क्रियान्वयन निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने तक स्थगित कर दिया गया है। भारत में एक महिला प्रधानमंत्री और दो महिला राष्ट्रपति थीं। लेकिन, गहरी संरचनात्मक और प्रणालीगत कठिनाइयों (राजे, 2019) ने महिलाओं का खराब प्रतिनिधित्व किया, जिसके परिणामस्वरूप शासन और निर्णय लेने में 'लोकतांत्रिक कमी' हुई (रहमान और राव, 2004)। भारत ने 90 के दशक की शुरुआत से ही ग्रामीण-शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की, फिर भी, कई सर्वेक्षणों में पाया गया कि अधिकांश महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों ने 'लिंग-आधारित भेदभाव' की सूचना दी, और कई स्थानों पर, उनके पुरुष रिश्तेदारों, विशेष रूप से पतियों ने 'प्रॉक्सी' भूमिकाएँ निभाईं। राजनीति में इस असमान शक्ति समीकरण के कारणों की व्याख्या करते हुए, अध्ययनों (फॉक्स और लॉलेस, 2004) ने स्पष्ट किया कि 'महत्वाकांक्षा में लिंग अंतर' है, क्योंकि राजनीतिक उम्मीदवारों के रूप में आवश्यक पेशेवर और आर्थिक साख वाली कई योग्य महिलाएँ अक्सर 'कार्यकारी कार्यालयों के लिए दौड़ने के लिए कम प्रोत्साहित महसूस करती हैं और उनका मानना है कि वे पुरुषों की तुलना में ऐसे कार्यालयों के लिए कम योग्य हैं'।

साक्ष्य यह भी बताते हैं कि महिलाओं का राजनीतिक करियर अक्सर 'पारिवारिक और संबंधपरक विचारों' से प्रभावित होता है, और यदि उन्हें अपने करियर की उपलब्धियों के लिए अधिक लागत का सामना करना पड़ता है, तो वे ऐसे उद्देश्यों को पूरा करने से कतराती हैं। साथ ही, अन्य शोधकर्ताओं ने मतदाताओं के पूर्वाग्रह और भेदभाव की ओर इशारा किया जो महिलाओं की चुनावी संभावनाओं में मात्रात्मक रूप से मायने रखते हैं। यहां तक कि राजनीतिक दल के नेता भी गेट-कीपर के रूप में कार्य करते हैं, यदि वे महिलाओं के प्रति मतदाताओं के पूर्वाग्रह के बारे में जानते हैं, और वोट-अधिकतम करने की रणनीति के रूप में महिला दावेदारों के बजाय पुरुष उम्मीदवारों को बढ़ावा देने के इच्छुक हैं।

साक्ष्य यह भी बताते हैं कि महिलाओं का राजनीतिक करियर अक्सर 'पारिवारिक और संबंधपरक विचारों' से प्रभावित होता है, और यदि उन्हें अपने करियर की उपलब्धियों के लिए अधिक लागत का सामना करना पड़ता है, तो वे ऐसे उद्देश्यों को पूरा करने से कतराती हैं। साथ ही, अन्य शोधकर्ताओं ने मतदाताओं के पूर्वाग्रह और भेदभाव की ओर इशारा किया जो महिलाओं की चुनावी संभावनाओं में मात्रात्मक रूप से मायने रखते हैं। यहां तक कि राजनीतिक दल के नेता भी गेट-कीपर के रूप में कार्य करते हैं, यदि वे महिलाओं के प्रति मतदाताओं के पूर्वाग्रह के बारे में जानते हैं, और वोट-अधिकतम करने की रणनीति के रूप में महिला दावेदारों के बजाय पुरुष उम्मीदवारों को बढ़ावा देने के इच्छुक हैं (एस्टेव-वोलार्ट और बैग्स (2012)। फिर भी, पश्चिमी यूरोप में विश्व मूल्य सर्वेक्षण (2017-2020) की नवीनतम लहर के आंकड़ों से पता चला है कि 20 प्रतिशत से भी कम सर्वेक्षण उत्तरदाताओं ने इस कथन से सहमति व्यक्त की है कि पुरुष महिलाओं की तुलना में बेहतर राजनीतिक नेता बनाते हैं।

अब, इसका समाधान क्या है? स्वीडन (बेस्ले एट अल., 2017) जैसे विभिन्न देशों में उम्मीदवारों की सूची में लैंगिक कोटा लागू करना महिलाओं को सशक्त बनाने और निर्वाचित राजनेताओं की गुणवत्ता में सुधार करने में कमोबेश प्रभावी है, खासकर उम्मीदवारों की सूची की संरचना को विनियमित करके (कैम्पा और हॉसर, 2020)। कई लोगों ने यह भी सुझाव दिया कि एक संयुक्त राजनीतिक-आर्थिक रणनीति जो श्रम बाजार में महिलाओं के समावेश पर जोर देती है, और जोड़ों के भीतर आर्थिक भूमिकाओं का पुनर्वितरण करती है, लैंगिक-भूमिका दृष्टिकोण को बदल सकती है और महिलाओं को राजनीतिक सत्ता के पदों पर प्रवेश करने में मदद कर सकती है (फोल्के और रिकने, 2020 और कैम्पा और सेराफिनेली, 2019)। चूंकि दुनिया पितृसत्तात्मक मानसिकता, लिंगवाद और श्रम के लैंगिक विभाजन में गहराई से उलझी हुई है, मुख्य राजनीतिक कार्यकारी के रूप में महिलाओं की हिस्सेदारी अभी भी पुरुषों की तुलना में 9 से 1 से अधिक है।

भारत में चिकित्सा पर्यटन

विदेश में रहने वाले भारतीय प्रवासी भी सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा देखभाल के लिए तेजी से भारत लौट रहे हैं।

आरके सिन्हा
(लेखक, राज्यसभा के पूर्व सांसद हैं)

हाल ही में, ब्रिटेन के राजा चार्ल्स अपनी पत्नी, रानी कैमिला के साथ एक निजी यात्रा पर भारत आए। अपने तीन दिवसीय प्रवास के दौरान, वे बैंगलुरु के पास एक आधुनिक समग्र स्वास्थ्य केंद्र में रुके, जहाँ उन्होंने योग, ध्यान सत्र और योग चिकित्सा में भाग लिया। यह दर्शाता है कि सामान्य रोगियों से लेकर राजघरानों तक, वैश्विक अभिजात वर्ग भी भारत के आधुनिक डॉक्टरों और पारंपरिक उपचार विधियों से अच्छे स्वास्थ्य और युवावस्था को बनाए रखने के लाभों को महसूस कर रहे हैं। हाल के वर्षों में, भारत हृदय रोग, हड्डी के विकार, किडनी और लीवर प्रत्यारोपण, दंत चिकित्सा, कैंसर और यहां तक कि लाइलाज मानी जाने वाली बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बन गया है। मरीज न केवल दक्षिण एशियाई देशों से बल्कि अफ्रीका, मध्य एशिया, खाड़ी देशों और यहां तक कि पश्चिमी देशों से भी हर साल लाखों की संख्या में आ रहे हैं। सस्ती और सफल आधुनिक चिकित्सा उपचारों के साथ-साथ आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आहार विज्ञान और बाजरा आधारित चिकित्सा जैसी पारंपरिक भारतीय उपचार पद्धतियाँ विदेशी रोगियों के बीच लोकप्रिय हो रही हैं। उदाहरण के लिए, केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री, रैला ओडिंगा की बेटी ने केरल के एर्नाकुलम में श्रीधरेयम आयुर्वेदिक नेत्र अस्पताल में उपचार प्राप्त करने के बाद अपनी दृष्टि वापस पा ली।

इस सफलता के कारण भारत में आयुर्वेदिक उपचार चाहने वाले पूर्वी अफ्रीका के रोगियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। देहरादून की अपनी लगातार यात्राओं के दौरान, मैं अक्सर उड़ानों और ट्रेनों में सभी उम्र और व्यवसायों के पुरुषों और महिलाओं से मिलता हूँ। उनमें से कई दो सप्ताह से लेकर तीन महीने तक के प्रवास के लिए हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून जैसे स्थानों पर आश्रमों या स्वास्थ्य केंद्रों की ओर जाते हैं।

उनके ठहरने की अवधि और लागत - जो अक्सर लक्जरी पाँच सितारा होटल दरों के बराबर या उससे अधिक होती है - उनकी स्थिति की गंभीरता और आवश्यक उपचार पर निर्भर करती है। पारंपरिक उपचारों के अलावा, दिल्ली, मुंबई, बैंगलुरु और चंडीगढ़ जैसे शहरों के आधुनिक अस्पताल अपनी उपस्थिति को बेहतर बनाने के लिए कॉस्मेटिक प्रक्रियाओं की तलाश करने वाले बड़ी संख्या में अंतरराष्ट्रीय रोगियों को आकर्षित कर रहे हैं। प्लास्टिक सर्जन हर महीने दर्जनों विदेशी मरीजों को जले हुए घाव की मरम्मत, बाल प्रत्यारोपण और त्वचा कसने की प्रक्रियाओं जैसे उपचारों के लिए देखते हैं। यह प्रवृत्ति भारत के लिए अधिक विदेशी रोगियों को आकर्षित करने का एक सुनहरा अवसर दर्शाती है। चिकित्सा पर्यटन न केवल मूल्यवान विदेशी मुद्रा अर्जित करता है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को भी समर्थन देता है, क्योंकि मरीज अक्सर देखभाल करने वालों के साथ आते हैं जो हफ्तों या महीनों तक होटलों में रहते हैं।

विदेश में रहने वाले भारतीय प्रवासी भी सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा देखभाल के लिए तेजी से भारत लौट रहे हैं। भारत की बढ़त यूरोप या अमेरिका में समान सेवाओं की लागत के एक अंश पर शीर्ष-स्तरीय प्री-और पोस्ट-सर्जिकल देखभाल प्रदान करने में निहित है। भारत में कॉस्मेटिक सर्जन वसा घटाने और त्वचा कसने जैसी प्रक्रियाओं की मांग करने वाले रोगियों का इलाज करते हैं, क्योंकि उम्र बढ़ने और पर्यावरणीय कारक त्वचा संबंधी समस्याओं को बढ़ाते हैं। सौंदर्य उपचारों के बारे में बढ़ती जागरूकता के साथ, पुरुष और महिला दोनों ही कॉस्मेटिक और सर्जिकल समाधानों का विकल्प चुन रहे हैं।

विश्व स्तर पर, सालाना लाखों कॉस्मेटिक सर्जरी की जाती हैं, जिसमें अमेरिका इस क्षेत्र में अग्रणी है। शुरुआत में महिलाओं के बीच लोकप्रिय होने के बावजूद, प्लास्टिक सर्जरी अब पुरुषों के बीच भी उतनी ही आम है। मोटे तौर पर, प्लास्टिक सर्जरी को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है- कॉस्मेटिक सर्जरी, जो दिखावट को निखारती है, और पुनर्निर्माण सर्जरी, जो चोटों, बीमारियों या जन्म दोषों से होने वाले नुकसान की मरम्मत करती है। भारत अपने उच्च योग्य चिकित्सा पेशेवरों, उन्नत उपकरणों और लागत प्रभावी उपचारों के साथ, चिकित्सा पर्यटन में एक बड़ी छलांग लगाने के लिए अच्छी स्थिति में है।

भारत में उपचार की लागत अमेरिका की तुलना में लगभग एक-चौथाई है, गुणवत्ता से समझौता किए बिना। यदि भारत रणनीतिक रूप से इस क्षेत्र को मजबूत करता है, तो रोगी थाईलैंड, सिंगापुर, चीन और जापान जैसे प्रतिस्पर्धियों की तुलना में भारत को अधिक पसंद करेंगे, जो चिकित्सा पर्यटकों के लिए भी होड़ कर रहे हैं। चिकित्सा पर्यटन वैश्विक स्तर पर कई अरब डॉलर का उद्योग है। एक बड़ा हिस्सा हासिल करने के लिए, भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अस्पताल और क्लीनिक विकसित करने चाहिए, कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स और प्रत्यारोपण जैसे क्षेत्रों में विशेष देखभाल प्रदान करनी चाहिए और टेलीमेडिसिन और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को अपनाना चाहिए। भारत की बाजरा-आधारित चिकित्सा भी एक अनूठी बढ़त प्रदान करती है। पद्म श्री पुरस्कार विजेता डॉ. खादर वली का दावा है कि बाजरा बिना किसी दवा के छह सप्ताह से छह महीने के भीतर सबसे गंभीर बीमारियों को भी ठीक कर सकता है। इस तरह के अनूठे दृष्टिकोण, सरकार से मजबूत नीति समर्थन के साथ, भारत की चिकित्सा पर्यटन क्षमता को और बढ़ा सकते हैं। मार्केटिंग अभियान, रोगी-केंद्रित पैकेज, वीजा सुविधा, भाषा अनुवाद सेवाएँ और आवास व्यवस्थाएँ भारत को अंतर्राष्ट्रीय रोगियों के लिए अधिक आकर्षक गंतव्य बना सकती हैं। आँकड़े खुद ही अपनी कहानी बयां करते हैं- 2022 में 14 लाख विदेशी रोगी इलाज के लिए भारत आए। 2030 तक सालाना 1 करोड़ अंतरराष्ट्रीय रोगियों को आकर्षित करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने के लिए, भारत को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएँ सुनिश्चित करनी चाहिए और विशेषज्ञता के विशिष्ट क्षेत्रों को विकसित करना चाहिए। उचित योजना और क्रियान्वयन के साथ, भारत खुद को चिकित्सा पर्यटन के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित कर सकता है।

आप की बात

जी-20 में भारत

भारत जी- 20 सम्मेलन में अपने निजी मामलों को भी सुलझाने में दिलचस्पी ले रहा है। सम्मेलन में उपस्थित कई राष्ट्र अध्यक्षों से विवादित मामलों पर सकारात्मक निदान से भारत ने एक तीर कई निशाने साधने की जो कोशिश की है वह अवश्य रंग लाएगी। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी हुआ विचार विमर्श भारत की किसी भी मामले के समाधान के प्रति प्रतिबद्धता जताता है। रियो डी जनेरियो में जी-20 सम्मेलन अपने उद्देश्यों के अलावा सदस्य देशों की आपसी चर्चा विचार विमर्श और सहमति के लिए भी जाना जाएगा। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीएर स्टार्मर से भी मुलाकात की जो भारत के आर्थिक अपराधी विजय माल्या और नीरव मोदी के प्रत्यारोपण को लेकर थी। प्रत्यारोपण का मामला ब्रिटेन ने कानूनी उलझन में डालकर उलझा रखा है। इसके अलावा मोदी ने इटली, फ्रांस, पुर्तगाल और नार्वे के राष्ट्रीय अध्यक्षों से भी भेंट में अहम चर्चाएं की। भारत ने अपने निजी मामलों के अलावा आपसी सार्वजनिक हितों को भी चर्चा में रखा ताकि उन पर सहमति बनाकर समन्वित लाभ सबको मिल सके। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार के लिए अगले साल चर्चा पर बनी सहमति बड़ी उपलब्धि है इससे दोनों देशों के आर्थिक हित सधेंगे ही।

-अमृतलाल मारू, इंदौर

अमेरिकी नीतियां

ट्रंप का पिछला शासन भारत-अमेरिका संबंधों के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। अमेरिका प्रथम नीति के तहत ट्रंप ने अमेरिकी हितों को सर्वोपरि रखा, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक और कूटनीतिक संबंधों में नए आयाम जुड़े। ट्रंप प्रशासन की व्यापार नीतियों ने भारतीय उत्पादों पर भारी आयात शुल्क लगाकर भारतीय उद्योगों को प्रभावित किया। इस्पात और एल्युमिनियम पर शुल्क तथा एच-1बी वीजा नियमों को सख्त बनाने से भारतीय आईटी पेशेवरों और उद्योगों को झटका लगा। उदाहरण के लिए, कई भारतीय कंपनियों को अमेरिकी परियोजनाओं में कटौती करनी पड़ी। हालांकि, इन चुनौतियों ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति दी और घरेलू उद्योगों ने नए बाजार तलाशने शुरू किए। सामरिक दृष्टि से ट्रंप प्रशासन ने भारत के साथ संबंध मजबूत किए। मेजर डिफेंस पार्टनर का दर्जा और क्वाड जैसे मंचों पर भारत की भूमिका को प्रोत्साहन मिला। अपाचे और सीहॉक हेलीकॉप्टर जैसे हथियारों की आपूर्ति ने भारतीय सेना को सशक्त बनाया। लेकिन रूस से एस-400 मिसाइल प्रणाली की खरीद पर अमेरिकी आपत्ति ने भारत की स्वतंत्र रणनीति की अनिवार्यता को स्पष्ट किया। भारत को अमेरिकी निर्भरता कम कर अपने व्यापार और सामरिक संबंधों में संतुलन बनाना होगा। यूरोप, अफ्रीका, और एशिया में नए साझेदार तलाशने होंगे।

-अवनीश कुमार गुप्ता,आजमगढ़

विदेशों पर निर्भरता

1980 के दशक से रोजगार आधारित शिक्षा पर अत्यधिक जोर दिए जाने के कारण भारत विज्ञान की विभिन्न शाखाओं से संबंधित आधारभूत सिद्धांतों के शोध और अध्ययन में पिछड़ सकता है जिससे नए सिद्धांतों के प्रतिपादन, नई खोजों, आविष्कारों आदि में हमारी प्रगति पर प्रभाव पड़ेगा। ऐसी ही चेतावनी कुछ दशकों पूर्व ज्ञान आयोग ने भी दी थी। उदाहरणार्थ, डिजिटल क्षेत्र में हम पहले से बने ऐप्स और सॉफ्टवेयर के उपयोग सीखकर रोजगार पा सकते हैं लेकिन इस क्षेत्र में शोध और रिसर्च किए बिना हम स्वयं ऐप्स और सॉफ्टवेयर बना नहीं सकते। इसीलिए हम अमेरिका और चीन में बने डिजिटल उत्पादों पर काफी हद तक निर्भर रहे हैं। इस निर्भरता के भयानक और दूरगामी नुकसान हो भी रहे हैं और भविष्य में अत्यधिक खतरों का सामना करना पड़ सकता है। डिजिटल क्षेत्र के अलावा भौतिक, रसायन, चिकित्सा, कृषि, खगोल आदि विज्ञानों में हम पिछड़ते जाएंगे। पहले ही इन विज्ञानों में नोबल पुरस्कार हम ने 2 बार ही प्राप्त किए हैं। यदि हमने दवाइयों के शोध नहीं किए तो विदेशी दवाइयों पर निर्भर रहेंगे। वे देश षडयंत्रपूर्वक हमें दवाइयों के रूप में जेनेटिक समस्याएं दे सकते हैं। 1960 के दशक में आयातित अनाजों के साथ कितनी समस्याएं भी आई थी। हमें विदेशी निर्भरता से बचना होगा

- ललित दुबे, रतलाम

शीर्ष पर महिला हॉकी

भारत की महिला हॉकी टीम कप्तान सलीमा टेटे की अगुवाई में एशियन हॉकी चैंपियनशिप में चीन को 1-0 से हराकर एशियन हॉकी चैंपियनशिप का खिताब भारत के नाम किया। बिहार के राजगीर में खेले गए इस चैंपियनशिप के लिए चीन, जापान, मलेशिया और कोरिया की टीमों से लोहा लेते हुए देश की बेटियों ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। भारत ने सेमी फाइनल के कड़े मुकाबले में जापान को 2-0 से हराकर फाइनल प्रवेश किया था। इससे पहले भारत ने मलेशिया, कोरिया,थाईलैंड, जापान और चीन को हरा कर भारत की टीम अजेय साबित हुई थी। इस टूर्नामेंट में दीपिका कुमारी ने 11 गोलकर शानदार व्यक्तिगत सफलता अर्जित की और अंत में फाइनल मैच में भी दीपिका ने एकमात्र विजय गोल दाग कर भारत को विजय दिलाई। भारत के खिलाड़ियों ने अपने प्रथम मैच से ही साहसिक अभियान की शुरुआत की थी। भारत की महिला हॉकी की टीम ने 150 करोड़ भारतीयों की आशा और आकांक्षा के अनुरूप खेल कर भारत का नाम रोशन किया है। हमारी टीम को सरकार की ओर से और सुविधाएं मिलनी चाहिए।

-वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से
responsemail.hindipioneer@gmail.com
पर भी भेज सकते है।

भारत की गिनती तेजी से विकास कर रहे देशों में होती है। युद्ध और नाना प्रकार के संकट से घिरी दुनिया में चंद ही देश हैं, जिनकी विकास दर भारत से बेहतर है। भारत के पास खुशी मनाने के अनेक मुद्दे हैं, पर ध्यान रहे, आगे की तेज यात्रा के लिए चुनौतियां भी कम नहीं हैं। क्या अभी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा परेशानी में है? आर्थिक दबाव के क्या कारण हैं? मध्यम वर्ग किन हालात से गुजर रहा है? गांवों और शहरों की क्या भूमिका है? पेश है, ऐसे सवालों के जवाब तलाशती **अभिषेक मुखर्जी** की रिपोर्ट ...

ताकि खर्च करने से हाथ न खींचें लोग

दक्षिणी दिल्ली में विशाल तुगलकाबाद किले के खंडहरों के ठीक सामने सुंदर रूप में संरक्षित बलुआ पत्थर और संगमरमर का एक मकबरा है। 14वीं सदी की शुरुआत में बना यह मकबरा दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक का है।

गयासुद्दीन का जीवन गरीब से अमीर होने की आदर्श गाथा है। उन्होंने एक व्यापारी के घर नौकर के रूप में जिंदगी की शुरुआत की थी। शाही सेना में नौकरी पाने से पहले वह काफी समय दिल्ली में भटकते रहे थे। सेना में बहाली के बाद वह लगातार तरक्की पाते गए और इतने शक्तिशाली हो गए कि शाही खानदान के झगड़ालू उत्तराधिकारियों को उखाड़ फेंका। दिल्ली के सुलतान हो गए। परिकथा जैसी उनकी जिंदगी अत्यधिक क्रूरता, कट्टरता और मध्ययुगीन बर्बरता से भी लैस थी, लेकिन जो गुण उन्हें दूसरों से अलग करता था - वह था उनका प्रशासनिक ज्ञान। आम लोगों के बीच से गुजरते हुए ऊपर उठे गयासुद्दीन लोगों की समस्याओं से भली-भांति परिचित थे। इससे भी खास बात यह थी कि उनमें आम लोगों के प्रति सहानुभूति थी। उनके नीति निर्धारण में राज्य हित और जन कल्याण के बीच बेहतर संतुलन की कोशिश दिखती थी।

मिसाल के लिए, उन्होंने न सिर्फ पिछले सुलतान द्वारा लगाए गए करों के बोझ को काफी हद तक कम कर दिया, बल्कि सूखे के वर्षों के दौरान भी कर माफ कर दिया था। साथ ही, सुरक्षा बढ़ाने के लिए ग्रामीण इलाकों में सिंचाई के लिए नहरों की खुदाई करवाई थी और किलों के निर्माण जैसी बुनियादी ढांचागत परियोजनाएं शुरू की थीं। गयासुद्दीन ने आश्चर्यजनक रूप से आधुनिक

जहां तक आवास या मकान की बात है, तो जितना कम कहा जाए, उतना बेहतर है। बड़े शहरों में आवास या घरों की कीमतों ने घर की तलाश में लगे लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। बड़े शहरों में लोग जो कमाते हैं, उसका लगभग 22 प्रतिशत आवास के लिए खर्च करते हैं। हम जानते हैं कि रियल एस्टेट की कीमतें बढ़ गई हैं, किराए बढ़ गए हैं। यह बदलाव बड़े शहरों में अधिकांश उपभोक्ताओं के लिए तनाव पैदा कर रहा है। आम लोगों के खर्च में शिक्षा और चिकित्सा व्यय को भी जोड़ लिया जाए, तो आम आदमी पर आर्थिक दबाव खतरनाक अनुपात तक बढ़ जाता है।

आर्थिक फरमान जारी किए थे। उन्होंने अपने राजस्व अधिकारियों से कहा था कि अत्यधिक कराधान और राजाओं की अत्यधिक मांगें तरक्की के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं।

आज के दौर में देखें, तो शायद इस समय ऐसा कोई समूह या वर्ग नहीं है, जो तरक्की संबंधी दबाव को महसूस नहीं कर रहा है। यह अनुभव वास्तव में भारतीय शहरी मध्यवर्ग के बीच मजबूती से गूंज रहा है। मध्यम वर्ग में मांग घटने के संकेत कारपोरेट क्षेत्र में भी लगातार दिख रहे हैं। हाल ही में समाप्त दूसरी तिमाही के आंकड़ों में भी यह बात साफ तौर पर सामने आई है कि शहरी भारत में आर्थिक संकट के संकेत दिख रहे हैं, जिनका समाधान करना होगा।

भारत की सबसे बड़ी फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) अर्थात रोजमर्रा की उपभोक्ता वस्तुओं का सर्वाधिक निर्माण करने वाली कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने सितंबर में बीती तिमाही में साल-दर-साल आधार पर 3.86 प्रतिशत की कमी के साथ 2,612 करोड़ रुपये की गिरावट दर्ज की है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और प्रबंध निदेशक (एमडी) रोहित जावा बताते हैं कि हमने हर जगह मांग में कमी देखी है। यह शहरी विकास में गिरावट की प्रवृत्ति है, खासकर ऐसे बड़े शहरों में, जो कुछ समय से एफएमसीजी विकास का इंजन बने हुए हैं।

यूनिलीवर की प्रतिद्वंद्वी कंपनी, नेस्ले इंडिया ने भी कमजोर आंकड़े दर्ज किए हैं। उसके राजस्व वृद्धि में एक प्रतिशत की तेज गिरावट आई है। कंपनी के चेयरमैन और एमडी, सुरेश नारायणन ने इसके लिए सिकुड़ते मध्यम वर्ग को जिम्मेदार ठहराया है, जो परंपरागत रूप से एफएमसीजी कंपनियों का विकास इंजन रहा है। नारायणन बताते हैं कि बाजार को धीमी मांग का सामना करना पड़ रहा है। नारायणन ने पिछले महीने संवाददाताओं से कहा था कि खाद्य और पेय पदार्थ क्षेत्र में वृद्धि, जो पहले दोहरे अंक में हुआ करती थी, अब घटकर 1.5 प्रतिशत से 2 प्रतिशत रह गई है।

वह यह भी बताते हैं कि दूसरे स्तर या उससे नीचे के शहर में बाजार काफी हद तक स्थिर लगते हैं, ग्रामीण बाजार भी काफी हद तक स्थिर हैं, दबाव केवल बड़े शहरों और महानगरों में पड़ रहा है। बड़े शहरों में अभी मांग की जो स्थिति है, उसकी तस्दीक दूसरी कंपनियां भी कर रही हैं। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने शहरी मांग में नरमी बताई है, तो आईटीसी समूह ने बताया है कि वाहन बिक्री, बैंक ऋण और व्यक्तिगत ऋण वृद्धि, क्रेडिट कार्ड लेनदेन की मात्रा, जीएसटी संग्रह, उत्पाद निर्यात वृद्धि और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में भी गिरावट के संकेत हैं।

अगस्त और सितंबर में अत्यधिक बारिश हुई है और खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ी हैं, जिसके कारण महंगाई 9 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। खाद्य पदार्थों की कीमतों ने रोजमर्रा की वस्तुओं पर होने वाले खर्च को प्रभावित किया है। ध्यान रहे, एफएमसीजी क्षेत्र की कुल बिक्री में शहरी भारत की हिस्सेदारी लगभग दो-तिहाई है और ऐसे में, इस क्षेत्र में किसी भी तरह की कमी के संकेत वास्तव में खतरे की घंटी से कम नहीं हैं।

हालांकि, ऐसा नहीं है कि मांग में कमी केवल उपभोक्ता वस्तुओं तक ही सीमित है। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता मारुति सुजुकी, जिसने सालाना 0.4 प्रतिशत की राजस्व वृद्धि दर्ज की, ने वित्तीय वर्ष की पहली छमाही के दौरान ग्रामीण बिक्री में लगभग 8 प्रतिशत की वृद्धि देखी, जबकि शहरी बाजार में 2 प्रतिशत की गिरावट आई। शहरों में ऑटो बिक्री में भी गिरावट है, जबकि ग्रामीण बाजार में वृद्धि दर्ज की गई। सीमेंट निर्माताओं और पेंट कंपनियों से लेकर शराब निर्माताओं व त्वरित सेवा रेस्तरां संचालकों तक मांग में कमी देखी गई है।

एक कार और मकान का मालिक होना महान भारतीय मध्यम वर्ग का अंतिम सपना माना जाता है। दोनों मोर्चों पर, उपभोक्ताओं के एक बड़े समूह से सपना दूर होता जा रहा है। कार के मामले में तो ऐसा है कि कार की बिक्री से सरकार खूब कमाती है, जबकि कार निर्माता कंपनी को कम फायदा होता है। एक कार बिकती है, तो कर और उपकर मिलाकर सरकार करीब 30 प्रतिशत तक राशि वसूल लेती है, जबकि कार निर्माता कंपनी की जेब में 10 प्रतिशत राशि ही पहुंचती है। यह संकेत है कि व्यवस्था में कुछ खामी है। आप भले ही कार खरीदने की वजह से एक बार की वित्तीय मार झेल लें, पर प्रति लीटर पेट्रोल पर 50 प्रतिशत से अधिक कर भुगतान करना कड़वी गोली है। सरकार ने पेट्रोल में इथेनॉल मिलाना अनिवार्य कर दिया, पर ईंधन की कीमतों में कमी का कोई संकेत नहीं है।

जहां तक आवास की बात है, तो जितना कम कहा जाए, उतना बेहतर है। बड़े शहरों में आवास या घरों की कीमतों ने घर की तलाश में लगे लोगों को मुश्किल में डाल रखा है। बड़े शहरों में लोग जो कमाते हैं, उसका लगभग 22 प्रतिशत आवास के लिए खर्च करते हैं। हम जानते हैं कि रियल एस्टेट की कीमतें बढ़ गई हैं, किराए बढ़ गए हैं। यह बदलाव बड़े शहरों में अधिकांश उपभोक्ताओं के लिए तनाव पैदा कर रहा है। आम लोगों के खर्च में शिक्षा और चिकित्सा व्यय को भी जोड़ लिया जाए, तो आर्थिक दबाव खतरनाक अनुपात तक बढ़ जाता है।

आनंद राठी वेल्थ के निदेशक और प्रमुख, उत्पाद और अनुसंधान अधिकारी, चेतन शेनॉय ने मिंट को बताया है कि बढ़ती कीमतें खर्च लायक आय को खत्म कर दे रही हैं, जिससे लोग अपने खर्च को लेकर अधिक सतर्क हो गए हैं। ज्यादातर लोग कीमती चीजों की खरीद को टालने लगे हैं। चेतन शेनॉय यह भी बताते हैं कि बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक परियोजनाओं पर धीमे सरकारी खर्च ने भी आर्थिक गतिविधियों को कम करने में योगदान दिया है, जिसका परोक्ष असर उपभोग पर पड़ रहा है। बेशक, सुधार के कई उपाय सरकार के हाथ में हैं।

mint

विकास और आय बढ़ाने की जरूरत

भारतीय अर्थव्यवस्था में इस मोड़ पर आर्थिक विकास में तेजी लाने के साथ ही लोगों की आय बढ़ाने के उपाय करने की जरूरत है। विशेष रूप से शहरों में सरकारी के साथ ही निजी निवेश बढ़ाने की जरूरत है। जब देश को निकट भविष्य में विकसित बनाने का लक्ष्य है, तो राजनीतिक दलों को ठोस आर्थिक नीतियों के साथ सामने आना चाहिए। कौशल विकास की योजनाओं को और पुख्ता करने की जरूरत है।

गांव हों और बेहतर

गांवों में मनरेगा ने काम किया है। आम श्रमिकों की कमाई बढ़ी है। शहरी श्रमिकों की तुलना में ग्रामीण श्रमिक ज्यादा सुखी हैं। उनकी आय भी ठीक हो रही है और उनका खर्च भी बढ़ रहा है। देश में अनेक कंपनियां ग्रामीण बाजार के जरिए ही अपना व्यवसाय चला रही हैं।

शहरों में हो ज्यादा सुधार

मनरेगा जैसी योजना शहरों में भी पुरजोर ढंग से लागू होनी चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि शहरी श्रमिकों की आय, भत्ते, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा और आवास के बारे में तार्किक रूप से नहीं सोचा जा रहा है। शहरों में आवास खरीदना श्रमिकों की आय क्षमता से बहुत बाहर की बात है। खासकर बड़े शहरों में श्रमिकों की संख्या बहुत ज्यादा है और अगर इस वर्ग की आय को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो अर्थव्यवस्था में मांग को यथोचित बल नहीं मिलेगा।

भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार और बढ़ाने की जरूरत

रोजमर्रा के उपभोक्ता उत्पाद बनाने वाली (एमएमसीजी) कंपनियों ने विगत वर्ष में शहरी बाजारों में कम मांग का सामना किया है। निफ्टी शेयर बाजार में भी इस पहलू को देखा जा सकता है।

निजी खपत में आई कुछ कमी

भारत के सकल घरेलू उत्पाद में निजी खपत खर्च (पीएफसीई) का हिस्सा घटा है।

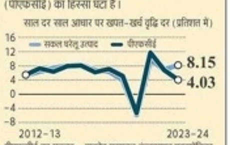

पीएफसीई का मतलब - प्राइवेट फायनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इससे पता चलता है कि देश में लोग कितना खर्च कर रहे हैं।

कार की बिक्री में भी ज्यादा गति नहीं

लॉक डाउन का साया पूरी तरह से खत्म हो गया है, लेकिन लोगों की आय और कार रखने की कम क्षमता के चलते कार की बिक्री मे ज्यादा तेजी नहीं आ रही है।

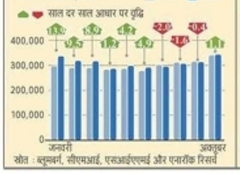

स्रोत : ब्लूमबर्ग, सीएमआई, एसआईएएमई और एनारॉक रिसर्च

फिर भी बढ़ते जा रहे मकान के दाम

पिछले वर्ष में देश के टॉप 7 शहरों में मकान या आवास की कीमत में औसतन 23 प्रतिशत की उछाल देखी गई है।

12.3
लाख रुपये है प्रति व्यक्ति आय संपन्न वर्ग में, जिसमें देश के करीब 12 करोड़ लोग शामिल हैं।

2.5
लाख रुपये है प्रति व्यक्ति आय मध्यम वर्ग में, जिसमें देश के करीब 30 करोड़ लोग शामिल हैं।

1.7%
की दर से बढ़ रही ग्रामीण भारत में श्रमिकों की मजदूरी। शहरों की तुलना में गांवों की स्थिति ठीक।

0.5%
घटी है शहरी वेतनभोगी श्रमिकों की वास्तविक कमाई साल 2011-12 के बाद से प्रति वर्ष।

मध्यम वर्ग में कौन?

यूगोव-मिंट-सीपीआर मिलेनियल के एक सर्वे में शामिल 88 प्रतिशत लोगों ने खुद को मध्यम वर्ग का माना है। हालांकि, प्रति माह 50,000 रुपये से कम कमाने वाले भी खुद को मध्यम वर्ग में मानते हैं। सर्वे में शामिल इस आय वर्ग के 90 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वे मध्यम वर्ग है, लेकिन 4 लाख रुपये प्रति माह से अधिक कमाने वालों में से 57 प्रतिशत ने भी खुद को मध्यम वर्ग का माना है। क्या इस मध्यम वर्ग को समझने के लिए भारत में कोई बेहतर रूपरेखा है? एक सुनिश्चित पैमाना बनाकर काम करने की जरूरत है।

तीन तरह के भारतीय

ब्लूम वेंचर्स के मुताबिक, भारत के उपभोक्ताओं को तीन वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला, संपन्न वर्ग है, जिसमें लगभग 3 करोड़ परिवार या 12 करोड़ लोग शामिल है, जिनमें प्रति व्यक्ति आय लगभग 12.3 लाख रुपये है और यह देश का मुख्य उपभोक्ता वर्ग है। उसके नीचे आकांक्षी वर्ग है, जिसमें 30 करोड़ लोग शामिल हैं, जिनकी प्रति व्यक्ति आय लगभग 2.5 लाख रुपये है। पिरामिड के सबसे निचले-तीसरे वर्ग में भारत की अधिकांश आबादी है, जिसके पास किसी भी ऋण-ब्याज की गारंटी देने योग्य कमाई नहीं है।

असमानता घटाना जरूरी

भारत का संपन्न वर्ग देश में प्रदूषण को लेकर चिंतित नहीं है, वह अवसर मिलते ही यूरोप या ऐसे देशों में चला जा रहा है, जहां स्थितियां आरामदेह हैं। दूसरी ओर, मध्यम वर्ग और निचले वर्ग के लोग अपने जरूरी खर्चों में कटौती करने को मजबूर हैं। आय के मोर्चे पर अगर देखें, तो नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार, 2017-18 और 2022-23 के बीच श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी मे प्रति वर्ष केवल 0.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

रोजनामचा

पं. राघवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

स्कैन करें
भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

मेष : आत्मविश्वास में कमी रहेगी। मन परेशान भी हो सकता है। संतान की सेहत का ध्यान रखें। भागदौड़ अधिक रहेगी। रहन-सहन अव्यवस्थित रहेगा।

वृष : मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। परिवार का साथ मिलेगा। कारोबार में भागदौड़ अधिक रहेगी। कुछ कठिनाई भी आ सकती हैं। पिता का साथ मिलेगा।

मिथुन : मन अशांत रहेगा। मन में बुरे विचारों से बचें। परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। वस्त्रों आदि पर खर्च बढ़ सकते हैं। भागदौड़ अधिक रहेगी।

कर्क : धैर्यशीलता में कमी रहेगी। आत्मसंयत रहें। लेखनादि बौद्धिक कार्यों में व्यस्तता बढ़ेगी। मान-सम्मान की प्राप्ति होगी। परिवार की सेहत का ध्यान रखें।

सिंह : वाणी में सौम्यता रहेगी। नौकरी में बदलाव के अवसर मिल सकते हैं। किसी दूसरे स्थान पर भी जा सकते हैं। किसी मित्र का सहयोग मिलेगा। आय में वृद्धि होगी।

कन्या : मन प्रसन्न तो रहेगा। लेकिन, मन में बुरे विचारों से बचें। कारोबार में व्यस्तता बढ़ेगी। परिश्रम भी अधिक रहेगा। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी।

तुला : मन परेशान रहेगा। परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। कुटुंब के किसी बुजुर्ग से धन मिल सकता है। पिता की सेहत का ध्यान रखें। खर्चों में वृद्धि होगी।

वृश्चिक : आत्म संयत रहें। अपनी भावनाओं को वश में रखें। परिवार में शांति बनाए रखने के प्रयास करें। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा।

धनु : मन परेशान रहेगा। शैक्षिक कार्यों में बाधा आ सकती है। सचेत रहें। नौकरी में कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। परिश्रम अधिक रहेगा।

मकर : आत्म संयत रहें। क्रोध के अतिरेक से बचें। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार में वृद्धि होगी। पिता की सेहत का ध्यान रखें। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी।

कुंभ : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। नौकरी के लिए परीक्षा व साक्षात्कार कार्य में सफल रहेंगे। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। आय में वृद्धि होगी।

मीन : मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। नौकरी में तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। कार्यक्षेत्र में वृद्धि होगी। पर, स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। वाहन सुख में वृद्धि होगी।

व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋभुकांत गोस्वामी

27 नवंबर, बुधवार, शक संवत्: 06 मार्गशीर्ष (सौर) 1946, पंजाब पंचांग: 12 मार्गशीर्ष मास प्रविष्टे 2081, इस्लाम : 24 जमादि-उल-अव्वल 1446, विक्रमी संवत्: मार्गशीर्ष कृष्ण द्वादशी तिथि रात्रि 06.24 बजे तक (सूर्य उदय से पहले) तक पश्चात त्रयोदशी तिथि, चित्रा नक्षत्र (दिन रात)। कौलव करण। चन्द्रमा कन्या राशि मे सायं 06.07 बजे तक उपरांत तुला राशि में।
सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। हेमंत ऋतु। दोपहर 12 बजे से दोपहर 01. 30 बजे तक राहुकालम्।

वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

हमारी शादी को 12 साल हो गए हैं। हमारे अभी तक कोई संतान नहीं है। कृपया कोई उपाय बताएं।
-सोनिया, दरभंगा

- घर की पूर्व उत्तर पूर्व दिशा में एक हंसते हुए शिशु का चित्र लगाएं। घर के दक्षिण पूर्व में कोई ऐसी चीज हो जैसे पानी की टंकी, शौचालय, वॉशिंग मशीन तो उसे हटा दें।
- नियमित रूप से भगवान शिव एवं श्रीकृष्ण की पूजा करें। श्रीकृष्ण के बाल रूप का एक चित्र शयन कक्ष में एक ऐसे स्थान पर लगाएं, जहां से वे हर समय दिखाई दें।
- नियमित संतान गोपाल मंत्र का जाप करें तथा हवन करें। कई बार पितृ दोष के कारण संतान उत्पत्ति में बाधा होती है। अमावस्या को पितरों के निमित्त श्राद्ध करें।

वर्ग पहेली : 7798

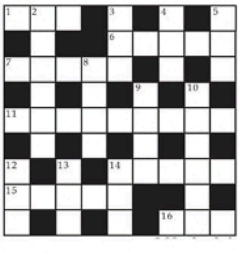

बाएं से दाएं

1. ज्ञान; समाचार; खबर; जानकारी (3)
6. धार बंधना; लगातार बरसना; हल्की परंतु निरंतर वर्षा होना (2,3)
7. टकराने का भाव; टक्कर; टकराव; भिड़ंत (5)
11. अंधकार से प्रकाश की ओर चलो; अंधेरे से ज्योति प्रकाश की ओर जाइए (3,1,5)
14. पूछना; खोज करना; जानना; ज्ञात करना; तथ्यान्वेषण करना (2,3)
15. हाव भाव; चटक मटक (2,3)
16. ऊंचा स्तंभ; लाट (3)

ऊपर से नीचे

2. चमक दमक, चटक मटक; तड़क भड़क; आभा; कांति; शान (3,3)
3. असुविधा; झमेला; बखेड़ा; विघ्न (3)
4. पिघली हुई धातु आदि को सांचे में डाल कर कोई आकार देना (3)
5. असहाय; आश्रयहीन; दीन; लावारिस; मातृ-पितृ विहीन (3)
8. अंजनीसुत; केसरी नंदन; वायुपुत्र (4)
9. पति में अनन्य श्रद्धा रखने वाली; अपांशुला; एकचारिणी; शीलवती (4)
10. तत्व या पूंजी न रहना; शरीर अशक्त होना (2,1,3)
12. आभूषण बनाने वाला; स्वर्णकार (3)
13. मानदंड; स्तर (3)
14. पुष्परज; फूल के केसर पर जमी धूल (3)

हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली
(उत्तर अगले अंक में)

वर्ग पहेली : 7797

1 का	■	2 ए	■	3 चि	त	4 क	ब	रा
5 न	म	की	न	■	■	रा	■	■
ख	■	कृ	■	■	6 त	ह	ल	7 का
ड़े	■	8 त	रा	9 ना	■	ना	■	र
10 के	द	■	■	श	■	■	11 शो	ग
र	■	12 भ	■	13 के	ल	14 क	■	र
15 ना	रा	ज	गी	■	■	ह	■	ब
■	■	बू	■	■	16 जं	क	ड़	ना
17 त	म	त	मा	ना	■	हा	■	ना

सुडोकू : 7780

* आसान

	1					8		
	7		6				4	5
3				2	9			
		9	4		1		3	
		1		8		2		
	3		2		5	1		
			9	6				2
7	2				3		8	
		5					1	

खेलने का तरीका : दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3x3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

सुडोकू : 7779

6	4	7	8	2	5	3	1	9
5	3	9	6	1	4	7	2	8
1	2	8	9	7	3	5	4	6
4	7	2	5	9	1	6	8	3
3	5	6	7	4	8	2	9	1
8	9	1	2	3	6	4	5	7
7	6	4	1	5	9	8	3	2
2	1	3	4	8	7	9	6	5
9	8	5	3	6	2	1	7	4

हिन्दुस्तान 1936

संविधान की शक्ति

देश का संविधान अपनी हीरक जयंती मना रहा है, तो इस अवसर पर संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित समारोह के महत्व और जम्मू-कश्मीर में पहली बार संविधान दिवस मनाए जाने के निहितार्थ बखूबी समझे जा सकते हैं। भारत और इसके नागरिकों के लिए यह वाकई गर्व की बात है कि जब-जब देश को जरूरत पड़ी, उसके पुरखों द्वारा वर्षों की मेहनत से तैयार इस पवित्र और सुदीर्घ ग्रंथ ने देश व देशवासियों का मार्गदर्शन किया। देश के लोग अपने संविधान से कितने जुड़े हैं और उनकी निगाह में इसका क्या सम्मान है, हालिया आम चुनाव के जनादेश ने शिद्दत से इसका एहसास कराया है। इसलिए राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान की ताकत को रेखांकित करते हुए उचित ही कहा कि 'बदलते समय की मांग के अनुसार नए विचारों को अपनाने की व्यवस्था हमारे दूरदर्शी संविधान-निर्माताओं ने बनाई थी। हमने संविधान के माध्यम से सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के अनेक बड़े लक्ष्यों को प्राप्त किया है।' गौर कीजिए, जिस वक्त नया आईन तैयार हो रहा था, तब हिन्दुस्तान की आबादी लगभग 36 करोड़ थी, आज यह संविधान 140 करोड़ से अधिक भारतीयों के हितों का संरक्षण कर रहा है।

ऐसा नहीं है कि भारतीय संविधान के आगे चुनौतियां नहीं आईं। संविधान को लागू हुए जितने साल गुजरे हैं, उनके मुकाबले यदि अनुच्छेद-356 के उपयोग-दुरुपयोग और निर्वाचित सरकारों की बर्खास्तगी की संख्या को ही गिनें, तो इसकी चुनौतियां स्पष्ट हो जाएंगी। अब तक 130 से भी अधिक बार इस अनुच्छेद का इस्तेमाल किया जा चुका है, फिर सन् 1975 का आपातकाल तो इस पर थोपे गए संकट का सबसे बड़ा उदाहरण है। कई बार विधायिका व न्यायपालिका में, तो कई बार कार्यपालिका व न्यायपालिका के बीच तनातनी की स्थितियां बनीं, मगर हरेक बार संविधान ने ही रास्ता दिखाया और मर्यादित समाधान निकल सके। अनुच्छेद-356 के दुरुपयोग पर अब वैधानिक अंकुश लग चुका है, जिससे संघीय ढांचा मजबूत हुआ है। दो दिन पहले ही संविधान की प्रस्तावना से 'समाजवादी' और 'पंथनिरपेक्ष' शब्दों को निकालने के लिए दायर याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की, वह आश्वस्त करती है कि संविधान के बुनियादी ढांचे के साथ किसी किस्म की दुस्साहसिक छेड़छाड़ मुमकिन नहीं है।

भारत और भारतीयों के लिए यह गर्व की बात है कि जब-जब देश को जरूरत पड़ी, उसके पुरखों द्वारा वर्षों की मेहनत से तैयार इस पवित्र ग्रंथ ने उसका मार्गदर्शन किया है।

हमारे इर्द-गिर्द के लोकतंत्रों की दुर्दशा भी बताती है कि भारतीय संविधान के निर्माता कितने दूरदर्शी और काबिल लोग थे। हमारे साथ ही आजाद हुए कई पड़ोसी लोकतंत्र, जो तब आर्थिक मोर्चे पर हमसे कहीं बेहतर स्थिति में थे, आज दिवालिया होने के मुहाने पर हैं, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। निस्संदेह, भारतीय लोकतंत्र की कामयाबी और इसकी राजनीतिक स्थिरता का इसमें बड़ा योगदान है। जिस सहजता के साथ यहां सत्ता का हस्तांतरण होता रहा और इसके राजनीतिक वर्ग ने लोकतांत्रिक मूल्यों का निबाह किया है, वह दुनिया के लिए नजीर है। जाहिर है, यह स्थिति भारतीय संविधान ने सुनिश्चित किया कि हाशिये की आवाज भी केंद्र तक अबाध पहुंचे। राजसत्ता के शीर्ष पर द्रौपदी मुर्मु की उपस्थिति ही बता रही है कि भारतीय संविधान ने जिन तबकों के उत्थान का सपना संजोया है, पचहत्तर वर्षों में उनकी जिंदगी में कितना बदलाव आया है। इसलिए सौ से अधिक संशोधनों के बाद भी भारतीय संविधान की आत्मा अक्षुण्ण है और यह भारतीय गणतंत्र का आधार है।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 27 नवंबर, 1949

ऐतिहासिक कार्य की पूर्णाहुति

हमारे विधान निर्माताओं ने भारतीय प्रजातंत्र का विधान बनाने का दुस्तर कार्य आज से २ वर्ष ११ महीने और १७ दिन पूर्व प्रारंभ किया था, उसकी सफल पूर्णाहुति कल हो गई। विधान परिषद में इस अवसर पर प्रसन्नता का वातावरण था और वह स्वाभाविक ही था। किसी भी बड़े कार्य की निर्विघ्न समाप्ति पर प्रसन्नता ही अनुभव की जा सकती है। एक समय था, जब देश का भाग्य विदेशी शासकों के हाथों में था। वही देश का शासन विधान बनाते थे और उसके अनुसार ही हम पर शासन करते। इस पराधीनता के विरुद्ध हमने बगावत की; हमने अपने भाग्य का फैसला करने के विदेशियों के अधिकार को चुनौती दी। हमने मांग की कि हमको अपने भाग्य का फैसला करने का हक होना चाहिए; अर्थात् हमको आत्म-निर्णय का अधिकार मिलना चाहिए। हमने अपने आत्म-निर्णय के अधिकार को मनवाने के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसक संघर्ष चलाया और उसका नतीजा यह आया कि विदेशी शासकों ने हमारा आत्म-निर्णय का अधिकार स्वीकार किया। हमारी मांग थी कि देश का विधान बनाने के लिए बालिग मताधिकार पर विधान परिषद का चुनाव हो। किन्तु परिस्थितियों ने यह संभव नहीं होने दिया। किन्तु जो विधान परिषद अस्तित्व में आई, उसने देश के व्यापक से व्यापक लोकमत का प्रतिनिधित्व किया, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह विधान भारत की ३२ करोड़ जनता की सहमति से बना है और उसके अनुसार बनने वाली सरकार लोगों की, लोगों के लिए और लोगों द्वारा चलने वाली सरकार होगी। विधान परिषद के जिन सदस्यों ने यह विधान तैयार किया है, वे अपने परिश्रम के लिए देशवासियों के अभिनन्दन के पात्र हैं। डा. राजेन्द्र प्रसाद की भी इस अवसर पर सराहना करनी पड़ेगी, जिन्होंने पूरी योग्यता और निष्पक्षता के साथ विधान परिषद का कार्य संचालन किया।

जब यह विधान तैयार हो रहा था, तो देश के एकीकरण की प्रक्रिया भी साथ-साथ जारी थी। वह क्रिया विधान की पूर्णाहुति के साथ ही पूरी हुई है। भारत के नक्शे पर जो सैकड़ों छोटी-बड़ी कई स्वतंत्र रियासतें बिखरी हुई थीं और जिनका उस रूप में अस्तित्व देश की स्वतंत्रता के लिए खतरा हो सकता था, उन्हें देश के राजनीतिक ढांचे में यथास्थान फिट कर दिया गया है।

प्रदूषण के समय बच्चों की परवाह

संघमित्रा शील आचार्य | प्रोफेसर, जेएनयू

दिक्कत यह है कि हम कुछ दिनों तक तो संवेदनशीलता दिखाते हैं, विशेषकर सर्दियों की शुरुआत में, लेकिन जैसे ही हवा कुछ साफ होती है, हम सब कुछ बिसरा देते हैं।

लगातार बढ़ते-घटते प्रदूषण के बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्कूलों को हाइब्रिड (ऑनलाइन-ऑफलाइन, दोनों) तरीके से चलाने का फैसला तो कर लिया गया है, लेकिन इसकी चुनौतियां भी कम नहीं हैं। जब वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) लगातार 400 के ऊपर बना रहे, तो विशेषकर बच्चों के लिए आबोहवा काफी जहरीली बन जाती है। चूंकि वे स्कूल के लिए सुबह-सुबह निकलते हैं और उस वक्त तापमान कम रहने की वजह से प्रदूषक जमीन के नजदीक ही हवा में थमे रहते हैं, इसलिए बच्चों के संक्रमित होने की आशंका बढ़ जाती है। इससे उनका श्वसन तंत्र ज्यादा संवेदनशील बन जाता है और अगर बच्चा अस्थमा जैसी सांस की किसी बीमारी से पीड़ित है, तो उसकी समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। प्रदूषण उन बच्चों के लिए और अधिक कष्टप्रद बन जाता है, जिनका बसेरा सड़कों के किनारे है। एक आकलन है कि ट्रैफिक से बच्चों में फेफड़े का संक्रमण 25 फीसदी तक बढ़ सकता है।

दरअसल, प्रदूषण से बच्चे कई तरह से परेशान होते हैं। इसका सबसे पहला वार तो गर्भस्थ शिशु पर होता है, जिसका वजन तुलनात्मक रूप से कम हो सकता है, जो अपने देश की पुरानी समस्याओं में से एक है। फिर, कई मामलों में गर्भपात और समय से पूर्व पैदा होने का कारण भी प्रदूषण को माना गया है। अध्ययन यह भी है कि जो बच्चे खदानों के आसपास रहते हैं, उनमें ब्लड कैंसर होने की आशंका ज्यादा होती है। प्रदूषण का दुष्प्रभाव बच्चों की समझ और सीखने की क्षमता पर भी पड़ता है। वैसे भी, वयस्कों की तुलना में बच्चों की श्वसन प्रणाली कहीं ज्यादा संक्रमित होती है, इसलिए प्रदूषण उनकी मुश्किलों को बढ़ा देता है।

मगर स्कूल से बहुत अधिक दिनों तक बच्चों की दूरी भी उचित नहीं। वैसे भी, दिल्ली में प्रदूषण किसी एक दिन की समस्या है नहीं, यह पूरे साल हमें परेशान करता है। हां, सर्दियों में यह खतरनाक स्तर तक बढ़ जाता है। ऐसे में, अच्छा तो यही होगा कि हम स्कूलों को इस कदर विकसित करें कि वहां बच्चे प्रदूषण से कम से कम प्रभावित हों। बड़े निजी स्कूलों में कक्षाएं ही नहीं, कॉरिडोर तक वातानुकूलित होते हैं, उनकी गाड़ियां भी सुरक्षित होती हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों से हम इसकी अपेक्षा नहीं कर सकते। वैसे भी, जब कुल जीडीपी का तीन फीसदी हिस्सा भी हम शिक्षा पर खर्च नहीं कर पा रहे, तब यह कल्पना ही बेमानी है कि सरकारी स्कूल वातानुकूलित होंगे। यह मांग हास्यास्पद ही मानी जाएगी कि हमारी सरकारें स्कूलों में एयर प्यूरीफायर लगाएं। मगर हमें अपने बच्चों का भी ध्यान रखना है, तो एक उपाय उनमें एन-95 या मानक वाले मास्क का वितरण हो सकता है। ये मास्क उनको प्रदूषण के सीधे संपर्क में आने से बचा सकते हैं।

वैसे, इस पूरे मामले का एक पहलू यह भी है कि जो बच्चे अधिक साफ-सफाई या वातानुकूलित वातावरण में रहते हैं, उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता उन बच्चों की तुलना में कम होती है, जो अपेक्षाकृत गंदगी में रहते हैं। हालांकि, इसका यह अर्थ नहीं कि हम अपने बच्चे को साफ-सुथरा न रखें। हम सफाई पर जरूर ध्यान दें, मगर ऐसा करते हुए हम उन्हें प्रकृति से दूर न करें।

तर्क यह भी दिया जाता है कि मध्याह्न भोजन योजना से बच्चे वंचित हो रहे हैं, इसलिए भी उनको स्कूल आना चाहिए। मगर ऐसी मांग करने वाले कहीं न कहीं प्रदूषण को रोकने की अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास रहे हैं। बच्चे के लिए मध्याह्न भोजन जरूरी है, लेकिन उन्हें प्रदूषण के दुष्प्रभावों से बचाना भी उतना ही आवश्यक है। दिक्कत यही है कि हम कुछ दिनों तक तो संजीदगी दिखाते हैं। विशेषकर सर्दियों की शुरुआत में, जब मौसम बदलता और प्रदूषण की धुंध छाने लगती है, लेकिन जैसे ही हवा कुछ साफ होती है, हम सब कुछ बिसरा देते हैं।

हम इस मौसम के प्रदूषण के लिए बड़ी आसानी से किसानों को दोषी ठहराने लगते हैं, लेकिन सड़कों पर गाड़ियों से या विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों से होने वाले प्रदूषण को नजरंदाज कर देते हैं, जबकि ये प्रदूषण के बड़े स्रोत हैं। फिर, पराली की समस्या के लिए भी जिम्मेदार हम खुद हैं। असल में, जलवायु परिवर्तन के कारण फसलों की कटाई और दूसरी फसलों की रोपाई के बीच होने वाली बारिश कम होने लगी है। इसके कारण पराली खेतों में गल नहीं पाती। आईआईटी, कानपुर ने जरूर पराली को रीसाइकिल करने का प्रयोग शुरू किया है, लेकिन केंद्र तक पराली को ले जाने की सुविधा किसानों के पास नहीं है या यह अतिरिक्त लागत भी उनकी जेब पर काफी भारी पड़ेगी। इसीलिए, इस मद में सब्सिडी देने की मांग लगातार की जाती रही है। यह राशि आम लोगों द्वारा स्वास्थ्य पर खर्च की जाने वाली रकम से कम ही होगी, क्योंकि आकलन है कि स्वास्थ्य पर हम अपनी आमदनी की 70-80 फीसदी राशि खर्च कर देते हैं। अमीरों में यह आंकड़ा गरीबों की तुलना में कम है।

साफ है, नीति के स्तर पर प्रदूषण के खिलाफ काम होना चाहिए। कम से कम भविष्य या नई पीढ़ी के लिए तो ऐसा किया ही जाना चाहिए। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने तो एक्शन प्लान भी बनाया है, लेकिन उस पर शायद ही अमल किया जाता है। यह स्थिति तब है, जब कुछ साल पहले दिल्ली के एक वरिष्ठ डॉक्टर ने फेफड़े की दो तस्वीरें जारी करते हुए बताया था कि किस तरह पहाड़ी इलाके के व्यक्ति का फेफड़ा लाल है, जबकि दिल्ली में रहने वाले शख्स का फेफड़ा कत्थई काला हो गया है। यह स्थिति जब वयस्कों की है, तब बच्चों के फेफड़े की कल्पना ही की जा सकती है। विशेषकर यह जानते हुए कि बच्चे के लिए शुरुआती 1,000 दिन काफी अहम होते हैं।

जाहिर सी बात है कि हमारी एजेंसियों को प्रदूषण के खिलाफ न सिर्फ सख्त नीतियां बनानी चाहिए, बल्कि उन नीतियों को पूरी ईमानदारी से लागू भी करना चाहिए। वायु गुणवत्ता सूचकांक जब 100 से नीचे रहता है, तब उसे संतोषजनक माना जाता है, जबकि इस आंकड़े से जैसे-जैसे हम ऊपर उठते जाते हैं, हमारी सेहत के लिए खतरा बढ़ता जाता है। रही बात बच्चों की, तो जन्म के समय यदि किसी बच्चे का वजन 2.5 किलो से कम है, तो यकीनन, इसका एक कारक प्रदूषण भी हो सकता है।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

महिला उद्यमियों को अपनी टीम बनाकर काम करना चाहिए

सौम्या सिंघवानी | प्रोफेसर व अर्थशास्त्री

विश्व स्तर पर महिलाएं ही घरेलू बजट का प्रबंधन कर रही हैं। हालांकि, जब व्यावसायिक बजट या वित्त की बात आती है, तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफी कम नजर आता है। अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि महिलाएं फंड प्रबंधन और कर्ज वापसी में पुरुषों से बेहतर प्रदर्शन करती हैं। इससे पता चलता है कि महिलाओं में ज्यादा वित्त कौशल होता है। ध्यान देने की बात है कि जब व्यवसाय शुरू करने की बात आती है, तो महिलाएं पैसे नहीं मांगती हैं? 898 महिला उद्यमियों के बीच हमारे अध्ययन में हमने पाया कि उनमें से 40 प्रतिशत से भी कम बैंकों से वित्तीय सहायता चाहती हैं। हमारे अध्ययन से यह भी पता चला है कि 60 प्रतिशत से अधिक महिला उद्यमियों को बैंकों से वित्तीय सहायता प्राप्त करते समय कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इससे यह सवाल पैदा होता है कि क्या महिलाएं व्यवसाय के लिए पैसे नहीं मांग रही हैं या उन्हें पैसा मिल ही नहीं रहा है?

हमने पाया कि महिला उद्यमी अक्सर पैसे नहीं मांगतीं, क्योंकि उन्हें अपने वित्तीय ज्ञान पर भरोसा नहीं है। जब कुछ महिलाएं ऋण प्राप्त करने का प्रयास करती हैं, तो ऋण देने वाले पुरुष अधिकारियों की लैंगिक रूढ़िवादिता पुरुषों व महिलाओं में ऋण के असमान वितरण में योगदान करती है। विश्व बैंक का डाटा इसकी पुष्टि करता है, पुरुषों को उनकी जमा राशि के 52 प्रतिशत के बराबर कर्ज मिलता है, जबकि महिलाओं को सिर्फ 27 प्रतिशत। जाहिर है, स्त्रियों के प्रति विश्वास बढ़ाने की जरूरत है, ताकि महिलाओं का आत्मविश्वास भी बढ़े। हमारे अध्ययन के अनुसार, सभी स्तरों और विभिन्न चरणों में उन्हें किसी न किसी चुनौती का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए महिलाओं को प्रोत्साहन की जरूरत है।

उद्यमी महिलाएं परस्पर सहयोग के साथ काम करेंगी, तो वित्त जुटाने और प्रबंधन में एक-दूसरे से सीखकर वे बेहतर काम कर पाएंगी।

वित्तीय रूप से महिलाओं का आश्वस्त होना जरूरी है। झुकने या समझौता करने के बजाय महिलाओं को सबसे पहले, धन संबंधी मामलों पर ऑनलाइन और ऑफलाइन पाठ्यक्रमों या कार्यशालाओं के माध्यम से खुद को वित्तीय रूप से शिक्षित करने की जरूरत है; दूसरा, महिला उद्यमियों को वित्तीय सलाह और सहायता लेने के लिए वित्त क्षेत्र की सक्रिय महिलाओं तक पहुंचना चाहिए। महिला वित्तीय एजेंट महिलाओं की जरूरतों व झिझक के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं और उनकी उद्यमशीलता यात्रा में बेहतर सहायता कर सकती हैं।

उद्यमी महिलाओं को पारिवारिक सहयोग जरूर मिलना चाहिए। कई महिलाओं को एक तरफ घरेलू जिम्मेदारियों की सामाजिक अपेक्षाओं और दूसरी तरफ, एक सफल व्यवसाय चलाने की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। ऐसे में, उनके पास शांत बैठकर विचार करने या विचार जुटाने के लिए समय कम मिल पाता है। ऐसे में, महिलाओं के लिए सबसे जरूरी है कोई ऐसी जगह या कार्यालय, जहां वह समय पर जरूरत के हिसाब से बैठकर विचार कर सकें और अपनी प्राथमिकता तय कर सकें।

अध्ययन में पाया गया है कि कैसे उनकी महिला रिश्तेदार, जैसे उनकी मां व सास उनकी ताकत का स्तंभ बनती हैं। अच्छी सास या अच्छी मां हो, तो उद्यमी महिलाएं अनेक प्रकार की जिम्मेदारियों से बचकर व्यवसाय पर ध्यान दे पाती हैं। उद्यमी महिलाओं को झिझक छोड़कर नेटवर्किंग मजबूत करनी चाहिए। किसी कार्यशाला या दफ्तर के लिए जल्दी तैयार हों। जल्दी पहुंचकर भीड़ होने से पहले ही अपना मुख्य काम या शंकाओं को दूर कर लें। अन्य महिला उद्यमियों को मित्र बनाएं, टीम बनाएं, सहयोग करें, सहयोग लें। अपने काम में साफगोई लाएं। आप कौन हैं, आपको क्या पसंद है, इस बारे में 30 सेकंड का एक संक्षिप्त परिचय तैयार करें और इसे अपने प्रोजेक्ट से जोड़ें और एक उद्यमी के रूप में अपनी जरूरतों को पहचानें।

महिला उद्यमी अपनी एक महिला जनजाति बना लें। अपना एक उद्यमी क्लब बना लें या किसी स्थापित क्लब में शामिल हो जाएं। उद्यमी महिलाएं अगर मिलकर काम करेंगी, तो समस्याओं के समाधान और काम की नई बात सीखने में उन्हें बहुत सुविधा होगी। लैंगिक भेदभाव वाली दुनिया में वे एक साथ तैरकर वित्तीय मामलों में न केवल अपनी ताकत बढ़ा सकती हैं, बल्कि अपने नए सौहार्दपूर्ण संबंधों की बदौलत वित्तीय गहराई को भी अधिक आसानी से दिशा देने में सक्षम हो सकती हैं।

(सह-लेखिका सुदीप्ता शॉ के साथ)

मनसा वाचा कर्मणा

बचपन में मिले सही संस्कार

शिशु को सबसे पहले बतलाया जाए कि यह तुम्हारी माता हैं, यह पिता, यह तुम्हारे दादा-दादी हैं, यह चाचा। सभी श्रेष्ठ भावों को बच्चों को समझाना है। पहले अर्थ बताना है, फिर संस्कार सुदृढ़ करना है। इस संबंध में प्रेरणादायक घटना प्रस्तुत कर रहा हूं।

एक बड़े संत हुए, करपात्रीजी महाराज। परम विद्वान, विरागी थे, उन्हें धर्म सम्राट भी कहा जाता था। जब उनका शरीर पूरा होने लगा, और लगने लगा कि जीवन नहीं बचेगा, तब एक विद्वान, जो पुरी शंकराचार्य श्री निरंजनदेव तीर्थ थे, उनके आग्रह पर उन्हें उपनिषद सुनाते थे और रामानंद संप्रदाय के बहुत बड़े संत थे सीताराम सैन जी, वह उन्हें *वाल्मीकि रामायण* सुनाते थे। दोनों करपात्रीजी के शिष्य थे। एक दिन दोनों ने पूछा कि 'महाराज, आप भागवत की कथा करते हैं और वेदांत का भी प्रवचन करते हैं, श्रीयंत्र की भी पूजा करते हैं, आप अपने प्रवचन से पहले भगवान राम का कीर्तन भी करते हैं- *श्रीराम जय राम जय जय राम।* शिवजी की भी उपासना करते हैं, इससे यह पता नहीं चलता कि आपका सबसे अधिक विश्वास किस मंत्र या किस शास्त्र या किस देवता पर है? आपके परम श्रद्धेय देवता कौन हैं?'

करपात्रीजी महाराज ने टालने की कोशिश की और कहा, 'यह नहीं बतलाया जाता।' दोनों विख्यात शिष्यों ने बार-बार आग्रह किया, प्रिय शिष्य थे। कुछ रुककर करपात्रीजी महाराज ने पूछा, 'कोई प्रिया अपने प्रियतम का नाम बताती है क्या कि मैं बता दूं?' शिष्यों ने फिर पूछा, 'हम जानना चाहते हैं। आप सबकी पूजा करते हैं, किंतु आपके सबसे प्रिय देवता कौन हैं, कौन-सा मंत्र है, किस भगवान का विग्रह है?' करपात्रीजी महाराज ने उत्तर दिया, 'मेरे रामजी सबसे ज्यादा प्रेरक-प्रेरणास्पद हैं।' यह सुनकर शिष्य चकित हुए, फिर प्रश्न किया, 'आप तो संन्यासी हैं, वहां महादेवजी सबसे बड़े देवता हैं, आप भागवत करते हैं, तो कृष्णजी भी आपको प्रिय हैं, यह क्या हुआ?'

करपात्रीजी महाराज ने बताया, 'यह हमारी माताजी की कृपा का चमत्कार है। जब मैंने जन्म लिया, तब मुझे तेल लगाते हुए, गोद में झुलाते हुए, काजल लगाते हुए, जब भी मैं मां के साथ होता था, तब वह कुछ और नहीं बोलती थीं, केवल यही गाती थीं- *श्रीराम जय राम जय जय राम...।* मैंने संसार में आते ही सबसे ज्यादा यही शब्द सुना। मैं बड़ा हुआ, खूब पढ़ता रहा, लेकिन *श्रीराम जय राम जय जय राम,* जो मेरे कानों में गूंजते थे, वे भूले नहीं। फिर मेरा जीवन परम शक्ति? रामजी के लिए समर्पित हो गया कि अब अपनों का भी उद्धार और दूसरों का भी उद्धार करना है।

करपात्रीजी महाराज ने बताया, 'यह हमारी माताजी की कृपा का चमत्कार है। जब मैंने जन्म लिया, तब मुझे तेल लगाते हुए, गोद में झुलाते हुए वह यही गाती थीं- *श्रीराम जय राम जय जय राम...।*

यही शिक्षा है। बच्चों को बचपन में ही सही परिवेश और संस्कार दे दीजिए, तो वे जीवन में आगे कभी न भूलते हैं और न भटकते हैं।

रामानंदाचार्य स्वामी श्रीरामनरेशाचार्य

द्रौपदी मुर्मु | राष्ट्रपति, भारत

लोगों के दुख-दर्द में भागीदार होना साहित्य की पहली शर्त है। दूसरे शब्दों में, मानवता के प्रवाह से जुड़ना साहित्य की कसौटी है। साहित्य वही है, जो मनुष्यता को शक्ति प्रदान करे, समाज को बेहतर बनाए।

संसद में इस तरह हंगामा करना ठीक नहीं

जिन सांसदों ने संसद सत्र के पहले ही दिन एक उद्योगपति के नाम पर हंगामा किया, क्या उन्होंने अपने आस-पास के भ्रष्ट नेताओं को लेकर किसी सत्र में आवाज उठाई है? क्या कोई सांसद भ्रष्ट नहीं होता? एक उद्योगपति को मोहरा बनाकर संसद का कीमती समय बर्बाद करना क्या गलत नहीं है? असल में, यह प्रवृत्ति पिछले कुछ वर्षों से बढ़ती जा रही है। लोकतंत्र के इस मंदिर को राजनीतिक कुश्ती का अखाड़ा बना दिया गया है। नतीजतन, पहले दिन से ही सत्र में हंगामा होने लगता है। यह जानते हुए भी कि हमाम में सब नंगे हैं, विभिन्न दलों के सांसद एक-दूसरे पर कीचड़ उछालने से बाज नहीं आते।

संसद के कीमती समय की कीमत पक्ष और विपक्ष, दोनों को समझनी चाहिए। मगर लाख टके का सवाल यही है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, यानी शांति के लिए कठोरता कौन दिखाए? यहां कोई भी अपने पांव पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहता। इतनी हिम्मत आखिर है किसमें, क्योंकि सभी तो अपनी कुर्सी और सत्ता से नाजायज फायदा उठाते रहे हैं। जैसे-जैसे समय के साथ भारतीय राजनीति में खोट आती गई है और राजनीतिक पार्टियों पर स्वार्थ हावी होता गया है, वैसे-वैसे संसद में काम की बातें कम होती गई हैं और हंगामा बढ़ता गया है। यह किसी भी जीवंत लोकतंत्र की अच्छी तस्वीर नहीं। इससे तो हमारा लोकतंत्र कमजोर ही होगा। अब तो लगने यही लगा है कि संसद देशहित और जनहित का मंच न रहकर, सिर्फ चुनावी रैलियों का मंच बन गया है। आखिर इसका दोषी कौन है?

यह सही है कि संसद जब बहस का मंच है, तो वहां हंगामे भी होंगे, लेकिन कोई भी चीज अधिक हो, तो वह बुरी मानी जाती है। यदि सरकार जनहित के अपने कामों से पीछे हट रही है, तो विपक्ष को उस पर दबाव बनाना ही चाहिए और इसके लिए अगर उसे हंगामा करना पड़े, तो करने से नहीं हिचकना चाहिए, लेकिन हरेक मुद्दे पर हंगामा करना भी उचित नहीं। भारत ही नहीं, किसी भी लोकतंत्र में ऐसा नहीं है कि सरकार ने हमेशा गलत ही फैसला लिया हो। इसलिए, जब वह अच्छा फैसला करे, तो उसकी सराहना भी होनी चाहिए। भारत में ही अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष, मिलकर संसद चलाते हैं, तो क्या आम लोगों को फायदा नहीं होगा? वैसे भी, जब सभी दलों का मूल उद्देश्य जनता की सेवा है, तो उनको जनता की सेवा करनी चाहिए, न कि बेवजह के हंगामे में जनता के हित के कामों को तिलांजलि देने में अपना योगदान देना चाहिए।

राजेश कुमार चौहान, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

हंगामेदार सत्र

अपनी मांग मनवाने के लिए यह जरूरी

संसद क्या है? यह भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय, जो सरकार के काम-काज की जांच करती है, नए कानून बनाती है, नीतियां निर्धारित करने का अधिकार रखती है और दैनिक मुद्दों पर बहस करती है। विचार-विमर्श इसकी मूल संकल्पना का ही हिस्सा है, इसलिए यह अपेक्षा करना कि संसद में सब कुछ बड़ी ही शांति से अंजाम दिया जाएगा और कोई शोर-शराबा नहीं होगा, संसद से कुछ अधिक उम्मीदें पाल लेने जैसा है। अगर हम नहीं चाहते कि संसद का सत्र हंगामेदार हो, तो हमें सबसे पहले यह देखना चाहिए कि आखिर हंगामा होता ही क्यों है? आखिर क्यों बार-बार जनहित के मुद्दों को नजरंदाज करने की कोशिश की जाती है? आखिर क्यों बहुमत की आड़ में अल्पमत वाले दलों की तौहीन की जाती है? जब तक हम इन सवालों के जवाब नहीं ढूंढ़ेंगे, यह नहीं समझ सकेंगे कि संसद में हंगामा होता क्यों है या इसको किस तरह रोका जाना चाहिए?

यह तय है कि अब मतदाताओं का ध्रुवीकरण इस तरह हो चुका है कि संसद भी उससे अछूती नहीं रही। इसीलिए, लोकतंत्र के मंदिर में सभी अपनी-अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश में लगे रहते हैं। चूंकि जिम्मेदारी सत्ता पक्ष पर अधिक होती है और उसकी रुचि शायद ही संसद को जीवंत बनाने में है, इसलिए वह ऐसे हंगामों में मूक रह जाना ही पसंद करता है। कभी-कभी तो वह खुद इसे न्योता देता है, ताकि अपने मन-मुताबिक काम वह परदे के पीछे से, यानी अध्यादेश लाकर कर सके। ऐसे में, सोचना उन नेताओं को चाहिए, जो वास्तव में जनता के हित में काम करना पसंद करते हैं और चाहते हैं कि जनता के हित सर्वोपरि रखे जाएं। इसके लिए उन्हें न सिर्फ अपने दल, बल्कि दूसरी पार्टियों के नेताओं को भी समझाना चाहिए, लेकिन ऐसा हम नहीं देख रहे। तंत्र की सुस्ती के कारण संसद सत्र में हंगामे किए जाते हैं।

अच्छा तो यही होगा कि संसद में सार्थक बहस हो, लेकिन यदि बहस करने की नीयत न हो, तो नीयत पैदा करने के लिए हंगामा जरूरी हो जाता है। कभी भगत सिंह ने भी कहा था कि बहरी सरकार को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। हम यहां धमाके को बम विस्फोट के रूप में न समझें, लेकिन जब तक तंत्र को यह एहसास नहीं होगा कि उसके सामने बैठा शख्स जागृत है, तब तक वह सक्रिय नहीं होगा। देखा जाए, तो सोए हुए तंत्र को जगाने के लिए हंगामे का सहारा लिया जाता है।

दीपक, टिप्पणीकार